BPSC-110

वैश्विक राजनीति

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिति

प्रो. डी. गोपाल (अध्यक्ष) राजनीति विज्ञान संकाय, हेड, गांधी एवं शांति अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली	प्रो. ए. पी. विजापुर राजनीति विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रो. जगपाल सिंह राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
प्रो. अब्दुल नफे (रिटा.) अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन एवं कनाडियन अध्ययन केंद्र, एसआईएस, जेएनयू, नई दिल्ली	प्रो. पी. साहदेवन दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र, एसआईएस, जेएनयू, नई दिल्ली	प्रो. एस. वी. रेड्डी राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
प्रो. आर. एस. यादव (रिटा.) राजनीति विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	प्रो. अनुराग जोशी राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली	

पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. डी. गोपाल, राजनीति विज्ञान संकाय, अध्यक्ष एवं हेड, गांधी एवं शांति अध्ययन केंद्र संपादकः प्रो. अब्दुल नफे, जेएनयू, नई दिल्ली एवं प्रो. दरवेश गोपाल, एसओएसएस, इग्नू, नई दिल्ली

इकाई पुनरीक्षण, स्वरूपण एवं अद्यतीकरण : डॉ. महीप, अकादमिक सहायक, राजनीति विज्ञान संकाय, एसओएसएस, इग्नू

पाठ्यक्रम तैयार करने वाली टीम

खंड	इकाई लेखक
खंड 1 वैश्वीकरणः धारणाएं एवं दृष्टिकोण	
खंड 01 वैश्वीकरण की समझ	डॉ. राज कुमार शर्मा, अकादमिक एसोशिएट, राजनीति विज्ञान संकाय, ईग्नू, नई दिल्ली
खंड 02 राज्य की संप्रभुता एवं अधिकार क्षेत्र	सुश्री सुरुचि अग्रवाल रिसर्च स्कॉलर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
खंड 03 वैश्विक अर्थ व्यवस्था एवं वित्तीय संस्थान (आईएमएफ, विश्व बैंक)	डॉ. अरूंधति शर्मा, विजिटिंग फैकल्टी (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा
खंड 04 वैश्विक व्यापार व्यवस्था (डब्ल्यूटीओर एवं अन्य)	सुश्री रिंकी दहिया एवं सुश्री दीपिका, दिल्ली विश्वविद्यालय
खंड 05 एमएनसी एवं टीएनसी की कार्य–प्रणाली	डॉ. अरूंधति शर्मा, विजिटिंग फैकल्टी (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा
इकाई 06 वैश्वीकरण – सांस्कृतिक एवं तकनीकी आयाम	डॉ. करुण हेमम यादव, रिसर्च एसोशिएट, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
खंड 2 समकालीन वैश्विक मुद्दे	
इकाई 07 पर्यावरण की वैश्विक राजनीति	डॉ. शैलजा गुल्लापल्ली, रिसर्च एसोशिएट, गांधी स्मृति, 5 तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली
खंड 08 सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की चुनौतियां	डॉ. प्रज्ञा पांडेय, रिसर्च एसोशिएट, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली
इकाई 09 गैर–पारंपरिक सुरक्षा के जोखिम	डॉ. अमृता डे. एसआईएस, जेएनयू, नई दिल्ली एवं डॉ. महीप, एसओएसएस, ईग्नू
इकाई 10 शरणार्थी एवं प्रव्रजन	डॉ. सल्विन पॉल, शांति और संघर्ष एवं प्रबंधन विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
इकाई 11 मानवीय सुरक्षा	डॉ. शैलजा गुल्लापल्ली, रिसर्च एसोशिएट, गांधी स्मृति, 5 तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली

खंड 3 समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध	
इकाई 12 वैश्विक प्रतिरोध (वैश्विक सामाजिक आंदोलन एवं गैर सरकारी संगठन)	डॉ. करुण हेमम यादव, रिसर्च एसोशिएट, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
इकाई 13 वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य	डॉ. करुण हेमम यादव, रिसर्च एसोशिएट, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. डी गोपाल, राजनीति विज्ञान संकाय, अध्यक्ष एवं हेड, गांधी एवं शांति अध्ययन केंद्र

संपादक : प्रो. अब्दुल नफे, जेएनयू, नई दिल्ली एवं प्रो. दरवेश गोपाल, एसओएसएस, इग्नू, नई दिल्ली

इकाई पुनरीक्षण, स्वरूपण एवं अद्यतनीकरण : डॉ. महीप, अकादमिक सहायक, राजनीति विज्ञान संकाय, एसओएस, ईग्नू

मुद्रण प्रस्तुति

श्री राजीव गिरधर
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
सामग्री निर्माण एवं वितरण विभाग, इग्नू

श्री हेमन्त परीदा
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
सामग्री निर्माण एवं वितरण
विभाग, इग्नू

सितम्बर, 2021

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2021

ISBN:

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्र मुद्रण) द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली-110068 से अथवा इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा मुद्रित और प्रकाशित ।

लेज़र टाइप सेट- टेसा मीडिया एण्ड कंप्यूटर्स

मुद्रण -

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विषय सूची

		पेज नंबर
खंड 1	**वैश्वीकरण : धारणाएं एवं दृष्टिकोण**	**13**
इकाई 1	वैश्वीकरण की समझ	15
इकाई 2	राज्य की संप्रभुता एवं अधिकार क्षेत्र	29
इकाई 3	वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय संस्थान (आईएमएफ, विश्व बैंक)	44
इकाई 4	वैश्विक व्यापार व्यवस्था (डब्ल्यूटीओ एवं अन्य)	68
इकाई 5	एमएनसी एवं टीएनसी की कार्य–प्रणाली	87
इकाई 6	वैश्वीकरण–सांस्कृतिक एवं तकनीकी आयाम	101
खंड 2	**समकालीन वैश्विक मुद्दे**	**117**
इकाई 7	पर्यावरण की वैश्विक राजनीति	119
इकाई 8	सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की चुनौतियां	139
इकाई 9	गैर–पारंपरिक सुरक्षा के जोखिम	153
इकाई 10	शरणार्थी एवं प्रव्रजन	171
इकाई 11	मानवीय सुरक्षा	194
खंड 3	**वैश्विक–बदलाव : शक्ति एवं शासन**	**207**
इकाई 12	वैश्विक प्रतिरोध (वैश्विक सामाजिक आंदोलन एवं गैर सरकारी संगठन)	209
इकाई 13	वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य	223
संदर्भ ग्रंथ		**238**
ग्रंथ सूची		**241**

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

प्रस्तावना

वैश्विक राजनीति से हमारा क्या तात्पर्य है? यदि आप पाठ्यक्रम की सामग्री को देखें तो आप पाएंगे कि ऐसे मुद्दे व प्रक्रियाएं, ताकत व कारक और संस्थान व तंत्र हैं जो वैश्विक स्तर पर संचालित होते हैं और इन संचालनों के परिणाम राष्ट्र व राज्यों के नीति–निर्धारण को प्रभावित करते हैं और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन को आकार देते हैं। वैश्विक प्रशासन और इन मुद्दों का प्रबंधन वैश्विक स्तर पर राजनीतिक क्रियाकलाप की बात करता है।

सबसे पहला व महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाया जाना आवश्यक है, वह है : वैश्वीकरण क्या है? इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी घटना बहुआयामी और कार्य जटिल है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक अवधारणा या एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया या अभ्यासों का समूह है। जो भी हो, आम राय है कि हम आज वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं। वैश्वीकरण की कुछ मुख्य विशेषताओं की पहचान करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण, वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम पर लिखने वाले लगभग सभी विद्वानों ने वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण एवं उपभोग सहित पूंजी, प्रौद्योगिकी और वस्तुओं व उत्पादन प्रक्रियाओं के वैश्विक प्रवाह में एकीकरण और गहनता के पहलू को उजागर किया है। दूसरा, वे परस्पर संबंधों की बात करते हैं। आधुनिक तकनीक, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार एवं परिवहन में क्रांति ने आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक एवं सुरक्षा के स्तरों पर घनिष्ठ अंतर्संबंधों को आसान बनाया है। तीसरा, समय और स्थान की निकटता कुछ ऐसी है कि दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं का दूर के स्थानों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण बढ़ती अहमियत, विस्तार के पैमाने और सामाजिक संपर्क की तेज गति व अंतर–क्षेत्रीय प्रवाह एवं स्वरूप के प्रभाव को दर्शाता है। जैसे–जैसे समुदाय आपस में जुड़ते गए, विश्वव्यापी सामाजिक मेलजोल बढ़ता गया है और दूर के स्थानों में होने वाली घटनाओं का स्थानीय और तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। चौथा, वैश्वीकरण भौतिक शक्ति की ऐतिहासिक संरचना है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह वैश्विक शक्ति समीकरण, राष्ट्रों और किसी देश के अंदर समुदायों व सामाजिक समूहों के बीच पैदाईशी और गहरी विषमता और पदानुक्रम को दर्शाता है। यह मानव सामाजिक संगठन के पैमाने में बदलाव या परिवर्तन को संदर्भित करता है जो दूर के समुदायों को जोड़ता है और विश्व के प्रमुख क्षेत्रों और महाद्वीपों में शक्ति संबंधों की पहुंच का विस्तार करता है। अंत में, वैश्वीकरण ने राष्ट्र और सांस्कृतिक पहचान के विचार को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण पूरी तरह वैश्विक निकटता और चेतना की गहनता है।

वैश्वीकरण का संचालक क्या है? इसका स्पष्टीकरण है – वैश्विक पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगम, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय निजी बैंक और जी–7 जैसे मंचों के माध्यम से अमेरिका के नेतृत्व वाली विकसित देशों की सरकारें और इससे ऊपर आधुनिक तकनीक। आइए, हम वैश्वीकरण के चालक के रूप में प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों को देखें। व्यापक शब्दों में, प्रौद्योगिकी को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के सामाजिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैश्वीकरण की अधिकांश प्रक्रियाओं के मुख्य सूत्रधार और प्रेरक बल के रूप में तकनीकी विकास को देखा जाता है। हम इन दिनों हम एक नए 'डिजिटल वैश्वीकरण' की भी बात कर रहे

हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने वैश्विक नेटवर्क का रास्ता खोल दिया है। वैश्विक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बोध के लिए आवश्यक सूचना और ज्ञान (विचारधारा भी), रखरखाव व पुनरुत्पादन यथार्थ के रूप में पल्लवित होती है, जो मूल रूप से पूंजीवादी व्यवस्था है। 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' या 'नई अर्थव्यवस्था' शब्द से स्पष्ट है कि इन सारी सूचनाओं, ज्ञान और विचारधारा का पूंजीवाद से गहरा संबंध है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक तकनीक ने वैश्विक पूंजीवाद को गहरा और मजबूत किया है। इंटरनेट और विशेष रूप से ई–कॉमर्स ऐसे शब्द हैं जो मूलतः तकनीकी–वैश्विकता के हालिया दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तकनीकी–वैश्वीकरण को विचारधारा के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है जो तकनीकी आधार पर वैश्विकता को तर्कसंगत बनाता है। यह पूरी प्रक्रिया 1990 के दशक के बाद हुई विश्वव्यापी अंतर्निर्भरता और वैश्विक आदान–प्रदान के नाटकीय निर्माण, विस्तार और तीव्र वृद्धि को प्रस्तुत करती है। वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या इसे सुधारा या उलटा किया जा सकता है? क्या यह मानव संस्था के नियंत्रण के बाहर एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह है? क्या वैश्वीकरण की बहुत आलोचना होती है? इन जटिल प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं हैं? इस बात पर व्यापक सहमति है कि वैश्वीकरण का वर्तमान चरण 1970 के आसपास शुरू हुआ। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो विभिन्न चरणों के माध्यम से विकसित होने के लिए बाध्य है। एक बात जो कुछ निश्चित तौर पर कही जा सकती है वह यह है कि आर्थिक नव–उदारवाद पर आधारित वैश्वीकरण का वर्तमान चरण सतत व स्थायी नहीं है। आंद्रे गौंडर फ्रैंक और अन्य लेखकों ने 1960 में विश्लेषण किया था कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और शक्ति संबंध घरेलू राष्ट्रीय विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी और सांस्कृतिक उद्दीपन में बाधा पहुंचाते हैं। आधुनिक तकनीक और उच्च गतिशील पूंजी पर सवार वैश्वीकरण के वर्तमान नव–उदार चरण ने कई खामियों को बदतर बना दिया है, जिसने वैश्विक पूंजीवाद को प्रभावित किया। वर्ष 1990 में वैश्वीकरण से रोजगार, स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक भागीदारी, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शांति व सुरक्षा सहयोग जैसे अवसर की बात कही गई थी। लेकिन, वैश्विक वास्तविकता इसके विपरीत है और गरीबी व असमानता जैसे कई मानकों पर स्थिति बदतर हुई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद की विजय के साथ शांति और समृद्धि की उम्मीद थी। शीत युद्ध की समाप्ति के कुछ तीन दशक बाद विश्व विशेष रूप से विकसित देश आंतरिक युद्ध और बाहरी हस्तक्षेपों, तानाशाही का उदय, असहिष्णुता और राष्ट्रवाद व स्वदेशी की भावनाओं में वृद्धि के गवाह बन गए। इसके अलावा, वैश्वीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का भारी दोहन किया। आलोचक वैश्वीकरण को वर्तमान नव–उदारवाद की जकड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं।

एक वैश्विक नागरिक समाज और प्रकृति के अधिकार व मानवाधिकारों की रक्षा में प्रतिरोध के नए रूपों का उदय वैकल्पिक वैश्वीकरण की उम्मीद के संकेत हैं। यह तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण में सुधार किया जा सकता है और प्रौद्योगिकी, ज्ञान व अंतर्संबंधों में विकास का उपयोग मानव जाति की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ विद्वान वैश्वीकरण 2.0 की भी बात करते हैं, अर्थात् वैश्वीकरण के वर्तमान पश्चिमोन्मुखी रूप में बदलाव। वैश्वीकरण 2.0 का अर्थ है वैश्वीकरण का 'पश्चिम से शेष तक' विशेष रूप से चीन और एशिया की ओर मुड़ना। एशिया वैश्विक उत्पादन और प्रौद्योगिकी का नया केंद्र बन गया है। महत्वपूर्ण रूप से आधुनिकता के एक नए गैर–पश्चिमी विचार को व्यापक स्वीकृति मिल रही है और शासन के

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में नए मानदंड व मूल्य जल्द ही स्थापित हो सकते हैं।

अंतर–निर्भरता, विशेष रूप से सूचना और संचार के क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय सीमाओं और भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में विचारों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही वैश्वीकरण के वर्तमान युग की वास्तविकताएं हैं। बहस के तहत दो महत्वपूर्ण विषय राज्य की संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान हैं। वैश्वीकरण ने राष्ट्र की संप्रभुता को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह परंपरागत ज्ञान कि राज्य की संप्रभुता अपरिवर्तनीय और अपरिहार्य है, अब सत्य नहीं रहा। निर्णय लेने और अपनी पसंद की नीतियां बनाने में राज्य संप्रभुता वैश्विक संस्थानों के अनुरूप और उसकी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य है। देश सिर्फ एक कानूनी संस्था हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय बनाते हैं और वे अकेले ही वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहलुओं से संबंधित निर्णय ले सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। एक संप्रभु राष्ट्र वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण राष्ट्रों की क्षमताओं को बदल रहा है, फिर भी कामकाजी वैश्वीकरण के लिए राष्ट्र अपरिहार्य है। वैश्वीकरण के कारण मूल्यों, संस्कृतियों और चीजों को करने के तरीके भी बदल रहे हैं। मानव जीवन के हर पहलू में बाजार की शक्तियां प्रवेश कर गई हैं, जो कुछ दशक पहले तक कल्पना से परे था। उदाहरण के लिए, यह संभव है कि भारत के कुछ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभी तक स्कूल और डाकघर उपलब्ध कराने में राष्ट्र सक्षम नहीं हो पा रहा हो, लेकिन कोका कोला और आलू के चिप्स के रूप में वैश्वीकरण की सर्वव्यापी उपस्थिति कोई भी देख सकता है।

इसी तरह, यह तर्क दिया गया था कि वैश्वीकरण से समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता के उदार मानवीय मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध एक महानगरीय वैश्विक नागरिक का जन्म होगा। इससे इनकार नहीं है कि मानवाधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा आदि के समर्थन में एक नई वैश्विक चेतना जगी है। लेकिन, दूसरी तरफ हो सकता है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की हो। विद्वानों का मत है कि समान दौर में देखी जाने वाली सांस्कृतिक जोर और पहचान की राजनीति वैश्वीकरण के सांस्कृतिक वैश्विक 'आक्रमण' की प्रतिक्रिया हो सकती है। संचार और सूचना की आधुनिक तकनीक ने भले ही दुनिया को 'ग्लोबल विलेज' में बदल दिया हो, लेकिन साथ ही इसने 'हम बनाम वे लोग' सिंड्रोम को भी गहरा किया है। बढ़ती असहिष्णुता, राष्ट्रवादी भावनाएं, जातीय एवं धार्मिक समूहों के खिलाफ हिंसा का प्रसार और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से आबादी के विशाल हिस्से को बाहर और हाशिए पर रखने की संस्कृति वैश्वीकरण की देन है। एक स्तर पर बड़ा ही कठिन प्रश्न पूछा जाता है : क्या वैश्वीकरण एक 'अच्छी' या 'बुरी' चीज है? क्या वैश्वीकरण दुनियाभर के लोगों में एकरुपता लाता है या उन्हें अलग बनाता है? उपलब्ध सबूत दोनों बात कहते हैं? समर्थक वैश्वीकरण की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं – यह समानता, स्वतंत्रता, पसंद, जीवन स्तर में वृद्धि और नए आधुनिक मूल्यों को लाता है और स्मार्टफोन जैसी तकनीक को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाता है। विरोधी सावधान करते हैं और तर्क देते हैं कि बाजार की गतिशीलता सामाजिक और राजनीतिक विकल्पों और परिणामों पर हावी है जो राष्ट्र और समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकती है। वैश्वीकरण के अवसर और पुरस्कार लोगों, क्षेत्रों और निगमों के चुनिंदा समूह के बीच शक्ति और धन को केंद्रित करते हुए असमान रूप से फैले हुए हैं। चुनौती यह है कि राष्ट्रों और मानव की बेहतरी के लिए वैश्वीकरण को एक सकारात्मक शक्ति कैसे बनाया जाए।

क्या वैश्वीकरण का विकल्प है? एक बड़ी चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्था को वापस समाज से कैसे जोड़ा जाए। अर्थव्यवस्था को समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए, केवल कुछ लोगों के लिए मुनाफा पैदा करने वाले बाजार के लिए नहीं। पूंजीवाद अलग करता है और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की इस विसंगति को बढ़ाता है। वैश्वीकरण के विकल्प के रूप में यहां एक महत्वपूर्ण विचार रखा गया है : समाज की समग्र भलाई के लिए अर्थव्यवस्था को काम करने के एक साधन के रूप में राष्ट्र का कार्य करना। वैश्विक वित्त और व्यापार संस्थानों के शिकारी ताकतों पर निगाह रखने के लिए व्यापार और निवेश पर एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र और राजकीय नियमों की आवश्यकता है। जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वैश्वीकरण का व्यावहारिक सूत्र आत्म–निर्भरता की ओर वापसी, अर्थव्यवस्था का स्थानीयकरण, स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधन बंदोबस्ती के अनुरूप काम करना है। माना जाता है कि आईटी का उपयोग सकारात्मक रूप से नए समुदायों के निर्माण के लिए किया जा सकता है जो आत्मनिर्भर हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है: वैश्विक शासन में गैर–सरकारी संगठनों को लाकर वैश्विक शासन के दायरे का विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह के साथ एक नया और अधिक न्यायसंगत विश्व आर्थिक और राजनीतिक क्रम और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ एवं विश्व बैंक जैसे वैश्विक शासन तंत्र में उभरती शक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। वैश्वीकरण की कई तरह की प्रतिक्रिया है। कुछ लोग वैश्वीकरण की सामूहिकता को अस्वीकार करते हैं, अन्य लोग इसमें सुधार करने में विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग वैश्वीकरण के वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करते हैं। उस अर्थ में इन सभी वैश्विक बाधाओं में राजनीतिक उद्देश्य है। सहभागी लोकतंत्र बनाने से लेकर स्थानीय प्रशासन ('वैश्विक सोच, स्थानीय कार्य'), स्थानीय समुदायों के लिए स्वायत्तता, लैंगिक न्याय और पृथ्वी के अधिकारों एवं पर्यावरण संरक्षण को मान्यता जैसे कई विचार हैं जिन्हें उत्साहपूर्वक रखा गया। वैश्वीकरण के गहन विश्लेषण करने पर संसाधनों के दोहन, वृहद विकास परियोजनाओं और नदियों एवं अन्य जल संसाधनों का प्रदूषण एवं विध्वंस के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण का पता चलता है।

प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की शक्तियों और इसका विरोध करने वालों, दोनों की मदद की है। विश्व भर में हुए कई लोकप्रिय विरोध आंदोलनों में प्रमुख रूप से अरब स्प्रिंग, इराक पर आक्रमण के खिलाफ युद्ध–विरोधी विरोध प्रदर्शन, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन, वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्ल्यूएसएफ) और विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठकों का विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। वैश्वीकृत दुनिया को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी और आर्थिक संकट जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सीमा से परे इन चुनौतियों को किसी भी देश या अंतर–सरकारी संस्थानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। इनका समाधान सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों और बहुपक्षीय निकाय एवं स्थानीय पहल जैसी शक्तियों के समन्वित प्रयासों से ही किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, बर्ड फ्लू, मानव तस्करी, सूखा एवं भोजन की कमी और अंतर्देशीय जल एवं वायु प्रदूषण आदि जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय शासन और बहुपक्षीय समन्वय के लिए नए मानदंडों और तंत्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वैश्विक शासन और इसकी चुनौतियां सभी बहुपक्षीय संस्थाओं में बहस का एक विषय है।

संस्कृति को परिभाषित करना मुश्किल है। फिर भी, यह संस्कृति ही है जो मनुष्य को प्रकृति और जीवन से जुड़ने में सक्षम बनाती है, विश्वास और संस्कार में अर्थ खोजती है और यह उन परम अर्थों की खोज का हिस्सा है जो मानव को लक्ष्य और प्रेरणा प्रदान करते हैं। संस्कृति हमें खुद को एक समूह या समुदाय के हिस्से के रूप में और एक समूह अन्य समूहों व समुदायों से अलग कैसे है, इसकी व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, संस्कृति एक व्यक्ति को उसके आस–पास की दुनिया को समझने और उसकी व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। 21वीं सदी में सांस्कृतिक प्रसार की मात्रा और सीमा पुराने समय की अपेक्षा बहुत अधिक है। इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल टेलिफोनिक उपकरण के प्रसार के बाद व्यक्तिवाद के आदर्श व मूल्य, उपभोक्तावाद और विभिन्न जातीय एवं धार्मिक बहस पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। आज, सांस्कृतिक प्रथाएं शहर और राष्ट्र जैसे निश्चित इलाकों से निकल कर प्रमुख वैश्विक विषयों के साथ बातचीत में नए अर्थ प्राप्त कर रही हैं। वैश्विक और स्थानीय के इन अंतर्संबंधों ने संस्कृतियों के स्थानीयकरण, ध्रुवीकरण और संकरण की वास्तविकताओं को पेश किया है।

द्वितीय विश्व युद्ध का अंत वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर (एलआईओ) की शुरुआत को चिह्नित किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की विजयी शक्तियां शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने और मौद्रिक स्थिरता, विकासात्मक सहायता और एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाने के लिए आगे आईं। आने वाले समय में वे सैन्य उपयोग वाले परमाणु, मिसाइल और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रसार की जांच करने के लिए अन्य संस्थानों एवं तंत्रों की स्थापना भी करेंगे। 1940 के दशक में आईएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और टैरिफ व व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीटी) जैसे ब्रेटनवुड्स संस्थानों का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सहयोग और सामूहिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। ब्रेटनवुड्स संस्थानों को मौद्रिक और वित्तीय सहयोग के लिए स्थापित किया गया था। आईएमएफ का उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं को मौद्रिक सहायता खासकर संकट के समय में प्रदान करना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए सरकारों को उधार देता है। एक तुलनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) मूर्त रूप नहीं ले सका, इसलिए 1948 में एक अंतरिम संधि के रूप में जीएटीटी को एक उदार व्यापार प्रणाली के मानदंडों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई और इसने जीएटीटी का स्थान ले लिया। डब्ल्यूटीओ एक अंतर–सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच व्यापार करने के लिए शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना है।

1970 के दशक में नव–उदारवाद के युग का उदय हुआ। नव–उदारवाद एक विशिष्ट विचारधारा है। नव–उदारवाद के उदय ने राष्ट्र में विश्वास को ग्रहण लगा दिया। मिल्टन फ्रीडमैन जैसे नव–उदारवादी का पूरा ध्यान मुद्रावादी सिद्धांतों पर केंद्रित था जो राज्य की किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका को कम करता है। बाजार द्वारा स्व–नियमन की अवधारणा नव–उदारवादियों की मान्यता का केंद्र है। नव–उदारवादियों का कहना है कि संसाधनों का कुशल आवंटन एक आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है

और संसाधनों को आवंटित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका बाजार तंत्र है। नव–उदारवाद ने आर्थिक विकास की धारणा को बदल दिया है। आईएमएफ, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने आर्थिक विकास के नव–उदारवादी रास्ते का समर्थन किया है। इन संस्थानों ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों (एसएपी) के माध्यम से विकासशील देशों में अपने वांछित आर्थिक पुनर्गठन को आगे बढ़ाया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने इसे लंबे समय तक शीर्ष पर रखा और आर्थिक सहायता एवं सहयोग, ऋण पुनर्गठन एवं बाजार में पहुंच आदि की नीतियों के माध्यम से इसे विकासशील देशों में बढ़ाया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय निजी बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों के समूह ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और संचालन के माध्यम से नव–उदारवाद को विशेष रूप से विकासशील देशों में बढ़ावा दिया। मोटे तौर पर, इस समन्वित दृष्टिकोण को 'वाशिंगटन सहमति' का नाम दिया गया है।

बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) और ट्रांसनैशनल कॉर्पोरेशन (टीएनसी) रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। पिछले कुछ तीन या चार दशकों में, एमएनसी और टीएनसी दुनिया के कई देशों में वहां के संसाधनों पर कब्जा कर कई देशों से अधिक शक्तिशाली संस्थान बन गए हैं। ये निगम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालने की क्षमता के कारण शक्ति का केंद्र बन गए हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया की 100 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 51 अब वैश्विक निगम हैं, जबकि सिर्फ 49 देश हैं। जापानी टीएनसी मित्सुबिशी आर्थिक आकार में दुनिया में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया से भी बड़ा है।

कोई व्यक्ति कह सकता है कि टीएनसी वैश्वीकरण का वाहन है। विश्व अर्थव्यवस्था में टीएनसी का प्रमुख योगदान अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला या वैश्विक मूल्य श्रृंखला का निर्माण है, जिसके तहत दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर एक ही उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। निर्यात में वृद्धि कर आर्थिक विकास को गति देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और शोध एवं विकास (आरएंडडी) को मेजबान देश में लाना टीएनसी के सकारात्मक पहलुओं में शामिल है। हालांकि आलोचकों को फिर भी संशय है। कहा जाता है कि टीएनसी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं, जरूरत से ज्यादा उपभोग करने की संस्कृति थोपते हैं, कुछ रोजगार पैदा करते हैं और वैश्विक स्तर पर धन और असमानता को बढ़ाते हैं। टीएनसी नए सांस्कृतिक मूल्यों और उपभोग की आदतों के प्रसार के लिए भी जिम्मेदार हैं – जिसे संस्कृति का तथाकथित मैकडॉनलाइजेशन कहा जाता है।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करना वैश्विक राजनीति के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पेरिस जलवायु समझौता, 2015 एक ऐतिहासिक नतीजा है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहमति का उदाहरण है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा पेरिस समझौता छोड़ने के निर्णय के बाद अमेरिका इससे भले बाहर हो गया हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में सहमति बनी और ग्रीनहाउस गैस प्रभावों के कारण बढ़ते तापमान से निपटने में अलग–अलग जिम्मेदारी तय हुई। सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) रासायनिक, जैविक और परमाणु हो सकते हैं। चुनौती यह है कि इन हथियारों को कैसे वापस लिया जाए और उनके प्रसार को रोका जाए। सबसे बड़ी चिंता आतंकवादियों और अन्य विध्वंसकारी तत्वों के हाथों में इन हथियारों के पड़ने का खतरा है। आज, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनने की जरूरत है। पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा का मतलब संप्रभु राज्यों की सुरक्षा थी, लेकिन ड्रग्स,

हथियारों एवं मानव–तस्करी, आतंकवादी नेटवर्क, 'असफल' राज्य आदि जैसे अपरंपरागत स्रोतों से समुदायों और व्यक्तियों की सुरक्षा आज खतरे में है। इन गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों में सबसे बड़ा आतंकवाद है जो राज्य और समाज के एक समान नहीं है। आज प्रवासी और शरणार्थी आंदोलन एक वैश्विक घटना बन गई है। इसकी कई अभिव्यक्तियां हैं और हाल के दिनों में आर्थिक, राजनीतिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक जैसे कई कारणों से और तेज हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन नए और कुछ अनोखे घटनाक्रमों ने मानव सुरक्षा के लिए एक आह्वान किया है। एक नई अवधारणा के तहत मानव सुरक्षा का विचार यह है कि समुदाय और व्यक्तियों को भय और चाह से कैसे सुरक्षित किया जाए। मानव सुरक्षा का एजेंडा एक बार फिर कई अन्य वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों की तरह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु राष्ट्रों के विचार से टकराते हैं।

वर्तमान पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक 'वैश्विक राजनीति' है, इसमें 13 विषय–वस्तु शामिल हैं। पाठ्यक्रम को तीन व्यापक वर्गों में विभाजित किया गया है :

पहला खंड 1 वैश्वीकरण : धारणाएं और परिप्रेक्ष्य : इस खंड में छः विषयों का संकलन है, जिसमें वैश्वीकरण जैसी प्रमुख अवधारणाओं से परिचित कराना, वैश्विक वित्तीय और व्यापार पर दृष्टिकोण स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का संचालन, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक एवं तकनीकी आयाम और वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य संप्रभुता पर बहस शामिल हैं।

खंड 2 समकालीन वैश्विक मुद्दे पांच प्रमुख विषयों की पहचान और चर्चा करता है जो समकालीन वैश्विक राजनीति के केंद्र हैं। इस विषय में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार, प्रवासी और शरणार्थी संकट, आतंकवाद जैसे गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर समकालीन बहस में मानव सुरक्षा का आह्वान शामिल है।

खंड 3 समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध : इस वर्ग में दो इकाई हैं – पहली इकाई में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए असंख्य प्रतिरोध आंदोलनों पर चर्चा और बहस शामिल है। वैश्वीकरण अपरिहार्य हो सकता है या नहीं भी, लेकिन अनुभवजन्य साक्ष्य और सैद्धांतिक रचना जो वैश्वीकरण के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, उनमें काफी शैक्षिक हित हैं। अंतिम इकाई फिर से वैश्वीकरण की अवधारणा और वास्तविकता पर चर्चा करती है।

खंड 1
वैश्वीकरण : धारणाएं और परिप्रेक्ष्य

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 वैश्वीकरण की समझ

संरचना

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 वैश्वीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं

1.2.1 वैश्वीकरण के चरण

1.2.2 वैश्वीकरण के प्रकार

1.2.3 डिजिटल वैश्वीकरण

1.3 वैश्वीकरण के सिद्धांत

1.3.1 अति वैश्विकतावादी

1.3.2 संशयवादी

1.3.3 परिवर्तनवादी

1.4 वैश्वीकरण एवं संप्रभुता

1.5 आलोचना

1.6 सारांश

1.7 संदर्भ ग्रंथ

1.8 अभ्यास प्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई में, आप वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे :

- वैश्वीकरण का अर्थ समझने में,
- इस पर विभिन्न विचारों की चर्चा करने में,
- इसके चरणों और प्रकारों की व्याख्या करने में,
- वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संबंधों की जांच करने में, तथा
- वैश्वीकरण पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने में।

1.1 प्रस्तावना

'वैश्वीकरण' शब्द 1980 के दशक के बाद से मीडिया द्वारा एक लोकप्रिय चर्चा का विषय बन गया है। पहली बार 1960 के दशक में प्रदर्शित होने के बाद, 'वैश्वीकरण' को अक्सर एक प्रक्रिया, एक स्थिति, एक प्रणाली, एक बल और एक युग के रूप में विभिन्न तरीके से वर्णित किया गया है। वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति और प्रौद्योगिकी जैसे

क्षेत्रों को शामिल करती है। यह कोई एकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी कई प्रक्रियाओं का संयोजन है जो कई बार ओवरलैप और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। इसीलिएय वैश्वीकरण को किसी एक विषय में सीमित नहीं किया जा सकता है। वैश्वीकरण से जुड़ी कुछ घटनाएं इस प्रकार हैंः शास्त्रीय उदारवादी या मुक्त बाजार की नीतियां, पश्चिमी (या यहां तक कि अमेरिकी) राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन (पश्चिमीकरण या अमेरिकीकरण), नई सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरनेट क्रांति) का प्रसार और अंत में, वैश्विक एकीकरण की ओर रुझान जिसका अर्थ है कि दुनिया प्रमुख सामाजिक संघर्षों के बिना एक एकीकृत समुदाय बन रही है। यह विभिन्न क्षेत्रों में वैश्वीकरण के व्यापक प्रभाव के कारण है कि इस अवधारणा पर जोरदार बहस हो रही है।

1.2 वैश्वीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं

कई विद्वानों ने इस अवधारणा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्वीकरण को परिभाषित करने की कोशिश की है। एंथनी गिडेंस के अनुसार, वैश्वीकरण का अर्थ 'दुनिया भर के सामाजिक संबंधों में निकटता से है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं से स्थानीय घटनाएँ प्रभावित होती हैं और स्थानीय घटनाओं से दूर वाली घटनाएं प्रभावित होती हैं।' जान आर्ट स्कॉल्ट का तर्क है कि वैश्वीकरण से दुनिया भर के लोगों के बीच 'वैश्विक क्षेत्रीय' संबंधों का विकास होता है क्योंकि 'सीमाओं के परे' संपर्क क्षेत्रीय सीमाओं को अप्रासंगिक बना देते हैं। डेविड हार्वे इसे 'टाइम स्पेस कम्प्रेशन' के रूप में परिभाषित करते हैं। डेविड हेल्ड के अनुसार, 'वैश्वीकरण को एक प्रक्रिया (या प्रक्रियाओं का सेट) के रूप में सोचा जा सकता है जो सामाजिक संबंधों और लेन–देन के स्थानिक संगठन में परिवर्तन का प्रतीक है – जिसका मूल्यांकन उसकी व्यापकता, तीव्रता, वेग और प्रभाव के संदर्भ में किया जाता है – जो अंतर–महाद्वीपीय या अंतर–क्षेत्रीय प्रवाह और गतिविधियों के नेटवर्क, संपर्क, और शक्ति उत्पन्न करता है।' इन परिभाषाओं में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत, संचार और परिवहन में तकनीकी प्रगति के कारण समय और स्थान का संकुचन शामिल है, जिससे दुनिया भर में लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण का मतलब स्थानीयता और राष्ट्रीयता का वैश्विक स्तर पर अधीनता नहीं है, बल्कि यह केवल इन तीन स्तरों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।

वैश्वीकरण से जुड़ी ये पांच विशेषताएं हो सकती हैं। पहला, यह क्षेत्रीयता के परे जाता है, जिसका अर्थ है कि भौगोलिक सीमाएं कम प्रासंगिक हो जाती हैं क्योंकि इंटरनेट और मीडिया दुनिया को काफी करीब ले आती हैं। टीवी और ऑनलाइन समाचारों के माध्यम से एक देश में होने वाली घटनाओं की सूचना तुरंत दूसरे देशों में पहुंच जाती हैं। दूसरी विशेषता अंतर्संबंध है। भौगोलिक सीमाओं के अप्रासंगिक होने के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) ने दुनिया भर के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया। युवा रंगरूट अपने घरों में रहते हुए इंटरनेट के माध्यम से अपने आकाओं के संपर्क में रहते हैं, यह सुविधा वैश्वीकरण

के कारण ही संभव हो सका है। वैश्वीकरण की लोकप्रिय तस्वीर यह है कि यह एक शीर्ष–डाउन प्रक्रिया है जहां एक एकल वैश्विक प्रणाली स्थापित की जा रही है। यहां, वैश्वीकरण को होमोजेनाइजेशन से जोड़ा जाता है क्योंकि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता एकरूपता (शीर्ष से वैश्वीकरण) के पक्ष में नष्ट हो रही है। हालाँकि, स्वदेशीकरण की ओर भी एक बदलाव होता है क्योंकि पश्चिमी उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं (नीचे से वैश्वीकरण) में अवशोषित किया जाता है। तीसरी विशेषता गति है, क्योंकि लोग, सूचना, सामान और सेवाओं की गति तीव्र हो गई हैं जिससे सामाजिक गतिविधियां भी काफी तेज हो गईं हैं। वैश्वीकरण की चौथी विशेषता यह है कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्वीकरण एक समकालीन घटना नहीं है क्योंकि इसकी विशेषताएं मानवता की शुरुआत से ही मौजूद हैं, हालांकि वैश्वीकरण की शुरुआत में वे इससे पूरी तरह से असहमत थे। अन्त में, वैश्वीकरण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक ही समय में राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

वैश्वीकरण की उत्पत्ति के बारे में दो दृष्टिकोण हैं। जॉर्ज रित्जर के अनुसार, भौतिकवादी दृष्टिकोण का मानना है कि सामान्य तौर पर पूंजीवाद या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण के मुख्य कारक हैं। इसके विपरीत, आदर्श दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण सोच और विचारों, सूचना और ज्ञान में बदलाव का परिणाम है। विचार के मामले में, स्थानीय और राष्ट्रीय विचार से यह बदलाव वैश्विक स्तर पर है। हमारा नॉलेज बेस भी वैश्विक हो गया है। हालाँकि, रित्जर का तर्क है कि वैश्वीकरण भौतिक और आदर्श दोनों कारकों का परिणाम है।

1.2.1 वैश्वीकरण के चरण

अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कभी भी वैश्वीकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन यह उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में एक प्रमुख विषय है। आर्थिक विकास के बारे में उनका विवरण इसके अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में समय के साथ बाजारों का एकीकरण है। जैसे–जैसे श्रम विभाजन उत्पादन को विस्तारित करने में सक्षम बनाता है, विशेषज्ञता के लिए खोज व्यापार का विस्तार करती है, और धीरे–धीरे, दुनिया के अलग–अलग हिस्सों से समुदायों को एक साथ लाती है। यह प्रवृत्ति सभ्यता जितनी पुरानी है। वैश्वीकरण की विशेषताएं लंबे समय से मौजूद हैं लेकिन शिक्षाविद अभी भी वैश्वीकरण के शुरुआती बिंदु के बारे में एकमत नहीं हैं। यहाँ, तीन दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है कि वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो चक्रों में हुई है। दूसरा समूह यह भी मानता है कि वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है लेकिन यह चक्रीय नहीं बल्कि रैखिक है। जबकि अंतिम समूह का मानना है कि यह एक नई घटना है।

ए.जी. हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक, ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री में इतिहास में वैश्वीकरण के चार चरणों के बारे में बताया है। पहला पुरातन वैश्वीकरण है जो औद्योगिकीकरण और आधुनिक राष्ट्रों के उदय से पहले हुआ था। इस वैश्वीकरण के प्रमुख कारक आदिवासी नेता, समुद्री और थल व्यापारी थे। उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय और अमेरिकी पकड़ के विस्तार में मदद की। अगला चरण प्रोटो–वैश्वीकरण है, यह अवधि 1600 से 1800 के बीच की है जब राज्य प्रणाली का

उदय हुआ। इस चरण में वैश्वीकरण के कारक व्यापारी और दास व्यापारी थे। 19 वीं शताब्दी से, आधुनिक या पश्चिम–केंद्रित चरण शुरू हुआ, जो औद्योगिकीकरण, शाही और औपनिवेशिक प्रवृत्तियों, विज्ञान समुदाय और सरकारी संगठनों से संबंधित था। 20 वीं सदी में औपनिवेशिकता के पतन के साथ इसके बाद के चरण की शुरुआत बहुराष्ट्रीय निकायों के उद्‌भव से हुई। यह चरण इंटरनेट के माध्यम से राजनीतिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग, आप्रवासियों और नेटवर्किंग का परिणाम है। एम बी स्टीगर ने अपनी पुस्तक, ग्लोबलाइजेशन : ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, वैश्वीकरण के पांच चरणों को पूर्व–ऐतिहासिक अवधि के साथ 10000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच माना है। अगला पूर्व–आधुनिक काल (3500–1500 ईसा पूर्व), प्रारंभिक आधुनिक काल (1500–1750 ईसा पूर्व), आधुनिक काल (1750–1970) और समकालीन प्रणाली (1970 के बाद) है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण की वर्तमान स्थिति को लाने के लिए इन अवधियों में अलग–अलग आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक कारकों में समय के साथ बदलाव आया है।

स्कॉल्ट का मानना है कि हालांकि वैश्वीकरण ऐतिहासिक है लेकिन यह एक रैखिक प्रक्रिया है। उनके अनुसार वैश्वीकरण के तीन चरण हैं। पहला चरण 500 साल पहले शुरू हुआ, दूसरा 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में जबकि आखिरी 1960 में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। उनके अनुसार अंतिम चरण पूर्ण वैश्वीकरण है। यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक संचार, उपग्रहों, ऑप्टिक केबल, टेलीविजन, इंटरनेट, वैश्विक बाजारों के विस्तार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों की अवधि है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करती है बल्कि पारिस्थितिक समस्याओं और उनके समाधान खोजने के प्रयासों की अवधि भी है।

एंथनी गिडेंस का मानना है कि वैश्वीकरण, जैसा कि हम आज अनुभव करते हैं, वह न केवल नया है, बल्कि कई मामलों में क्रांतिकारी और प्रत्यक्ष है। दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है और नई तकनीक भी नए जोखिम भी लाती है। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण बहुआयामी होता है – क्योंकि इसके राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक पहलू होते हैं। उनका यह भी मानना है कि वैश्वीकरण एकल नहीं बल्कि कई प्रक्रियाओं का संयोजन है।

कुछ विशेषज्ञों ने अभी से ही वैश्वीकरण 2.0 के विचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि पुराने पश्चिमी–वर्चस्व वाले वैश्वीकरण 1.0, जिसने एक वैश्विक संस्कृति की सार्वभौमिकता को ग्रहण किया था, बीत चुका है। वैश्वीकरण 2.0 का अर्थ है, विभिन्न पहचान या संस्कृतियों की परस्पर निर्भरता जिसमें गैर–पश्चिमी आधुनिकता विद्यमान हो। आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय और उसके विकास के मॉडल को इस संदर्भ में देखा जाता है क्योंकि यह पश्चिमी विकास मॉडल की तरह लोकतंत्र और मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।

1.2.2 वैश्वीकरण के प्रकार

एंड्र्यु हेवुड के अनुसार, वैश्वीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक।

- आर्थिक वैश्वीकरण – यह इस विचार को दर्शाता है कि आज दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अलग–थलग नहीं है और एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था है

जिसने दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को अपने में समा लिया है। सोवियत संघ के पतन ने वैश्विक आर्थिक एकीकरण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया क्योंकि देशों का अंतिम प्रमुख ब्लॉक वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में सम्मिलित हो गया। आर्थिक वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सरकारों की अपनी अर्थव्यवस्थाओं के प्रबंधन और मुक्त बाजार सिद्धांतों के साथ उनके पुनर्गठन का विरोध करने की क्षमता कम कर दी है।

- सांस्कृतिक वैश्वीकरण – यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के एक हिस्से की सूचना वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करके व्यक्तियों, राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच के सांस्कृतिक अंतर को कम करती हैं। इसे मैकडॉनल्डाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि, संस्कृति भी वैश्वीकरण की ताकतों को बल देने के बजाय कम कर सकती है क्योंकि स्थानीय संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता को वैश्विक व्यापार ब्रांड बनने की आवश्यकता होती है।

- राजनैतिक वैश्वीकरण – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते महत्व से स्पष्ट है जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश संगठन 1945 के बाद के दौर में आए हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण का अंतर–राज्य जोर इसे आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण से अलग करता है क्योंकि वे गैर राज्य और बाजार आधारित कारकों की भूमिका को महत्व देते हैं।

डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण के सैन्य पहलू पर प्रकाश डाला है। उन्होंने सैन्य वैश्वीकरण को ''उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो विश्व व्यवस्था की राजनीतिक इकाइयों के बीच सैन्य संबंधों की बढ़ती विस्तार और तीव्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है, यह दुनिया भर के सैन्य संबंधों और उनके नेटवर्क, साथ ही साथ प्रमुख सैन्य तकनीकी नवाचारों (उपग्रहों से लेकर उपग्रहों तक) के प्रभाव को दर्शाता है, जिसने समय के साथ दुनिया को काफी करीब ला दिया है।" उनका तर्क है कि सैन्य क्षेत्र में वैश्वीकरण भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और महान शक्तियों के साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन प्रणालियों और सुरक्षा संरचनाओं के विकास, सैन्य प्रौद्योगिकियों के विश्वव्यापी हथियारों के साथ विश्व व्यापार के उद्‌भव और सैन्य और सुरक्षा पर अधिकार क्षेत्र के साथ वैश्विक शासन के संस्थागतकरण के मामले में दिखाई देता है। रॉबर्ट किओहेन और जोसेफ नाइ के अनुसार, सैन्य वैश्वीकरण में ''अंतर–निर्भरता के लंबे दूरी के नेटवर्क जिसमें बल, और बल का खतरा है, शामिल होते हैं।''

मैनफ्रेड स्टीगर ने एक और आयाम जोड़ा है – पारिस्थितिक वैश्वीकरण। उनका तर्क है कि संपूर्ण मानवता और पृथ्वी के बीच एक अटूट संबंध है। औद्योगिक क्रांति ने कई पारिस्थितिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें संसाधन और भोजन की कमी, आबादी में वृद्धि, जैव विविधता में कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। ये सभी समस्याएं वैश्विक हैं – समेकित मानवीय गतिविधि का परिणाम – और इसे समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हालांकि, अभी भी पारिस्थितिक मुद्दों की गंभीरता के बारे में बहस चल रही है, और, जबकि प्रगति हुई है, कुछ बहुपक्षीय उपायों को लागू भी किया गया है। वैश्वीकरण के इस चरण ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है, और आने वाली पीढ़ियों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है।

जॉर्ज रिट्जर ने धर्म, विज्ञान और खेल जैसे अन्य आयामों को जोड़ा है। उनका मानना है कि इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे धर्मों का दायरा वैश्विक है और वे अक्सर अपने वैश्विक दायरे का विस्तार करना चाहते हैं। विज्ञान एक वैश्विक उद्यम बन गया है क्योंकि इसका ज्ञान आधार दुनिया के कई हिस्सों से इनपुट के द्वारा बनता है और यह ज्ञान लगभग हर जगह प्रसारित होता है। प्रमुख संगठनों के फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ जैसे खेलों में शामिल होने से खेल भी वैश्विक हो गए हैं।

1.2.3 डिजिटल वैश्वीकरण

वैश्वीकरण किस ओर आगे बढ़ रहा है? हम वैश्वीकरण के एक नए, डिजिटल–संचालित युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे वैश्वीकरण 4.0 के रूप में वर्णित किया जाता है।

वैश्वीकरण के वर्तमान चरण को तीसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से सुगम बनाया गया। 1980 के दशक में इंटरनेट, तेज परिवहन और संचार में तेजी आई। लोग और व्यवसाय जुड़े हुए थेय कंप्यूटर पर एक बटन दबाने से, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में लाखों डॉलर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ई–बैंकिंग और ई–कॉमर्स शुरू हुआ। और तो और, इंटरनेट ने मूल्य श्रृंखलाओं के वैश्विक एकीकरण की सुविधा दी। कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर विनिर्माण और अंतिम उपभोग तक सभी एकीकृत हो गए। वर्ष 2000 में, वैश्विक निर्यात वैश्विक जीडीपी के एक–चौथाई तक पहुंच गया। परिणामस्वरूप व्यापार, आयात और निर्यात का योग, बढ़कर वैश्विक जीडीपी का लगभग आधा हो गया।

वैश्वीकरण की एक और लहर अभी बाकी है। वैश्वीकरण के इस दौर की नई सीमा साइबर दुनिया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था अब ई–कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं, 3 डी प्रिंटिंग के माध्यम से आ गई है। चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स आदि वैश्वीकरण की इस नवीनतम लहर के प्रवर्तक हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति के तकनीकी प्रगति के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित वैश्वीकरण की यह लहर कैसे काम करती है, यह अगले दशकों की कहानी है। वैश्वीकरण का यह दौर कैसे विकसित होता है और कैसे नई प्रौद्योगिकियां अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार को आकार देंगी, राजनीति और संस्कृति अगले कई दशकों तक अध्ययन और विश्लेषण का विषय है।

इस बीच, वैश्वीकरण और उसके परिणामों के खिलाफ प्रतिक्रिया भी वर्तमान चरण का हिस्सा है। वाम उदारवादी राजनीतिक हलकों में, इस बात की स्वीकार्यता है कि वैश्वीकरण ने सभी को लाभ नहीं दिया हैय बल्कि इसने बहुतों को पीछे छोड़ दिया है। बढ़ती असमानता, सामाजिक अस्थिरता, सांस्कृतिक तनाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि वैश्वीकरण की विरासत हैं। वैश्वीकरण के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ने का एक वैश्विक मूड है। कुछ इसे पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहते हैं। रूढ़िवादी जो अब तक वैश्वीकरण की बात किया करते थे, वे भी इससे दूर हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में आव्रजन के खिलाफ प्रतिक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का आव्रजन राष्ट्रीय संस्कृतियों के लिए खतरा है। आर्थिक संरक्षणवादी और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति अमेरिका और अन्य जगहों पर मजबूत हुई हैय यह कहा जाता है कि अन्य देशों ने अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में उदारीकृत व्यापार और आव्रजन प्रणाली का

अनुचित लाभ उठाया है। परिणामस्वरूप, वाम–उदारवादी और रूढ़िवादी राजनीतिक क्षेत्रों में वैश्वीकरण के खिलाफ भावनाओं का प्रसार होता हैय और कुछ इससे दूर होते जा रहे हैं।

आदर्श राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण पश्चिम देशों में गिरावट पर है। वैश्वीकरण के लिए समर्थन की आवाज अब चीन, भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से आ रही हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है। इसका समाधान आर्थिक वैश्वीकरण को अस्वीकार नहीं करना हैय बल्कि इसे समावेशी और न्यायसंगत बनाना है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः

i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और इसके उद्भव के क्या कारण हैं?

2) डिजीटल वैश्वीकरण की अवधारणा की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 वैश्वीकरण के सिद्धांत

गहन विवादास्पद विषय होने के नाते, इस बात पर तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं कि वैश्वीकरण हो रहा है या नहीं। एक अर्थ है कि प्रो–बनाम वैश्वीकरण विरोधी बहस पूंजीवाद और समाजवाद के बीच पुरानी और परिचित बहस के एक संशोधन से अधिक नहीं है क्योंकि वैश्वीकरण में एक मुक्त बाजार उन्मुखीकरण है। हालाँकि, यह बहस इस मायने में नई है कि यह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि बाजार संरचनाओं के लिए कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं और चुनाव नवउदारवादी वैश्वीकरण और विनियमित वैश्वीकरण के बीच है।

1.3.1 अति वैश्विकतावादी

वैश्वीकरण सिद्धांत की पहली लहर को अति वैश्विकतावादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि यह इंगित करता है कि पूंजी की गतिशीलता, एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कम महत्वपूर्ण हो गई है। इसके समर्थकों में फ्रांसिस फुकुयामा (ऐंड ऑफ हिस्ट्री), थॉमस फ्रीडमैन (वर्ल्ड इज फ्लैट) और केनिची ओहमाए (ऐंड ऑफ द नेशन स्टेट) शामिल हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय लेनदेन के कम्प्यूटरीकरण जैसे तकनीकी परिवर्तनों के कारण धन की आवाजाही पर राजनीतिक प्रतिबंध कम हो गए हैं। उनका मानना है

कि वैश्वीकरण का मौजूदा चरण राष्ट्र–राज्यों के लिए अहितकर है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को ''राष्ट्र से परे'' करता है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय सीमाएं अप्रासंगिक हो जाएंगी और राष्ट्रीय सरकारों को यूरोपीय संघ जैसे सुप्रानेशनल संगठनों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संपर्क की सुविधा प्रदान करनी होगी। इसका अर्थ है कि आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को दिशा दिखाती है। राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति, प्रभाव और यहां तक कि संप्रभुता भी खो देंगे क्योंकि उन्हें गतिशील पूंजी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को तैयार करना होगा। सामाजिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के लिए ऐसा करना परेशानी भरा होगा क्योंकि यहां व्यावसायिक हितों को सबसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इससे राष्ट्रीय संस्कृति में भी गिरावट आती है क्योंकि दुनिया भर के लोग वैश्विक संस्कृति का उपभोग करते हैं। राजनीतिक रूप से, राष्ट्र राज्य संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को महत्व देने लगते हैं। अति वैश्विकतावादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक ताकतें अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के मामले में राष्ट्रों से आगे सोचती हैं।

1.3.2 संशयवादी

दूसरी लहर संशयवादियों से जुड़ी है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण में कुछ खास नया नहीं है और इसके प्रभाव के बारे में राजनीतिक कारणों से बढ़ा–चढ़ा कर बताया जा रहा है। इसके मुख्य समर्थकों में पॉल हर्स्ट और ग्राहम थॉम्पसन (ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन : द इंटरनेशनल इकोनॉमी ऐंड पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस) शामिल हैं। 19 वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र की ओर संकेत किया था। संशयवादी वैश्वीकरण को एक क्रांतिकारी तकनीकी और आर्थिक बल के रूप में नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धांतकारों और राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए एक वैचारिक उपकरण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र राज्यों की निरंतर भूमिका देखी गई है। कोर (विकसित दुनिया) के मामलों में, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में राज्य शक्तिशाली बने हुए हैं। राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ है क्योंकि पुराने राष्ट्र वैश्वीकरण से तनाव में हैं। संशयवादियों का यह भी तर्क है कि राष्ट्रीय पहचान का एक इतिहास है, जो लोकप्रिय कल्पना है और वैश्विक संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। आर्थिक रूप से, संशयवादियों का कहना है कि वैश्वीकरण का विस्तार हर जगह समान रूप से नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, उप–सहारा अफ्रीका के देश पूर्वी एशिया और यूरोप के राष्ट्रों की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बहुत कम एकीकृत हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण अफ्रीका के कई हिस्सों में गरीबी और असमानता बढ़ी है। सांस्कृतिक रूप से, संशयवादियों का कहना है कि विभिन्न राष्ट्र वैश्वीकरण के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में फैल गए होंगे, लेकिन स्थानीय व्यंजनों के अनुसार इसके व्यंजनों में सामग्री का उपयोग करना पड़ता है (उदाहरण के लिए, वे जापान में झींगा बर्गर बनाते हैं और अपने यहूदी ग्राहकों के लिए कोषेर बर्गर)। संशयवादियों के विश्लेषण से ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं जो सत्ता, असमानता, संघर्ष और राष्ट्र राज्यों के महत्व जैसे पहलुओं पर बल देते हैं।

1.3.3 परिवर्तनवादी

तीसरी लहर में परिवर्तनवादी शामिल हैं जिनकी स्थिति अति वैश्विकतावादी और संशयवादियों के बीच की है क्योंकि वे वैश्वीकरण की एक जटिल तस्वीर को चित्रित करते हैं जहां ऐसा हो रहा है लेकिन जैसा कि अति वैश्विकवादियों द्वारा तर्क दिया जाता है, इसके कारण सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। डेविड हेल्ड और एंथोनी मैकग्रे (द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन्स रीडर : एन इंट्रोडक्शन टू द ग्लोबलाइजेशन डिबेट), एंथोनी गिडेंस (रनअवे वर्ल्ड) और उलरिच बेक (रिस्क सोसाइटी) इस तर्क के मुख्य समर्थक हैं। उनके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और संचार में वृद्धि, पर्यावरण, ड्रग्स और अपराध जैसी समस्याओं के कारण राष्ट्रीय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियां अन्य संस्थाओं के साथ संप्रभुता साझा करने के लिए परिवर्तित हो जाती हैं। वैश्विक असमानता का स्तर दो ध्रुवीय से बदलकर तीन स्तरीय हो जाता है जिसमें एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों का एक मध्य समूह भी शामिल है जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकृत होने के लिए महत्वपूर्ण विकास देखा है। राजनीतिक रूप से, राष्ट्र राज्य अधिक स्वशासित नहीं है, स्वायत्त इकाई और प्राधिकरण अधिक विसरित है। राज्यों को कार्यकर्ताओं के रूप में देखा जाता है और उनकी शक्ति को कम नहीं किया जाता है, बल्कि उनका पुनर्गठन किया जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय संस्कृति जैसे फिल्म, भोजन, धर्म और फैशन अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी से इतने प्रभावित होते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति अब वैश्विक संस्कृति से अलग नहीं है।

नीचे दी गई तालिका वैश्वीकरण के तीन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का सारांश प्रस्तुत करती है। तीन दृष्टिकोणों को थोड़ा संशोधित किया गया है और उन्हें वैश्विकतावादी, परंपरावादी और परिवर्तनवादी कहा जाता है।

Perspectives	Key Assumptions
Globalist	• There is a fully developed global economy that has supplanted previous forms of the international economy. • The global economy is driven by uncontrollable market forces, which have led to unprecedented cross-national networks of interdependency and integration. • National borders have dissolved and therefore the category of a national economy is now redundant. • All economic agents have to conform to the criteria for being internationally competitive. • The position is advocated by economic neo-liberals but condemned by neo-Marxists
Traditionalist	• The international economy has not progressed to the stage of a global economy to the extent claimed by the globalists. • Separate national economies remain a salient category. • It is still possible to organize cooperation between national authorities to challenge market forces and manage domestic economies and govern the international economy. • The preservation of entitlements to welfare benefits, for instance, can still be secured at the national level.
Transformationalist	• New forms of intense interdependence and integration are sweeping the international economic system. • These place added constraints on the conduct of national economic policy making. • They also make the formulation of international public policy to govern and manage the system very difficult. • This position sees the present era as another step in a long evolutionary process in which closed local and national economies disintegrate into more mixed, interdependent and integrated 'cosmopolitan' societies.

Source: Thompson (2000, p. 90-91).

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोट :

i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) वैश्वीकरण के अति वैश्विकवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 वैश्वीकरण एवं संप्रभुता

सामान्य अर्थों में, संप्रभुता का अर्थ है एक राज्य का अपने क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार और लोगों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता और एक संप्रभु राज्य के रूप में अन्य संप्रभु राज्यों द्वारा इसकी मान्यता होना। इस परिभाषा में संप्रभुता के आंतरिक और बाहरी पहलू शामिल हैं। आंतरिक रूप से, राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च प्राधिकरण है जो अपने नागरिकों से कानून और आज्ञाओं का पालन कराता है। इसके पास अपराधियों को दंडित करने और बल के उपयोग पर एकाधिकार होने का भी अधिकार है। क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी रूप से एक राज्य की संप्रभुता को अन्य राज्यों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी राज्य के घरेलू मामलों में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो।

हालांकि, वैश्वीकरण की ताकतें कई राज्यों में संप्रभुता के क्षरण, गैर–राज्य कार्यकर्ताओं की बढ़ती भूमिका, उप–राष्ट्रीय समूहों और विभिन्न प्रकार के ट्रांस–नेशनल फ्लो से राज्यों की संप्रभुता पर दबाव डालती हैं। प्रसिद्ध जापानी व्यापार रणनीतिकार, केनिची ओहमाए का तर्क है कि राष्ट्र राज्य अभी भी वैश्विक राजनीति में एक खिलाड़ी हो सकता है लेकिन उसने अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता खो दी है। इससे क्षेत्र–राज्य का उदय हुआ है जिसमें क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के आधार पर सीमाओं के पार स्थित समुदाय शामिल हैं। उनका तर्क है कि यह वह बाजार है जो निर्धारित करता है कि नागरिकता से किसका संबंध है और किसको बाहर रखा गया है। वह कहते हैं कि बाजार के बिना नागरिकता की धारणा का कोई मतलब नहीं है। वह आगे तर्क देते हैं कि आधुनिक राष्ट्र–राज्य – अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के अवयव – का पतन शुरू हो गया है। गिडेंस का कहना है कि राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता खो दी है और राजनेताओं ने घटनाओं को प्रभावित करने की अपनी क्षमता खो दी है। उनके अनुसार राष्ट्र–राज्य का युग समाप्त हो चुका है। डेविड हेल्ड ने पाँच ऐसे क्षेत्र बताए हैं जहाँ वैश्वीकरण ने संप्रभुता को कम किया है – विषम शक्तियां और शक्ति ब्लॉक, वैश्विक अर्थव्यवस्था, घरेलू नीति का अंत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और सामूहिक सुरक्षा संधि

संगठन (सीएसटीओ) जैसे सुरक्षा संगठनों के उदय के साथ, विदेशी और सुरक्षा विकल्पों पर स्पष्ट प्रतिबंध हैं जिन्हें सदस्य राज्यों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था में, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय संगठन राज्य सरकारों पर कुछ दबाव डालते हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक चाहते हैं कि राज्य सरकारें उनसे सहायता मांगने से पहले अपने राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का पुनर्गठन करें। इस तरह के विकास ने राष्ट्र राज्यों के लिए अपनी घरेलू नीतियों को तैयार करने के लिए जगह कम कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, सामूहिक निर्णय लेने के नए रूप हैं जिनमें राज्यों, अंतर–सरकारी संगठनों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूहों को संप्रभुता को प्रतिबंधित करना शामिल है। अंत में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों की मान्यता राष्ट्रीय सरकारों के साथ संघर्ष में आ सकती है जो मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सकते हैं। संप्रभुता का दूसरा आयाम राज्य के आंतरिक वर्चस्व से संबंधित है, जो इसके सभी व्यक्तियों और समूहों पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण के कारण संप्रभुता की यह अद्वैतवादी या ऑस्टिन समझ पहले से ही तनाव में आ रही है। बहुलवादियों का तर्क है कि राज्य की आंतरिक संप्रभुता एक ओर राज्य और नागरिक समाज और दूसरी ओर संघ की इकाइयों के अधिकारों के बीच अधिक विसरित होगी। मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी तकनीकी प्रगति नागरिकों को सक्रिय कर रही है और राज्य से नागरिक समाज समूहों को शक्ति स्थानांतरित कर रही है।

यह कहा जा सकता है कि ये घटनाक्रम राज्य से जुड़े संस्थानों की भूमिका को पुनर्निर्मित करते हैं। इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण संप्रभुता को मिटा नहीं रहा बल्कि इसे बदल रहा है। संप्रभुता मुख्य रूप से राज्य में रहती है, लेकिन यह विश्व बैंक, आईएमएफ और यूरोपीय संघ आदि जैसे राज्यों से परे कारकों में भी स्थित हो सकती है। वैश्वीकरण अपनी सीमाओं को बनाए रखने और संप्रभुता का इस्तेमाल करने के लिए राज्य की क्षमता को कम करके आंकता हैय अभी तक निकट भविष्य में, क्षेत्रीय राज्य वास्तविकता बने रहेंगे। पॉल हर्स्ट का तर्क है कि उच्च स्तर के व्यापार और निवेश के साथ एक विश्व अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं है और इस तरह की व्यवस्था में राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के संचालन में विशेष रूप से भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, जब तक राष्ट्र–राज्य महत्वपूर्ण रहेंगे, तब तक संप्रभुता प्रासंगिक रहेगी, हालांकि इसकी भूमिका और अभिव्यक्ति बदल गई है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोट :

i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) वैश्वीकरण संप्रभुता को कैसे कम करता है?

.....

.....

.....

1.5 आलोचना

वैश्वीकरण से असमानता के उलझे हुए रूप सामने आते हैं जो विजेताओं और हारने वालों को जन्म देते हैं। 2018 में, ऑक्सफैम ने बताया कि दुनिया के 26 सबसे धनी व्यक्तियों के पास दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी के बराबर या लगभग 3.8 बिलियन लोगों की संयुक्त संपत्ति थी। गरीबों पर भी अधिक कर लगाया जाता है : प्रत्येक अमेरिकी डॉलर के कर राजस्व में केवल 4 सेंट अमीर लोगों के करों से आता है। वैश्वीकरण के खेल में, यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक रूप से उन्नत देश विजेता रहे हैं जबकि हारने वाले विकासशील और सबसे कम विकसित देश हैं जहां मजदूरी कम है, विनियमन कमजोर है और उत्पादन घरेलू बाजारों के बजाय विश्व की ओर उन्मुख है। यह उत्तर–दक्षिण को विभाजित करता है क्योंकि औद्योगिक विकास उत्तरी गोलार्ध (विकसित देशों) में केंद्रित है जबकि नुकसान और गरीबी मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। 2007–08 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, एक नया शब्द लोकप्रिय हो गया है – अवैश्वीकरण। वाल्डेन बेलो को समर्पित, व्यापार में गिरावट और देशों के बीच निवेश के रूप में वैश्वीकरण के रोलबैक के संकेत। वह आगे तर्क देते हैं कि यह विश्व अर्थव्यवस्था से पीछे हटने का एक पर्याय नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक परिवर्तन है जो कि अंतरराष्ट्रीय निगमों की जरूरतों के आसपास लोगों, राष्ट्रों और समुदायों की जरूरतों के लिए एकीकृत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों और ब्रेक्सिट का सुझाव है कि राष्ट्रीयता के परिणामस्वरूप पतन की ओर रुझान बढ़ रहा है। आर्थिक तंगी से लेकर कई कारणों से दुनिया भर में राष्ट्रवादी भावना का उदय होता है, बड़े पैमाने पर आव्रजन के साथ मुद्दों को बदलने की इच्छा होती है।

वैश्वीकरण बढ़े हुए जोखिम और अनिश्चितता के साथ जुड़ा हुआ है जैसा कि एंड्रयू हेवुड ने उजागर किया था। उलरिच बेक ने एक जोखिम वाले समाज की बात की है जहां परंपरा, समुदाय और स्थापित संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं जिससे व्यक्तिवाद बढ़ जाता है। जैसा कि सभी निश्चित बिंदुओं को कम करके आंका गया है, यह लोगों की बुनियादी पहचान और मूल्यों पर सवाल उठाता है। वैश्वीकरण को पर्यावरणीय संकट के उत्प्रेरक के रूप में भी देखा जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, लाभ और उपभोक्तावाद पर जोर देकर, वैश्वीकरण पर्यावरण पर दबाव बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य कार्रवाई हासिल करना मुश्किल हो गया है क्योंकि इसमें बलिदान शामिल हैं और यह आर्थिक विकास को भी बाधित कर सकता है।

वैश्वीकरण का लोकतंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय निगमों के हाथों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को केंद्रित करके, लोकतंत्र उन्हें लोकतांत्रिक नियंत्रण से बचने का अधिकार देता है। उनके पास उत्पादन और पूंजी को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करने की क्षमता है और परिणामस्वरूप, विकासशील देश अपने निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। चिंता का दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक वैश्वीकरण की तुलना में आर्थिक वैश्वीकरण की गति तेज है। आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय सीमाओं पर कोई ध्यान नहीं देती है लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर राजनीति जारी है, जबकि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे आर्थिक प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वैश्विक पूंजीवाद को ध्यान में रखने के लिए बहुत कमजोर हैं।

नोम चॉम्स्की ने अमेरिका और उसके आर्थिक हितों पर हावी नव–उदारवादी वैश्वीकरण की आलोचना की है। चॉम्स्की का कहना है कि इस तरह के वैश्वीकरण को मोटे तौर पर अमेरिका द्वारा प्रायोजित किया जाता है और इसे अपने हितों के साथ–साथ अमेरिकी निगमों और अमेरिका के भीतर ''अभिजात्य'' के लिए तैयार किया जाता है, न कि आम जनता के लिए। वह ये तर्क भी देते हैं कि नव–उदारवादी वैश्वीकरण से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र को कमजोर करता है क्योंकि यह अंतर–कॉरपोरेट और राज्य के नेताओं की शक्ति को बढ़ाता है जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं, और बहुत कुछ, लोगों के प्रति जवाबदेह होने के बिना जवाबदेह नहीं है। चॉम्स्की के अनुसार, "निजीकरण प्रभावी लोकतांत्रिक विकल्प के क्षेत्र को कम करता है"।

1.6 सारांश

वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें राजनीति, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह एकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रियाओं का संयोजन है जो कई बार ओवरलैप और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। इसीलिए, वैश्वीकरण को किसी एक विषय में बांधा नहीं जा सकता है। वैश्वीकरण कैसे होता है, इसके बारे में दो दृष्टिकोण हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण का मानना है कि वैश्वीकरण के पीछे सामान्य या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूंजीवाद मुख्य कारक है। इसके विपरीत, आदर्श दृष्टिकोण कहता है कि वैश्वीकरण सोच और विचारों, सूचना और ज्ञान में बदलाव का परिणाम है। कुछ विशेषज्ञों ने पहले से ही वैश्वीकरण 2.0 के विचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि पुराने पश्चिमी–वर्चस्व वाले वैश्वीकरण 1.0, जिसने एक वैश्विक संस्कृति की सार्वभौमिकता को ग्रहण किया था, बीत चुका है। वैश्वीकरण 2.0 का अर्थ है, गैर–पश्चिमी आधुनिकता के नए रूपों की विशेषता कई पहचान या संस्कृतियों की परस्पर निर्भरता। एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय और उसके विकास के मॉडल को इस संदर्भ में देखा जाता है क्योंकि यह पश्चिमी विकास मॉडल की तरह लोकतंत्र और मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। वैश्वीकरण के बल कई तरह से राज्यों की संप्रभुता पर दबाव बढ़ाते हैं जैसे संप्रभुता का क्षरण, गैर–राज्य कारकों की बढ़ती भूमिका, उप–राष्ट्रीय समूहों और विभिन्न प्रकार के ट्रांस–नेशनल प्रवाह। डेविड हेल्ड ने पाँच ऐसे क्षेत्र दिए हैं जहाँ वैश्वीकरण ने संप्रभुता – विषम शक्तियों और शक्ति ब्लॉकों, विश्व अर्थव्यवस्था, घरेलू नीति का अंत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर किया है। यह कहा जा सकता है कि ये घटनाक्रम राज्य से जुड़े संस्थानों की भूमिका को पुनर्निर्मित करते हैं। इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण संप्रभुता को नहीं मिटा रहा है बल्कि इसे बदल रहा है। संप्रभुता मुख्य रूप से राज्य में रहती है, लेकिन यह राज्य से परे कारकों में भी स्थित हो सकती है, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ और यूरोपीय संघ आदि।

1.7 संदर्भ ग्रंथ

बेक, अलरिच, (1992), *रिस्क सोसाइटी : टूवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी*, लन्दन : सेज।

गिड्डेन्स, ऐन्थोनी (1999), *रनवे वर्ल्ड : हाउ ग्लोबलाइजेशन इज रिशेपिंग आवर लाइव्स*, लन्दन : प्रोफाइल्स बुक्स लिमिटेड।

हेल्ड, डेविड एण्ड मैकग्रेव, ऐन्थॉनी (2003), *दि ग्लोबल ट्रांस्फॉर्मेशन रीडर : ऐन इंट्रोडक्शन टू दि ग्लोबलाइजेशन डिबेट,* कैम्ब्रिज : पॉलिटी प्रेस।

हेवूड, ऐन्थॉनी, (2007), *पॉलिटिक्स,* हैम्शायर : पालग्रेव मैकमिलन।

हर्स्ट, पी. एण्ड थॉम्पसन, जी., (1999), *ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन,* कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज पॉलिटी प्रेस।

रिटजर, जॉर्ज, (2010), *ग्लोबलाइजेशन : ए बेसिक टेक्स्ट,* सूसेक्स : विली ब्लैकवेल।

शॉल्टे, जे.ए., (2005), *ग्लोबलाइजेशन : ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन,* न्यू यॉर्क : पालग्रेव मैकमिलन।

स्टीगेर, मैनफ्रेड बी., (2003), *ग्लोबलाइजेशन – ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,* ऑक्सफोर्ड : ओयूपी।

शिएउरमैन, विलियम, (2014), *ग्लोबलाइजेशन.* इन स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी रिट्राइव्ड फ्रॉम http://www.bibme.org/citation-guide/apa/website/

विनोद, एम. जे. एण्ड देशपाण्डे, एम., (2013), *कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थियरी,* न्यू देल्ही : पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।

थॉम्पसन, जी., (2000), इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? इन डी. हेल्ड (ऐडिटेड), *एग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड? कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स,* लंदन, न्यू यॉर्क : रूटलेज : दि ओपन यूनिवर्सिटी।

1.8 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- डेविड हेल्ड, एंथनी गिडेंस और जे ए स्कोल्ट द्वारा दी गई वैश्वीकरण की परिभाषाएं।
- वैश्वीकरण की घटना पर भौतिकवादी और आदर्श दृष्टिकोण।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- फ्रांसिस फुकुयामा, थॉमस फ्रीडमैन और केनिची ओहमा के विचार।
- अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण।
- राष्ट्रीय संस्कृति का ह्रास।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- संप्रभुता का क्षरण, गैर–राज्य अभिनेताओं की बढ़ती भूमिका, उप–राष्ट्रीय समूह और विभिन्न प्रकार के ट्रांस–नेशनल प्रवाह।
- डेविड हेल्ड के पाँच क्षेत्र जहाँ वैश्वीकरण संप्रभुता को कम करता है।

इकाई 2 राज्य की संप्रभुता एवं अधिकार क्षेत्र

संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 संप्रभुता

2.3 अधिकार क्षेत्र

2.4 वैश्वीकरण

2.5 वैश्वीकरण के प्रभाव

2.5.1 वैश्वीकरण और आर्थिक संप्रभुता

2.5.2 वैश्वीकरण और राजनीतिक संप्रभुता

2.5.3 वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संप्रभुता

2.6 वैश्वीकृत दुनिया में अधिकार क्षेत्र

2.7 सारांश

2.8 संदर्भ ग्रंथ

2.9 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई में, आप राज्य की संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अंत में, आप समझने में सक्षम होंगेः

- राज्य की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र का अर्थ
- राज्य की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव
- राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संप्रभुता पर वैश्वीकरण का प्रभाव
- वैश्वीकृत दुनिया में राज्य के अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण।

2.1 प्रस्तावना

एक राष्ट्र–राज्य को आमतौर पर एक 'देश', 'राष्ट्र' या 'राज्य' भी कहा जाता है, लेकिन, यह संप्रभु राज्य (एक क्षेत्र पर एक राजनीतिक इकाई) का एक विशिष्ट रूप है जिसे एक राष्ट्र (सांस्कृतिक इकाई) द्वारा निर्देशित किया जाता है, और जो अपने नागरिकों से अपनी वैधता प्राप्त करता है। कॉम्पैक्ट ओईडी राष्ट्र–राज्य को एक संप्रभु राज्य के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें से अधिकांश नागरिक या विषय उन कारकों से भी एकजुट होते हैं जो एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, जैसे भाषा, सामान्य वंश, संस्कृति और इतिहास। राष्ट्र–राज्य का अर्थ है कि एक राज्य और एक राष्ट्र मेल खाता है।

यह भी कहा जाता है कि राष्ट्र एकमात्र वैध राजनीतिक समुदाय है, और इसलिए यह राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च रूप है। वास्तव में, राष्ट्रीय संप्रभुता को आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून की आधारशिला माना जाता है, जिससे प्रत्येक राष्ट्र को आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है और उसके भाग्य का निर्धारण होता है।

आधुनिक राज्य का एक क्षेत्रीय आधार होता है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने अधिकार का प्रयोग करता है जिसे अन्य राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। आधुनिक राष्ट्र–राज्य राष्ट्रवाद की विचारधारा के तहत राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने की कोशिश करता है।

संप्रभुता की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। हालांकि, आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के साथ–साथ कानूनी और राजनीतिक सार्वभौमिकता के कारण, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत संप्रभुता की पारंपरिक समझ के मामले में राज्य शक्ति के अभ्यास के लिए जिम्मेदार है। समकालीन राजनीतिक दर्शन में संप्रभुता की अवधारणा में नए सिरे से रुचि पैदा करनी चाहिए क्योंकि वैश्वीकरण के आसपास के हालिया विकास और पर्यवेक्षी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के उदय के पर्यवेक्षकों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जीन बोडिन और थॉमस हॉब्स जैसे राज्य के प्रारंभिक आधुनिक सिद्धांतकारों द्वारा विस्तृत इसके पारंपरिक अर्थ में, संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सीमा के भीतर स्थित सर्वोच्च और अविभाज्य शक्ति।

2.2 संप्रभुता

संप्रभुता का अर्थ है अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर राज्य की पूर्ण और असीमित शक्ति; यहाँ, यह सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण और अघोषित राजनीतिक शक्ति दोनों है। आंतरिक संप्रभुता के रूप में यह राज्य के भीतर शक्ति के वितरण को संदर्भित करता है, और सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता और राजनीतिक प्रणाली के भीतर इसके स्थान के बारे में सवालों की ओर जाता है। बाहरी संप्रभुता के रूप में, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर राज्य की भूमिका से संबंधित है और एक स्वतंत्र और स्वायत्त अभिनेता के रूप में काम करने में सक्षम है या नहीं। आधुनिक राज्यों की संप्रभुता कानून की सर्वोच्चता में परिलक्षित होती हैय परिवार, क्लब, ट्रेड यूनियन, निजी व्यवसाय इत्यादि जैसे अन्य नियम उन नियमों को स्थापित कर सकते हैं जो कमांड प्राधिकरण, लेकिन केवल कानून द्वारा परिभाषित सीमाओं के भीतर ही संप्रभु राज्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

संप्रभुता का सिद्धांत राज्यों की आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को रेखांकित करता है। इस प्रणाली की उत्पत्ति अक्सर विद्वानों और लोकप्रिय साहित्य में पीस ऑफ वेस्टफेलिया में पता लगाया जाता है – 1648 में हस्ताक्षरित संधियों की एक श्रृंखला, जिसने यूरोप के धार्मिक युद्धों को समाप्त कर दिया। 1648 की संधि वेस्टफेलियन संप्रभुता के रूप में ज्ञात एक सिद्धांत के संयोग से हुई, जिसका सीधा अर्थ था कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य की अपने क्षेत्र और घरेलू मामलों पर और सभी बाहरी शक्ति के बहिष्कार की संप्रभुता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी अन्य देश के घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून में समान हैं। वेस्टफेलियन संप्रभुता क्षेत्रीय रूप से सीमांकित राज्यों के भीतर सर्वोच्च कानूनी

और राजनीतिक प्राधिकरण स्थित है, जिसने राष्ट्र के साथ खातिरदारी का दावा किया था।

राज्यों की व्यवस्था संप्रभुता के केंद्रीय मॉडल के आस–पास की जाती है। एक संप्रभु राज्य में क्षेत्रीय अखंडता होती है और इसका कानून बनाने का अधिकार निर्विवाद होता है। इसका अपने क्षेत्र के भीतर अपने आंतरिक मामलों में पूरा नियंत्रण होता है और अपने लोगों पर शासन करने का कानूनी अधिकार होता है। एक संप्रभु राज्य किसी दूसरे राष्ट्र–राज्य का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं करेगा।

आंतरिक संप्रभुता राज्य के आंतरिक मामलों और इसके भीतर सर्वोच्च शक्ति के स्थान को संदर्भित करती है। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य की जगह और इसलिए अन्य राज्यों के संबंध में इसकी संप्रभु स्वतंत्रता से है। कुछ समय के लिए सरकार की आंतरिक संरचना में कोई संप्रभु आंकड़े नहीं होने पर भी एक राज्य को अपने लोगों और क्षेत्रों पर संप्रभु माना जा सकता है। इस प्रकार बाहरी संप्रभुता का सम्मान किया जा सकता है, भले ही आंतरिक संप्रभुता विवाद या भ्रम का विषय हो। इसके अलावा, जबकि आंतरिक संप्रभुता के बारे में सवाल उठता है, लोकतांत्रिक सरकारों के वर्तमान युग में, यह प्रतीत होता है कि यह पुराना हो चुका है और बाहरी संप्रभुता का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल, आधुनिक राजनीति में कुछ गहरे विभाजनों में ऐसी संप्रभुता के विवादित दावे शामिल हैं।

2.3 अधिकार क्षेत्र

किसी राज्य का अधिकार क्षेत्र राज्य की संप्रभुता से उत्पन्न होता है, और यह इसकी एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय विशेषता है। यह व्यक्तियों, संपत्ति और घटनाओं पर एक राज्य का अधिकार है जो मुख्य रूप से इसके क्षेत्रों (भूमि, राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र, आंतरिक और क्षेत्रीय जल) के भीतर हैं। इस प्राधिकरण में कानून बनाना, कानून के नियमों को लागू करना और स्थगित करने की शक्तियां शामिल हैं। राज्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित शक्तियां राज्य के अधिकार क्षेत्र के प्रकार और रूपों के बारे में सवाल उठाती हैं। राज्य का क्षेत्राधिकार उन व्यक्तियों और संस्थाओं से अधिक हो सकता है, जिनके पास राष्ट्रीय संबंध हैं, जैसे व्यावसायिक फर्म। यह विस्तार उन आधारों या सिद्धांतों के बारे में प्रश्न उठाता है, जिन पर राज्य अपनी सीमा के भीतर और उसके बाहर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा कर सकता है। एक राज्य अपने क्षेत्र के भीतर बाध्यकारी कानून बनाने का हकदार है। कई क्षेत्रों में इसकी विधायी विशिष्टता है। यह वर्चस्व संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अंगों को सौंपा गया है।

हालांकि कानून मुख्य रूप से एक राज्य क्षेत्र के भीतर लागू करने योग्य है, यह कुछ परिस्थितियों में अपने क्षेत्र से आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, उदाहरण के लिए, स्वीकार करता है कि एक राज्य अपने क्षेत्र के बाहर रहनेवाले करदाता पर कर लगा सकता है यदि राज्य और करदाता के बीच एक वास्तविक संबंध है, चाहे वह राष्ट्रीयता या अधिवास हो। आम तौर पर, चूंकि राज्य एक–दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और क्षेत्रीय संप्रभुता रखते हैं, इसलिए उन्हें विदेशी क्षेत्र में अपने कार्यों को करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य के पास किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। इस अर्थ में, एक राज्य मेजबान राज्य की

सहमति के बिना विदेशी क्षेत्र पर अपने कानूनों को लागू नहीं कर सकता हैय अन्यथा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।

जब उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्ण संप्रभुता का वेस्टफेलियन सिद्धांत प्रचलित था, तो आमतौर पर यह माना जाता था कि संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संप्रभु राज्यों की स्वायत्त निर्णायक शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उनकी गतिविधियों से कमजोर नहीं हो सकतीं और न ही कमजोर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून अनिवार्य रूप से संघर्षों को टालने और राष्ट्रीय न्यायालयों की स्वतंत्रता की पुष्टि करने से संबंधित था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक, कानूनी तौर पर, राज्यों को लगभग पूर्ण अर्थों में संप्रभु माना जाता था, जो अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और संसाधनों पर सर्वोच्च अधिकार रखते थे।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोट :

i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) राज्य की संप्रभुता के बाहरी आयाम की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 वैश्वीकरण

इकाई 1 में आपको वैश्वीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताई गईं हैं। एक सामान्य स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि 1945 के बाद वैश्वीकरण में तेजी आई, आर्थिक निर्भरता की वृद्धि से यह परिलक्षित होता है क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में समाहित होती गई। इसके अलावा, इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ जैसे बहुराष्ट्रीय निकायों का उद्‌भव हुआ। राज्य तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी संप्रभुता का प्रयोग करता है : राजनीतिक और कानूनी संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। सभी वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हैं।

जैसा कि इकाई 1 में विस्तार से समझाया गया है, वैश्वीकरण के साथ, संप्रभु राज्यों की सीमाएं इलेक्ट्रॉनिक और अन्य प्रवाह जैसे कि धन हस्तांतरण, उपग्रह संचार, कंप्यूटर डेटा प्रवाह, पूंजी प्रवाह और व्यापारिक व्यापार के प्रभाव से अधिक भेद्य हो जाती हैं। समकालीन राज्य वैश्विक कंपनियों, वैश्विक उत्पादन और व्यापार, लोगों की आवाजाही – प्रवासी शरणार्थी आदि जैसे घटनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता के कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधारों को भी लचीला कर दिया है। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार की मदद से

महिलाओं के आंदोलनों से लेकर पर्यावरणविदों तक कई तरह के समूहों के बीच सुपर–क्षेत्रीय तालमेल और एकजुटता बनाई गई है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वैश्वीकरण राज्य और उसकी संप्रभुता के विचार को चुनौती देता है। जॉन नाइस्बिट के अनुसार, ''अंतर्राष्ट्रीय समाज एक औद्योगिक समाज से एक सूचना समाज में परिवर्तित हो रहा है। वस्तुतः सभी राष्ट्र–राज्य वैश्विक परिवर्तनों और वैश्विक प्रवाह के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं। माल, पूंजी, लोग, ज्ञान, संचार और हथियार, साथ ही साथ अपराध, प्रदूषक, फैशन और विश्वास, तेजी से क्षेत्रीय सीमाओं के पार चले जाते हैं। यह पूरी तरह से संगठित वैश्विक क्रम बन जाता है ...''

2.5 वैश्वीकरण के प्रभाव

वैश्वीकरण के युग में आधुनिक राज्यों की संप्रभुता बहुत ही चर्चित मुद्दा है। राष्ट्रीय संप्रभुता का महत्व बहुत कम हो जाता है क्योंकि राज्य अब अपनी सीमाओं पर संसाधनों, लोगों और सांस्कृतिक प्रभावों के आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। समय की आवश्यकता आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की बढ़ती निर्भरता की मांग करती है। राज्य का अब अपने संप्रभु क्षेत्रों में लोगों, विचारों और संसाधनों के पारगमन आंदोलनों पर नियंत्रण नहीं है।

वैश्वीकरण ने संप्रभुता को तीन तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी बाजारों के उदय ने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र–राज्यों की क्षमता में हस्तक्षेप किया है। दूसरा, राष्ट्र–राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्राधिकार सौंपा है। तीसरा, इन संगठनों द्वारा बनाए गए एक 'नए' अंतरराष्ट्रीय कानून ने अपनी घरेलू नीतियों के संप्रभु राज्यों द्वारा स्वतंत्र आचरण को सीमित कर रखा है।

2.5.1 वैश्वीकरण एवं आर्थिक संप्रभुता

आर्थिक वैश्वीकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अछूता नहीं है। सभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं कमोबेश एक इंटरलॉक्ड वैश्विक अर्थव्यवस्था में निवेशित हैं। बाजारों, वित्त, वस्तुओं और सेवाओं की परस्पर संबद्धता, और अंतरराष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्मित लिंक आर्थिक वैश्वीकरण के परिणाम हैं। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदियों से चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में व्यापार और वैश्विक निवेश का विस्तार और गति कई गुना बढ़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण आर्थिक वैश्वीकरण में तेजी आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार धन, निर्णयों और विचारों की आवाजाही को आसान बना दिया है। आमतौर पर यह दावा किया जाता है कि एक बटन के दबाने से दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पैसा स्थानांतरित करने की बाजार की क्षमता ने नीति–निर्धारण के नियमों को बदल दिया है, आर्थिक फैसलों को बाजार की ताकतों की दया पर पहले से कहीं अधिक निर्भर कर दिया है। कार्की के अनुसार, आर्थिक वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया हैय मानव नवाचार और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार और वित्तीय प्रवाह के माध्यम से तेजी से एकीकृत हो रही हैं। अब, दुनिया के किसी भी हिस्से में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव, दुनिया भर के देशों में महसूस किया जाता है। वित्तीय बाजारों, प्रौद्योगिकी और कुछ विनिर्माण और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ राष्ट्र राज्यों की कार्रवाई की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसके अलावा, विश्व बैंक और

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के उद्भव के कारण नई बाधाएं और अनिवार्यताएं शामिल हो जाती हैं।

इस युग में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के वर्चस्व ने विकासशील देशों को विशेष रूप से अपनी संप्रभुता को खत्म करने के लिए प्रेरित किया है। आज के समय में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किसी भी स्थानीय दुर्बलताओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो किसी भी तरह से वैश्विक बाजार या व्यापार परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। इन संस्थानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समान मानक बनाने के लिए सदस्य–राज्यों को घरेलू कानूनों को लागू करने का अधिकार दिया गया है।

पहले वर्णित की गई संप्रभुता की समझ राज्य के भीतर अनिवार्य रूप से निहित है। संप्रभुता राज्य को अपने नागरिकों पर शासन करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नीतियों को लागू करती हैं और राज्यों को ऐसे कानून लागू करने के लिए बाध्य करती हैं जो नीति के साथ सामंजस्य रखते हों, भले ही राज्य इसे लागू करने की स्थिति में हो या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने राज्य की संप्रभुता को अपनी महत्वाकांक्षा के साथ अतिक्रमित कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ सदस्य–राज्यों द्वारा उन नीतियों का कार्यान्वयन कराके उनकी संप्रभुता का अतिक्रमण करती हैं जो राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। विकासशील देशों के पास इन नीतियों को घरेलू कानूनों के रूप में संशोधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है क्योंकि ऐसा नहीं करने से सदस्य देशों के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होगा। वित्तीय सहायता या अनुदान, बाजार तक पहुंच आदि के लिए एक संप्रभु राज्य इतना निर्भर हो जाता है, कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों या धनी और विकसित देशों द्वारा निर्धारित शर्तो को स्वीकार कर लेता है। इसलिए, देशों के बीच असमानता, उनके विकास के स्तर और सामाजिक वातावरण को समझना बेहद आवश्यक है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन कारकों पर सफलतापूर्वक कार्य कर लेती हैं, तो यह विश्व अर्थव्यवस्था को केवल विकसित देशों के बजाय समग्र रूप से विकसित करने और प्रगति करने में सक्षम बनाएगा।

एक राष्ट्र–राज्य की संप्रभु शक्तियाँ केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए नहीं होती हैं। फिर भी, एक संप्रभु राज्य के शासन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उन नीतियों को तैयार करना और लागू करना है जो अपने मानव विकास सूचकांक को उच्चतर स्तर पर ले जाते हैं और अपने नागरिकों को एक सुरक्षित सामाजिक जीवन प्रदान करते हैं। ये आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य होते हैं।

हालाँकि, पिछले तीस वर्षों में, आर्थिक वैश्वीकरण के बढ़ते दायरे और सीमा के कारण कई विकसित लोकतंत्रों में कल्याणकारी राज्य की भावना पर हमला हुआ है। उदाहरण के लिए, मुद्राओं के अवमूल्यन, पूंजी बाजारों के उच्च नियमन, घरेलू उद्योगों को बर्बादी से बचाने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण, व्यापक सार्वजनिक खर्च के कारण व्यापक सार्वजनिक घाटा। फिर भी जैसे–जैसे बाजार अधिक एकीकृत होते गए हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दबाव ने राज्यों को राजकोषीय बाजार खोलने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर उच्च श्रम लागत के निहितार्थ को देखते हुए जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अधिक स्पष्ट रूप से, आर्थिक वैश्वीकरण, अपने सबसे हालिया रूप में, तीन मुख्य तरीकों से अपनी स्वयं की नीति परिणामों को निर्धारित करने के लिए व्यापार और आर्थिक एकीकरणय वित्तीय बाजारय और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से राज्यों की क्षमता को सीमित कर रहा है। व्यापार बाजारों के साथ–साथ पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती गतिशीलता के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण, राज्यों को श्रम लागत में कटौती करने, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कम करने, अपने घरेलू बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कराधान को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और कल्याणकारी राज्य के आकार और दायरे को कम किया जा रहा है।

2.5.2 वैश्वीकरण एवं राजनीतिक संप्रभुता

वैश्वीकरण राष्ट्रीय सरकारों की अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने और प्रभावित करने या अपने राजनीतिक कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति में कमी का कारण बना है। एक मजबूत संकेत है कि वैश्वीकरण का प्रभाव अधिक महसूस किया जाता है क्योंकि हर जगह काफी हद तक राजनीति अब अनिवार्य रूप से अर्थशास्त्र द्वारा संचालित होती है। ऐसा नहीं है कि सरकारें अब अपने राज्यों को चलाने में असमर्थ हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिक ताकतों के दबाव के अनुकूल बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संरचनाओं के संस्थागतकरण ने राजनीतिक वैश्वीकरण को जन्म दिया है। 19 वीं शताब्दी की शुरुआत से, यूरोपीय अंतर्राज्यीय प्रणाली एक तेजी से सघन अंतर्राष्ट्रीय मानदंड आदेश और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संरचनाओं का एक सेट विकसित कर रही है जो सभी प्रकार की बातचीत को नियंत्रित करती है। इस घटना को 'वैश्विक शासन' की संज्ञा दी गई है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सरकार या प्राधिकरण नहीं हैय फिर भी वैश्विक महत्व और चिंताओं के मामलों को एक प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया जाना है। वैश्विक शासन यहाँ विशिष्ट और सामान्य दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास को संदर्भित करता है जो विभिन्न मुद्दों का प्रबंधन करते हैं। सामान्य और वैश्विक संगठनों में जो सबसे अधिक उभरा था, वह राष्ट्र संघ था जिसे अब संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अरब लीग आदि मौजूद हैं। इन संगठनों का प्रभाव संस्था–निर्माण की एक प्रक्रिया का निर्माण करना है, जहाँ संगठन सदस्य राज्यों के शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। यह राजनीतिक वैश्वीकरण की प्रवृत्ति है। गैर–सदस्य राज्य खुद को इस सहयोग के बाहर पाते हैं और उन्हें गैर–अनुरूपतावादी के रूप में माना जाता है। भविष्य में बहुत से राज्य इन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य करेंगे।

अभी से ही इसका प्रभाव मानव अधिकारों के क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण, एक राज्य अब अपने नागरिकों और विदेशियों को अपने अनुसार चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसे विभिन्न मानवाधिकार संधियों में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

2.5.3 वैश्वीकरण एवं सांस्कृतिक संप्रभुता

संस्कृति व्यवहार और सोच के पैटर्न को संदर्भित करती है जो सामाजिक समूहों में रहने वाले लोग सीखते हैं, बनाते हैं, और साझा करते हैं। संस्कृति एक मानव समूह

को दूसरों से अलग करती है। लोगों की संस्कृति में उनके विश्वास, व्यवहार के नियम, भाषा, अनुष्ठान, कला, प्रौद्योगिकी, पोशाक की शैली, उत्पादन और खाना पकाने के तरीके, धर्म और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था शामिल हैं। संस्कृति में कई अलग–अलग विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, यह प्रतीकों पर आधारित होती है – विचारों, वस्तुओं, भावनाओं या व्यवहारों को संदर्भित करने और समझने के तरीकेय और भाषा का उपयोग करके प्रतीकों के साथ संवाद करने की क्षमता। दूसरा, संस्कृति साझी होती है। एक समाज में रहने वाले लोग संस्कृति के माध्यम से सामान्य व्यवहार और सोचने के तरीके साझा करते हैं। तीसरा, संस्कृति सीखी जाती है। जबकि लोग जैविक रूप से कई भौतिक लक्षणों और व्यवहार की प्रवृत्ति को विरासत में देते हैं, संस्कृति सामाजिक रूप से विरासत में मिलती है। एक व्यक्ति को समाज के अन्य लोगों से संस्कृति सीखनी चाहिए। चौथा, संस्कृति लचीली होती है। लोग लचीले ढंग से संस्कृति का उपयोग करते हैं और अपने आस–पास की दुनिया में बदलाव के लिए इसे समायोजित करते हैं। चूंकि कोई भी मानव समाज पूर्ण अलगाव में मौजूद नहीं है, विभिन्न समाज भी संस्कृति का आदान–प्रदान करते हैं और साझा करते हैं। संस्कृतियां अलगाव में नहीं रहतीं और न ही बढ़ती हैं। उनमें संवाद होता है और आपस में आदान–प्रदान करते हैं। वास्तव में, सभी समाजों में अन्य समाजों के साथ कुछ बातचीत होती है, जिज्ञासावस भी और क्योंकि अत्यधिक आत्मनिर्भर समाजों को कभी–कभी अपने पड़ोसियों से सहायता की आवश्यकता होती है। आर्थिक गतिविधियां अक्सर विविध संस्कृतियों को बातचीत और आदान–प्रदान के लिए मजबूर करती हैं। आज, उदाहरण के लिए, दुनिया भर में कई लोग इसी तरह की तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे कार, टेलीफोन और टीवी। कंप्यूटर नेटवर्क, वाणिज्यिक व्यापार और संचार प्रौद्योगिकियों ने एक वैश्विक संस्कृति बनाई है। इसलिए, केवल एक ही समाज के भीतर साझा की जाने वाली संस्कृति को खोजना मुश्किल हो गया है।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान सभी समाजों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। विभिन्न समाज विचार, लोगों, विनिर्मित वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों का आदान–प्रदान करते हैं। इस तरह के आदान–प्रदान की अपनी कमियां भी हैं, जैसे कि किसी अन्य समाज की संस्कृति के पहलुओं और मूल्यों की शुरूआत अन्य संस्कृति के लोगों के एकजुट जीवन को बाधित कर सकती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण सांस्कृतिक घटनाओं के दो सेटों के प्रसार से संबंधित है : (i) दुनिया के बड़े हिस्से में वैयक्तिकृत मूल्यों के प्रसार, मूल रूप से पश्चिमी मूल के। ये मूल्य सामाजिक अनुबंधों में व्यक्त किए जाते हैं जो व्यक्तिगत अधिकारों और पहचानों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पराराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मान्यता देते हैं। (ii) मूल रूप से पश्चिमी संस्थागत प्रथाओं, नौकरशाही संगठन और तर्कसंगतता को अपनाना, कानून के शासन में विश्वास, आर्थिक दक्षता और राजनीतिक लोकतंत्र के मूल्यों का वैश्वीकरण के तहत अधिक प्रसार रहा है। हालांकि, यह कहा जाना चाहिए, इन मूल्यों और संस्थानों को यूरोपीय ज्ञानोदय के बाद से प्रचारित किया गया है। तर्कसंगतता, व्यक्तिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, समानता, और दक्षता के पश्चिमी मूल्यों के बढ़ते प्रभाव और स्वीकृति वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है – एक प्रवृत्ति जिसने वैश्वीकरण के संदर्भ में गति और प्रकृति दोनों को बढ़ाया है। नई सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा समय और स्थान संपीड़न बस मूल्यों और प्रथाओं के वैश्वीकरण की दिशा में लंबी प्रवृत्ति का एक विस्तार और त्वरण है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोटः

i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संप्रभुता की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2.6 वैश्विक दुनिया में अधिकार क्षेत्र

वैश्वीकरण समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बदल रहा है और राज्य की संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र के विचार को प्रभावित करता है। संप्रभु राज्य के कानून की कीमत पर दो प्रमुख विकास उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले, सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेष शासनों को राज्य द्वारा पहले से ही एकाधिकार वाले क्षेत्रों, जैसे मानवाधिकार, सामाजिक और पर्यावरणीय कानूनों, आर्थिक विकास नीतियों और व्यापार और निवेश में परिवर्तित किया गया है। दूसरा, अंतर सरकारी संगठनों, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा तेजी से लागू किए गए नियम प्रमुख हैं। अनिवार्य रूप से, इन विकासों के साथ जुड़ा हुआ, राज्य संप्रभुता के वेस्टफेलियन विचार का आधार है। एक वैश्वीकृत दुनिया में, राज्य संप्रभुता के निरपेक्ष, अपरिवर्तनीय, दलाली न होने का विचार टिकाऊ नहीं है।

राज्य के कानूनी तंत्र पर वैश्वीकरण का वास्तविक प्रभाव संप्रभुता के कमजोर पड़ने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। वैश्विक ताकतों के द्वारा राज्य के कानून को बदलने की संभावना हैय हालांकि, राज्य के कानून में विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने और पारभासी कारकों के लिए एक उल्लेखनीय क्षमता है। इन अंतःक्रियाओं के परिणाम से संभवतः कानून की अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन होगा। वैश्वीकरण की गति और गहराई से कोई फर्क नहीं पड़ता, संप्रभु राज्यों को वैश्वीकरण को संभव बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न मानदंडों और प्रथाओं का कार्यान्वयन अभी भी संप्रभु राज्यों के हाथों में है। अंतर–सरकारी संगठनों (आईजीओ), अंतरराष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों (आईएनजीओ), अंतरराष्ट्रीय निगमों (टीएनसी) के रूप में अंतरराष्ट्रीय कारकों के साथ–साथ, राज्य एजेंसियों, निजी संस्थान और प्रवासियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ, अब वैश्विक मंच पर पर्याप्त भूमिका निभाते हैं। एनजीओ जैसे गैर–राज्य कारकों के प्रतिस्पर्धी हितों द्वारा राज्य संप्रभुता का एक हद तक 'समझौता' किया गया है। वास्तव में, कई क्षेत्रों में फैले नए संस्थानों द्वारा श्रम, माल, सेवाओं और पूंजी के आंदोलन को रोकते हुए कई राष्ट्रीय नियमों को बदल दिया गया है।

वर्तमान में, राज्य अपनी सीमाओं के भीतर भी, मानवता के व्यापक हितों से संबंधित मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकता है। व्यक्तियों और जातीय समूहों को अंतरराष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मानवीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था और प्रवर्तनीय तंत्र के विस्तार में देखा जाता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वैश्विक शासन की 'उभरती प्रणाली' के लिए एक केंद्रीय ढांचे में विकसित हुआ है। यह प्रणाली आईजीओ की स्थापना और परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन, महासागर उपयोग और विश्व व्यापार प्रणाली के कामकाज जैसे विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए मानक तंत्र की आपूर्ति करती है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोट :

i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) वैश्वीकरण ने राज्य के क्षेत्राधिकार को कैसे प्रभावित किया है?

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 सारांश

वैश्वीकरण ने एक बहुआयामी दुनिया को जन्म दिया है जो अद्वितीय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से गुजरती है जो वैश्विक स्तर पर परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। संप्रभुता, राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर नियम बनाने का अधिकार, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की पहचान है। वैश्वीकरण, जो विचारों, धन, वस्तुओं और लोगों के सीमा पार हस्तांतरण की बढ़ती मात्रा, गति और गुंजाइश को दर्शाता है, इसके राजनीतिक आयामों के अलावा जैसे मानवीय अंतर्राष्ट्रीय कानून में वृद्धि, प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था आदि, संप्रभु राज्यों के अनन्य क्षेत्रीय अधिकार को चुनौती देता है।

संप्रभुता की अवधारणा, एक बार निर्विरोध होने के बाद, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के भीतर विवाद की एक प्रमुख बाधा बन गई है। पहले संप्रभुता की अवधारणा का एक कालातीत या सार्वभौमिक अर्थ था, लेकिन हाल ही में बढ़ते वैश्वीकरण के बीच शोधकर्ताओं और विश्लेषकों ने कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में इस अवधारणा के बदलते अर्थों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया है। यह स्पष्ट है कि संप्रभु राज्य भविष्य में राजनीतिक प्राधिकरण और समुदाय का मुख्य और विशेष ध्यान केंद्रित रहने की संभावना नहीं है।

इसे प्राधिकरण और समुदाय के नए परिदृश्यों द्वारा चुनौती दी जाती है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच विभाजन से परे हैं, और जल्द ही राजनीतिक जीवन के नए रूपों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो इस अंतर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह सीमाओं के पार वैश्वीकरण के उभरते रुझानों के कारण है।

संप्रभुता, जो पहले राष्ट्र–राज्य में केंद्रित थी, को बाजार अर्थव्यवस्था और राज्यों की राजनीतिक रूप से परिभाषित सीमाओं से परे विस्तार करने की इसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति द्वारा चुनौती दी जाती है। परिणामस्वरूप, राज्य संप्रभुता की विशिष्टताएं कमजोर हो गई हैं, जैसे कानून बनाने और लागू करने की क्षमता, क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित करने और बचाव करने की शक्ति, साथ ही साथ आर्थिक प्रदर्शन को आकार देने और निर्देशित करने की क्षमता। जबकि संप्रभु राज्य निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसके अधिकांश पूर्व शक्तियों को शासन के अन्य स्तरों के साथ–साथ केंद्र सरकार के संस्थानों के तहत कर दिया गया है।

अधिकांश देशों के संक्रमण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली के बारे में सामान्य रूप से एक नई संप्रभुता के बारे में बात करना उचित है। हम यह मान सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रक्रियाओं को ताकत मिलती है, तो यह निश्चित रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिसमें विचारधारा और सामाजिक मनोविज्ञान में परिवर्तन शामिल हैं। एक अजीबोगरीब व्यवस्था उभरती है जहां अलग–अलग देशों, राष्ट्रों, क्षेत्रों और अन्य विषयों (निगमों, विभिन्न संघों, वैश्विक मीडिया होल्डिंग कंपनियों आदि) की समस्याएं एक उलझन में उलझ जाती हैं। अलग–अलग स्थानीय कार्यक्रम और संघर्ष बड़ी संख्या में देशों को प्रभावित करते हैं। उसी समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में फैसले का पूरी दुनिया में प्रभाव होता है। सामान्य तौर पर व्यापक अर्थों में वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बुनियादी क्षेत्रों में पारस्परिक अंतर्संबंधों की तीव्रता और जटिलता से पहचान की जाती है।

नियमों और विनियमों को ऐतिहासिक रूप से गतिविधियों या उन जगहों पर संदर्भित किया जाता है जहाँ गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। एक युग में जब गतिविधियां तेजी से सीमा पार करती हैं जो अलग–अलग नियामक वातावरण और नियामकों को अलग करती हैं, इन गतिविधियों पर कुछ नियंत्रण बनाए रखने के लिए, नियम बनाने वाले प्राधिकरण के स्थानिक संगठन को सवाल में लाया जाता है। क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त–क्षेत्रीयता या विवादों के मुद्दे अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान के रूप में सामने आते हैं और नियम जो उन पर शासन करते हैं। रिक्त स्थान और नियम बनाने वाले प्राधिकरण साझा करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वे साझा किए जाते हैं और इस तरह के साझाकरण के परिणाम संस्थागत तंत्र पर निर्भर करते हैं जो कि न्यायिक विवादों से निपटने के लिए स्थापित होते हैं।

वर्तमान इकाई में समझाया गया है कि वैश्वीकरण के प्रभाव और इसकी प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, पूर्ण और अविभाज्य संप्रभुता का विचार, जैसा कि होब्स और बोडिन द्वारा निर्धारित किया गया था, अब लागू नहीं होता है। राज्य की संप्रभुता की पुरानी अवधारणाएँ बदल गईं हैं क्योंकि संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र व्यापक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही हैं। राजनीतिक सिद्धांत के लिए समस्या यह है कि यह शक्ति के नए रूपों और शक्ति के पुराने रूपों की संशोधित प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विश्लेषणात्मक उपकरणों को विकसित करने में विफल रहा है।

अलग तरह से कहें, तो न केवल संप्रभुता का शास्त्रीय सिद्धांत अपर्याप्त है, जो अब अविभाज्य, निरपेक्ष और सर्वोच्च नहीं है, लेकिन इसमें शक्ति के उत्पादक रूपों को सिद्ध करने के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल का भी अभाव है। इस प्रकार, जैसा कि फौकॉल्ट का कहना है कि लेविएथन के मॉडल को छोड़ दिया जाना चाहिए और शक्ति का अध्ययन न्यायिक संप्रभुता और राज्य की संस्था द्वारा उल्लिखित क्षेत्र के बाहर किया जाना चाहिए।

वैश्वीकरण का जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है – चाहे वह राजनीति हो, आर्थिक या तकनीकी हो। संचार में तेजी से प्रगति ने एक वैश्विक समाज का निर्माण किया है। राष्ट्र राज्यों के बीच आर्थिक निर्भरता राज्यों की संप्रभुता पर नए अवरोध डाल रही है। आंतरिक मामलों को प्रभावित करने और यहां तक कि अन्य देशों की आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता को बदलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के साथ आर्थिक लीवरेज (प्रतिबंध) का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। एक ऐसी दुनिया में, जो सभी स्तरों पर जुड़ी हुई है, अपने आप को संप्रभु क्षेत्राधिकार के नाम पर आंतरिक राजनीति तक सीमित करके एक देश को अलग कर सकती है, जैसा कि हम उत्तर कोरिया के मामले में देख सकते हैं। हालांकि विकसित लोकतंत्रों को वैश्वीकरण से अधिकतम लाभ होता है, यह विकासशील देश हैं जो वैश्वीकरण के रूप में चुनौतियों का सामना करते हैं और लोक कल्याण के लक्ष्यों सहित उनकी घरेलू आर्थिक विकास रणनीतियों, हमेशा सिंक्रनाइजेशन में नहीं हो सकती। यह विश्व बैंक जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं और बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें विकासशील देश और अमीर और विकसित देशों में रहने वाली गरीब और कम आय वाली आबादी शामिल हैं। नतीजतन, कुछ अधिक उत्साही आलोचकों का तर्क है कि वैश्वीकरण ने कमजोर, कम–विकसित देशों के नव–उपनिवेशण का नेतृत्व किया है – एक घटना जो कई अफ्रीकी देशों में देखी जा सकती है। तेजी से आगे बढ़ रहे वैश्वीकृत दुनिया के साथ नहीं रह पाए इन देशों की आर्थिक विफलताओं ने राज्य की विफलता और घरेलू अव्यवस्था को जन्म दिया है।

वैश्वीकरण ने राज्यों के बीच स्वैच्छिक समझौते का विकास किया है। यह इस तथ्य के कारण है कि राष्ट्र–राज्य इसे दुनिया में एक लाभ के रूप में पहचानते हैं जहां वे रहते हैं। यह आम खतरे या खतरे की स्थिति में उनकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। यह आधुनिक अधिनायकवाद है। यूएनओ, नाटो, ईयू, आईएमएफ आदि जैसे अति–राष्ट्रीय संगठन अंतर–सरकारी राजनीतिक और आर्थिक कामकाज की सुविधा प्रदान करते हैं। सदस्य देशों के नौकरशाही तंत्रों पर अपनी इच्छाशक्ति लागू करने के लिए इन्होंने काफी समय तक प्रयास किया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि वैश्वीकरण सर्वोच्चतावाद के उच्चतम रूप के लिए अग्रणी है, अर्थात् एक वैश्विक राज्य या किसी प्रकार की वैश्विक सरकार।

वैश्वीकरण के विभिन्न तत्वों का कुल अलग–अलग संप्रभु राज्य को डब्ल्यूटीओ, यूरोपीय संघ और अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण समूहों, मुक्त व्यापार समझौतों और अन्य अलौकिक संगठनों के रूप में नीति और नियंत्रण के कम से कम क्षेत्र में छोड़ दिया है। इसके अलावा, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक नीतियां आईएमएफ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्रभावित

होने वाले एक बड़े स्तर पर भी हैं, जो शक्ति के नए केंद्रों के साथ एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का प्रमाण है। ऋण और सहायता प्राप्त करने के लिए शर्तें होती हैं जिन्हें प्राप्तकर्ता देशों को पालन करना होता है। अमीर और विकसित देश अक्सर विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए गए सामानों को अधिमान्य बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए मनमाने ढंग से मानदंडों को निर्धारित करते हैं। ये संस्थाएँ और मानदंड शासन के वैश्विक संस्थानों के उदय और वैश्विक आचरण के आदर्श के विभिन्न स्तरों की ओर संकेत करते हैं। वास्तव में, भविष्य के सिविल सेवक के लिए समस्याओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों के बीच सार्थक अंतर निकालना कठिन होगा।

वैश्वीकरण का सार राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों का एक जटिल जाल है, इसका मतलब यह है कि लोगों के जीवन में होने वाली घटनाएं हमसे बहुत दूरी पर लिए गए निर्णय पर आधारित होते हैं। दुनिया पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं के अर्थ में वास्तव में सीमाहीन हो गई है। राष्ट्रीय और राज्य सीमाएँ धुंधली हो गई हैंय और समय और स्थान के लोगों के बीच विभाजन कम महत्वपूर्ण और कभी–कभी पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए हैं।

2.8 संदर्भ ग्रंथ

बर्टेल्सन, जेन्स, (2006), ''दि कॉन्सेप्ट ऑफ सावरींटी रिविजिटेड'', *यूरोपीयन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ,* वॉल्यूम–17, इश्यू–2, अप्रैल, https://academic.oup.com/ejil/article/ 17/2/463/2756259/The-Concept-of-Sovereignty-Revisited.

बोलेव्सकी, विलफ्राइड, (2007), *डिप्लोमेसी एण्ड इंटरनेशनल लॉ इन ग्लोबलाइज्ड रिलेशनशिप,* स्प्रिंगर, बर्लिन।

चतुर्वेदी, इनाक्शी, (एन.डी.), ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट सावरींटी'', *इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन*। http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_249.pdf.

कूपर, स्कॉट, डैर्रेन हॉकिन्स, वाडे जैकोबी एण्ड डेनियल नील्सन (2008), ''यील्डिंग सावरींटी टू इंटरनेशनल इंस्टीच्यूशंस : ब्रिंगिंग सिस्टम स्ट्रक्चर बैक इन'', *इंटरनेशनल स्टडीज रिव्यू*। https://politicalscience.byu.edu/WadeJacoby/Assets/Published%20version_%20misr_802.pdf

ऐलीजाबेथ, ए., (एन.डी.), ''इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दि सावरींटी ऑफ स्टेट्स'', *अफ्रीकन जर्नल्स ऑनलाइन., एन.डी.* https://www.ajol.info/index.php/naujilj/article/ viewFile/82410/72564.

इर्लेनबुश, वेरेना, (2015), ''फ्रॉम सावरींटी टू वार : फोकाउल्ट'ज एनालिटिक ऑफ पावर'', *ई–इंटरनेशनल रिलेशंस,* दिसंबर 12. http://www.e-ir.info/2015/12/12/from-sovereignty-to-war-foucaults-analytic-of-power/

ऐरिक, सी., (2010), ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड दि फ्यूचर ऑफ दि लॉ ऑफ दि सावरीन स्टेट'', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंस्टीच्यूशनल लॉ,* वॉल्यूम–8, इश्यू–3, जुलाई 1.

https://academic.oup.com/icon/article/8/3/636/623517/Globalization-and-the-future-of-the-law-of-the.

गोर्डन, सुज़ाने ई., (2008), ''चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सावरींटी एण्ड ज्यूरिस्डिक्शन इन दि ग्लोबल इकोनॉमी : इज दियर ए टेरीटोरियल कनेक्शन?'' *यॉर्क यूनिवर्सिटी.* http://ccges.apps01.yorku.ca/wp/wp-content/uploads/2008/12/gordon-changing-concepts-of-sovereignty-and-jurisdiction-in-the-global-economy-is-there-a-territorial-connection.pdf.

गोक्सेल, निलूफर काराकासुलू (2012), ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड दि स्टेट'' http://sam.gov.tr/ wp-content/uploads/2012/02/1.-NiluferKaracasuluGoksel.pdf.

हेवूड, एण्ड्रयू, (2015), *ग्लोबल पॉलिटिक्स,* पालग्रेव मैकमिलन, न्यू यॉर्क।

हड्सन, अलन, (1998), ''बियोण्ड दि बॉर्डर्स : ग्लोबलाइजेशन, सावरींटी एण्ड एक्स्ट्रा–टेरिटोरियलिटी'', *जियोपॉलिटिक्स,* वॉल्यूम–3, नं.3 http://alanhudson.info/wp-content/uploads/2013/11/borders.pdf.

कु, जूलियन एण्ड जॉन यू, (2013), ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड सावरींटी'', *बर्कले जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ,* वॉल्यूम–31, इश्यू–1 http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1437&context=bjil.

लॉन्ग, क्युईना, (एन.डी.), ''इज ग्लोबलाइजेशन अण्डरमाइनिंग स्टेट सावरींटी'', *एकेडेमिया,* http://www.academia.edu/2945507/Is_Globalization_undermining_State_Sovereignty.

न्यू वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया (एन.डी.), ''नेशन–स्टेट''। http://www.newworldencyclopedia. org/entry/Nation-state.

पेडनेकर, समीक्षा, (2016), ''दि इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीच्यूशंस ऑन दि आइडिया ऑफ सावरींटी'', *लिंकेडिन,* जुलाई 20, https://www.linkedin.com/pulse/impact-international-institutions-idea-sovereignty-samiksha-pednekar.

सरूशी, डैन, (2010), इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एण्ड दियर ऐक्सरसाइज़ ऑफ सावरीन पावरर्स, ऑक्सफोर्ड, यू.के.।

वालिद, अब्दुलरहीम (एन.डी.), 'स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन', *प्राइवेट साइट फॉर लीगल रिसर्च एण्ड स्टडीज* / https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/7-state-jurisdiction.

यादव, इन्दर शेखर, ''ग्लोबलाइजेशन, स्टेट सावरींटी एण्ड सिविल सोसाइटी', *यूनिवर्सिटी ऑफ देल्ही, एन.डी.* https://sol.du.ac.in/mod/book/view.php?id=1245&chapterid=911.

2.9 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
   - राज्य संप्रभुता की अवधारणाय आंतरिक व बाह्य
   - वैश्वीकरण के तहत राज्य संप्रभुता का संशोधन

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
   - राज्य की राजनीतिक संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव
   - वैश्वीकरण और राष्ट्रीय संस्कृति
   - राज्य और आर्थिक संप्रभुता

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
   - संप्रभु राज्य के क्षेत्राधिकार की अवधारणा
   - राज्य क्षेत्राधिकार के विचार की चुनौतियों को सूचीबद्ध करें

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 3 वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय संस्थाएं (आईएमएफ, विश्व बैंक)

संरचना

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 वैश्विक अर्थव्यवस्था के चरण

3.2.1 व्यापारवाद का युग (1500–1750)

3.2.2 औद्योगिक क्रांति

3.2.3 सन् 1945 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

3.3 नवउदारवाद की पूर्वधारणा और विचारधारा

3.3.1 उदारवाद

3.3.2 नवउदारवाद

3.4 वैश्विक वितीय संस्थाएं

3.4.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

3.4.2 पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी)

3.5 सारांश

3.6 संदर्भ ग्रंथ

3.7 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई में, आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न चरणों से परिचय कराया जाएगा; उदारवाद और इसके विकासवादी चरणों की अवधारणाय और अंत में वैश्विक वित्तीय वास्तुकला जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) शामिल हैं, जिसे आमतौर पर विश्व बैंक कहा जाता है। इस इकाई का अध्ययन करने के बादआप निम्नलिखित को समझने में सक्षम हो जाएंगेः

- वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसके विभिन्न चरणों के माध्यम से समझना;
- नवउदारवाद की व्याख्या–अवधारणा एवं नीतियां;
- आईएमएफ और विश्व बैंक सहित वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के कामकाज की समझ।

3.1 प्रस्तावना

वैश्विक अर्थव्यवस्था में पिछले तीन दशकों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। चारों ओर बहुत अधिक प्रवाह है – आर्थिक और वित्तीय। उदाहरण के लिए, 2008–09 का वैश्विक आर्थिक संकट, विश्व अर्थव्यवस्था में ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवाद और लोकलुभावनवाद के सबसे हालिया ज्वार, विशेष रूप से ब्रेक्सिट वोट और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उत्पन्न डोनाल्ड ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी'। इन विकासों ने आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला पर बहस को मजबूत किया है। जाहिर है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के दायरे में भी वर्षों में विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर राजनीति और अर्थशास्त्र की परस्पर प्रकृति को मिलाते हुए काफी नजदीक आ गई है। आर्थिक कारकों के साथ राजनीतिक कारक वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि आर्थिक और राजनीतिक कारकों का पारस्परिक प्रभाव मौजूद हैय यह बातचीत पिछले कई शताब्दियों में मौलिक तरीकों में बदल गई है। यह विशेष रूप से व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए प्रवाह के कारण अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती निर्भरता का परिणाम है। वैश्विक दुनिया में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के तहत बाजार जटिल अंतरनिर्भरता पैदा करते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वर्तमान इकाई इस प्रश्न को संबोधित करती है और अर्थशास्त्र और राजनीति और वैश्विक आर्थिक अंतर्संबंध के पहलुओं पर प्रकाश डालती है – जिस तरह से यह वर्तमान समय में विकसित हुआ है। वास्तव में, वैश्विक अर्थव्यवस्था सदियों से विचारों और व्यवहार में बदलाव के साथ विकसित हुई है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापारिकता के युग से गुजर चुकी हैय औद्योगिक क्रांति और दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि जिसे संरक्षणवाद और 1929 के महामंदी द्वारा चिह्नित किया गया था। वर्तमान इकाई नवउदारवाद की विचारधारा का वर्णन और विश्लेषण करती है। नवउदारवाद की चर्चा उदारवाद और उसके प्रमुख अभिव्यक्तियों के संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण से पहले का है। अंत में, यह इकाई आईएमएफ और विश्व बैंक के साथवैश्विक वित्तीय संगठन के कामकाज की व्याख्या करता है।

3.2 वैश्विक अर्थव्यवस्था के चरण

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और विभिन्न चरणों को समझने से पहले, विषय के अर्थ और महत्व को समझना आवश्यक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अंतर–आर्थिक गतिविधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक दूसरे पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हालाँकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था को किसी निश्चित समय–सीमा में हुए राजनीतिक विकास के अभाव में नहीं समझा जा सकता है। अर्थशास्त्र और राजनीति का यह परस्पर संबंध हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार और कार्य को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने में राज्य और बाजार के सापेक्ष प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज में राज्य और बाजार के पारस्परिक प्रभाव को रॉबर्ट गिलपिन ने अपने राजनीतिक संबंधों की

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से वर्णित किया हैः ''... राज्य और संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाएं धन और विशेष रूप से,... राजनीतिक निर्णय और हित, आर्थिक गतिविधियों के स्थान और इन गतिविधियों की लागत और लाभों के वितरण को प्रभावित करते हैं।''

विश्व अर्थव्यवस्था में बारे में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, उसे देखते हुए, रॉबर्ट गिलपिन ने कुछ विवरणों में अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच गतिशील अंतर का वर्णन किया है जिसमें ऐतिहासिक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण, वह अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच पारस्परिकता के पहलू पर ध्यान देते हैं। वह इसका वर्णन निम्नानुसार करते हैंः (i) राज्य आर्थिक गतिविधि के ढांचे को निर्धारित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। एक बार किए जाने के बाद, राज्य की नीतियां उन समग्र आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं जो प्रमुख समूहों को लाभ पहुँचाती हैं। जिस तरह से राज्य इस शक्ति का प्रयोग करता है वह एक आर्थिक प्रणाली की प्रकृति को निर्धारित करता है। (ii) गिलपिन आगे कहते हैं कि आर्थिक प्रक्रिया ही शक्ति और धन का पुनर्वितरण करती है। उन्होंने कहा कि ''आधुनिक दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता मोटे तौर पर अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच पारस्परिक संपर्क का एक समारोह है''।

3.2.1 व्यापारवाद का युग (1500–1750)

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उद्भव सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। 1500 –1750 की अवधि को व्यापारवाद का युग कहा जाता है। कभी–कभी, इस अवधि को 'प्रारंभिक पूंजीवाद' या 'व्यापार पूंजीवाद' के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यह वह युग था जब यूरोप ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अन्य महाद्वीपों के साथ सामानों का आदान–प्रदान शुरू किया। अंतर महाद्वीपिय ढुलाई में वृद्धि ने 16 वीं शताब्दी में अंतर महाद्वीपिय व्यापार के विस्तार की सुविधा प्रदान की। 17 वीं शताब्दी में डच और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापार के उद्भव ने बाहरी दुनिया के साथ यूरोपीय व्यापार का स्तर बढ़ाया। वैश्विक व्यापार और इसका विस्तार यूरोप के मजबूत राजशाही राज्यों द्वारा संभव किया गया था। स्वयंसिद्ध को याद रखें : जब शक्तिशाली राज्य इसकी रक्षा करते हैं तो वैश्विक व्यापार पनपता है; यह तब गिरता है जब वे ऐसा नहीं करते। जैसा कि यह हो सकता है, वैश्विक व्यापार ने विश्व बाजार अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाया।

लेकिन व्यापारवाद क्या है? व्यापारवाद एक विचारधारा नहीं हैय बल्कि यह विभिन्न सिद्धांतों और प्रथाओं का एक संयोजन है जिसे यूरोप के विभिन्न देशों ने अलग–अलग समय पर यह सोचकर अपनाया कि ये उनके अपने राष्ट्रीय वाणिज्यिक हित में थे। कुछ मान्यताओं और सिद्धांतों के बारे में जो व्यापारी राज्यों को बहुत प्रिय लगते हैं और कुछ दो–ढाई शताब्दियों के लिए प्रचलित थेः (i) सोना, चांदी और किसी राज्य के स्वामित्व वाली अन्य कीमती धातुएं इसके धन का सूचक है। (ii) एक राज्य को आयात से अधिक निर्यात करना चाहिए ताकि व्यापार का अनुकूल संतुलन बना रहे; और इस प्रकार अधिक कीमती धातुओं का अधिग्रहण करना है। (iii) वैश्विक व्यापार के विस्तार की ऊपरी सीमाएँ हैं। यह माना जाता था कि 17 वीं शताब्दी तक यूरोपीय व्यापार ने इष्टतम स्तर प्राप्त कर लिया है; इसलिए यह अब गतिहीन होगा। (iv) जितनी बड़ी आबादी होगी, राज्य उतना ही मजबूत और

आत्मनिर्भर होगा। (v) राज्य, या राजा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बनाने और दिशा देने में भूमिका निभाते हैं। मजबूत राजशाही को न केवल अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम को भी आकार देना चाहिए।

व्यापारवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं: (i) वस्तु विनिमय प्रणाली गायब हो गई। 15 वीं शताब्दी के अंत तक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में धन अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। मुद्रा का मान बढ़ गया। यूरोपीय मुद्राएं बहुत शक्तिशाली हो गईं और उनका प्रचलन दूर–दूर के स्थानों में बढ़ गया। 'धन का अर्थ है धन की उत्पत्ति', यह कहावत व्यापारिकता के युग में हुई। यह माना जाता था कि एक धनवान व्यक्ति अपनी पसंद के सामान और सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। (ii) यूरोप में बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का गठन किया गया। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में छोटे राज्यों और रियासतों को एक किया, यानी लोगों का एक ही वंश, भाषा, संस्कृति, इतिहास आदि हो। बड़े राष्ट्र राज्यों ने संसाधनों और बाजारों के लिए लगातार युद्ध लड़ने के लिए बड़े नौकरशाहों और सेना का निर्माण किया। इन विकासों और विशाल दरबारी खर्चों के लिए और अधिक धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए सोने और चांदी जैसी अधिक धातुओं की आवश्यकता थी। नौकरशाही करियर सबसे आकर्षक थेय और व्यापारिक युद्ध यूरोप और विदेशों में फैल गए। (iii) विदेशी व्यापार, न कि घरेलू व्यापार कोसोने, चांदी और कीमती धातुओं और खनिजों को प्राप्त करने के लिए पसंदीदा पद्धति के रूप में देखा गया। निर्मित वस्तुओं में विदेशी व्यापार को कृषि वस्तुओं पर अधिक पसंद किया गया। (iv) यह खोज का युग था। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका और 1497–99 में वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ने इस तरह के धन को प्राप्त करने का जबरदस्त अवसर दिया। यूरोपीय खोजकर्ताओं ने पूरब के साथ पश्चिम को जोड़ा – जिसके परिणामस्वरूप रेशमी सड़कों तथा समुद्री रास्तों से मसालों का व्यापार होने लगा। अधिक धन रखने की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रही; बदले में, विदेशी उपनिवेशों और व्यापार को जीतने और बचाने के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। नए वैज्ञानिक खोजों और नवाचारों द्वारा व्यापारिकता की आयु संभव हो गई थी। यह खगोल विज्ञान, यांत्रिकी, भौतिकी और शिपिंग के क्षेत्र में ''वैज्ञानिक क्रांति'' का युग था। वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों ने पुर्तगाली, स्पेनिश और बाद में डच और अंग्रेजी द्वारा कालोनियों की खोज और निर्माण में सहायता दी। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना उस समय के सबसे बड़े करतबों में से एक था: इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण में सहायता की। नई भूमि की खोज और नई फसलों की शुरूआत ने अफ्रीकी दासता की संस्था बनाई – एक विरासत जो आज तक कई बदसूरत तरीकों से खुद को प्रकट करती है। (v) व्यापारवाद ने राज्य की आंतरिक और बाह्य दोनों आर्थिक नीतियों पर अधिक से अधिक शाही नियंत्रण की मांग कीय इसने धीरे–धीरे मजबूत राजशाही से निरंकुश राज्यों में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा, जब कालोनियों की संख्या बढ़ती गई और आकार में विस्तार हुआ, तो उन्हें वहां के संसाधनों और लोगों का शोषण अपने देश के लाभ के लिए वैध लगने लगा। ''इन सभी कारकों ने यह सुनिश्चित किया कि उत्तर मध्ययुगीन और शुरुआती आधुनिक युग के राज्यों ने एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में व्यापारवाद को अपनाया, जिसने उन्हें इन स्थानांतरित संस्थाओं का दोहन करने की अनुमति दी'' (स्रोत: ''यूरोप, 1450 से 1789'', एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड)।

18वीं शताब्दी के मध्य में व्यापारिकता का युग समाप्त हो गया। नए आर्थिक विचारों ने व्यापारवादी धारणाओं और विचारों को बदनाम कर दिया। सबसे प्रभावशाली था लैसेज फेयर अर्थव्यवस्था का विचार। लैसेज फेयरके सिद्धांत ने व्यापारीवादी पूंजीवाद की दो मुख्य धारणाओं को खारिज कर दिया : सोने और अन्य कीमती धातुओं की उपलब्धता सीमित हैय और यह कि वैश्विक व्यापार की एक ऊपरी सीमा है जहां यूरोप पहले ही पहुंच चुका है। डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ लैसेज फेयर के मुख्य प्रस्तावक थे। डेविड ह्यूम (1711–1776) ने उन प्राकृतिक लाभों की पहचान करने की कोशिश की, जिसका विभिन्न देशों ने वाणिज्य के प्रवाह में आनंद लिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नया सिद्धांत प्रदान किया। एडम स्मिथ (1723–1790) ने तर्क दिया कि वैश्विक धन स्थायी नहीं थाय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत ने काम किया। लाभ की भावना यानी बाजार का 'अदृश्य हाथ' मानव को श्रम के लिए प्रेरित करता है।

3.2.2 औद्योगिक क्रांति

औद्योगिक क्रांति ने अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप की तकनीकी, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को बदल कर रख दिया। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई – एक प्रक्रिया जो अब भी औद्योगीकरण के रूप में जारी है।

औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? यह सवाल सामाजिक विज्ञान में काफी हद तक अनुत्तरित है। कई सिद्धांतों को आगे रखा गया है। कहने के लिए पर्याप्त है कि यह सामाजिक और संस्थागत परिवर्तनों से उत्पन्न हुआ जो सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजी गृह युद्ध के बाद इंग्लैंड में कमजोर होते सामंतवाद से पीछे रह गया था। हालाँकि, हर कोई इस बात से सहमत है कि तकनीकी नवाचारों द्वारा औद्योगिक क्रांति संभव हो गई थीय और इनमें प्रमुख भाप इंजन का आविष्कार थी।

इतिहासकार भी एकमत नहीं हैं कि यह कब शुरू हुआ? एरिक हॉब्सबॉम का मानना है कि 1780 के दशक में औद्योगिक क्रांति कीश्शुरुआतश्हो गई थीऔर 1830 या 1840 के दशक के पहले तक काफी प्रभावी नहीं था। दूसरे शब्दों मेंकहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति सामूहिक रूप से तकनीकी परिवर्तनों को संदर्भित करती है जो पांच से छह दशकों के लंबे अंतराल में हुईऔर उसके बाद भी जारी रही।

हालांकि, इसके गहन प्रभाव से कोई असहमत नहीं है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक क्रांति मानव सामाजिक इतिहास में एक प्रमुख मोड़ है। इसका प्रभाव जीवन और समाज के सभी पहलुओं पर काफी पड़ा है – धन; सामाजिक जीवन; और राजनीतिः (i) इसने उत्पादन और उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि की, और इस प्रकार प्रति व्यक्ति धन में वृद्धि हुई। (ii) औद्योगिक क्रांति ने एक नए सामाजिक व्यवस्था को जन्म दियाः 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक, उद्योगपतियों और व्यापारियों का एक मजबूत मध्य वर्ग बन चुका था जो जमींदारों और रईसों के वर्ग पर विजय प्राप्त कर चुका था। बड़ी आबादी फैक्ट्री साइटों में चली गई, जहां वे फैक्ट्री के मजदूर बन गए। कार्ल मार्क्स के अनुसार, औद्योगिकीकरण ने समाज को दो वर्गों में विभाजित कियाः पूंजीपति (जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं) और सर्वहारा (श्रमिक वर्ग)।

(iii) 1844 में, फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा कि औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में नागरिक समाज को बहुत बदल दिया था। जल्द ही, करदाताओं ने मताधिकार के अधिकार की मांग की। प्रिंटिंग प्रेस में वाष्प शक्ति का उपयोग समाचार पत्र के व्यापक विस्तार और लोकप्रिय पुस्तकोंके प्रकाशन की सुविधा देता है। मुद्रित सामग्री से साक्षरता तक आसान पहुंचय और आगे लोकप्रिय राजनीतिक भागीदारी के लिए मांग करता है। 1832, 1867 और 1884–85 के सुधार विधेयकों के तहत ब्रिटेन में अधिक से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था।

(iv) अन्य परिवर्तन समान रूप से गहरे थे : वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक जांच का प्रसार। सामाजिक मुद्दों पर वैज्ञानिक ज्ञान लागू होने लगा। अनुभवजन्य और वैज्ञानिक रूप से शोध कार्य का एक उदाहरण एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशंस था। पूंजीवाद के लिए उनका मुख्य तर्क यह है कि औद्योगिकीकरण सभी के लिए धन में वृद्धि करता है, जैसा कि इंग्लैंड में बढ़ती खपत और जीवन प्रत्याशा से पैदा होता है।

मुक्त बाजार पूंजीवाद के गुणों पर एडम स्मिथ के विचारों का संक्षिप्त विवरण सहायक होगा। (i) एडम स्मिथ ने आधुनिक उद्योगों को श्रम विभाजन के आधार पर काम करते देखा। उन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन कारखानों का उत्पादन और अपने श्रमिकों की उत्पादकता दोनों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। (ii) विकास और समृद्धि दर्ज करने के लिए अर्थव्यवस्थाएं तुलनात्मक लाभ के मार्ग का अनुसरण करती हैं। (iii) उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के पास अपने स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक इच्छाशक्ति होती है। यह स्व–हित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके बाजारों की व्यक्तिगत मांगों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इसे 'अदृश्य हाथ' कहा। उदाहरण के लिए, यह परोपकार नहीं बल्कि स्वार्थ है जो एक बेकर उपभोक्ताओं को रोटी प्रदान करता है। (iv) उन्होंने सुझाव दिया कि व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा अच्छी है। प्रतिस्पर्धा निर्माताओं को ईमानदार रखती है। ग्राहक बेईमान विक्रेता से बच सकते हैं और ईमानदार को संरक्षण दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धाउचित मूल्य, उत्पाद की गुणवत्ता और आर्थिक नवाचार सुनिश्चित करती है।

3.2.3 1945 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार

यह व्यापारिकता के युग में था कि यूरोप ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अन्य महाद्वीपों के साथ सामानों का आदान–प्रदान शुरू किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने तक चार शताब्दियों तक, संपूर्ण वैश्विक व्यापार में इंट्रा–यूरोपीय व्यापार सबसे महत्वपूर्ण रहा। तकनीकी नवाचारों ने विदेशी व्यापार और औपनिवेशिक विस्तार की सुविधा प्रदान की। 18 वीं शताब्दी के मध्य से, समुद्री व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई।

प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक क्रांति से लेकर, तीन यूरोपीय शक्तियाँ ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी थे। तीनों ने बाहर की दुनिया के साथ यूरोप के वाणिज्यिक लिंक भी निर्धारित किए। उनका यूरोप के तीन–चौथाई से अधिक औद्योगिक उत्पादन और शेष दुनिया के साथ यूरोप के तीन–चौथाई से अधिक व्यापार का हिसाब था। तीनों अर्थव्यवस्थाओं में उनके बारे में उच्च स्तर की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा थी। इसके कारण उन्होंने बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया और कच्चे माल का आयात किया। प्रथम विश्व युद्ध के शुरु होने तक, तीनों पूंजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर भी हावी थे। ग्रेट ब्रिटेन वैश्विक पूंजी

बाजार का केंद्र था और यह व्यापार और वित्तीय नवाचारों के साथ आया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दुनिया के सभी पैसे और पूंजी बाजार में सोने के मानक के सिद्धांत का पालन किया। फ्रांस ने नए मानदंड और कानून तैयार किए, जिससे वैश्विक वित्तीय और राजकोषीय मामलों में बहुत अधिक तर्कसंगतता आई। विभिन्न उपायों को अपनाया गयाः जैसे कि सिक्कों और तौल के क्षेत्रों में मानक, साथ ही मुद्रा और बैंक सुधार आदि, विरोधी संरक्षणवाद, और व्यापारियों के अपराध को भंग करना। 18 वीं शताब्दी में लॉजेज के विचारों के प्रसार ने वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया। 18 वीं शताब्दी में कई मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थेय अधिकांश इष्ट राष्ट्र (एमएफएन) का सिद्धांत व्यापारिक राष्ट्रों द्वारा तैयार करके उसे अमल में लाया गया था।

इन सभी उपायों और विकासों ने वैश्विक व्यापार को बहुत स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएँ बहुत विविध थीं। उनके बारे में उच्च उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के साथ, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने लगीं। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने नवाचारों को लियाय और 19 वीं सदी के अंत तक इस्पात उत्पादन, रेलवे उपकरण, भारी मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विश्व में अग्रणी बना। एक उदारीकृत व्यापार प्रणाली ने यूरोप और बाकी दुनिया के बीच आंतरिक यूरोपीय व्यापार और व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया। श्रम का एक नया अंतर्राष्ट्रीय विभाजन अस्तित्व में आयाः यूरोप निर्मित उत्पादों, पूंजी और मशीनरी का निर्यात करता थाय बदले में, यह उपनिवेशों और दुनिया के अविकसित क्षेत्रों से कच्चे माल का आयात करता था।

20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, दो घटनाएं वैश्विक मुक्त व्यापार प्रणाली के लिए विनाशकारी साबित हुईं। प्रथम विश्व युद्ध ने इसे नुकसान पहुंचायाय युद्ध के बाद प्रणाली को फिर से जीवित करना असंभव हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विघटन हो गया था; 1914 में रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी मुद्राओं की परिवर्तनीयता को सोने में बदल दिया था। 1929 कीमहामंदी वैश्विक मुक्त व्यापार के लिए दूसरा झटका थाः वैश्विक व्यापार की मात्रा में 26 प्रतिशत और यूरोपीय व्यापार में 38 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्रवादी बन गईंय और संरक्षणवाद और व्यापारिक भेदभाव करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के प्रकोप ने यूरोप के भीतर माल और पूंजी के प्रसार को अवरुद्ध कर दिया। यूरोपीय देशों को शांति के समय कारखानों के उत्पादन की तरह युद्ध के बाद उत्पादन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ीय जिसके कारण नौसेना अवरोध और लेनदेन की उच्च लागत थी। इसके अलावा, जब युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप ने खुद को उदार पूंजीवादी और कम्युनिस्ट शिविरों के बीच विभाजित पाया। संक्षेप में, उदारीकृत व्यापार शासन को दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में छोड़ दिया गया था।

अंतर–युद्ध की अवधि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अन्य बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लेकर आई। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वैश्विक व्यापार की धुरी को स्थानांतरित कर दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त में अमेरिका का प्रभाव और उसकी भूमिका 1918 के बाद तेजी से बढ़ी। 1929की महामंदी के बाद, अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामलों में अग्रणी बन गया। जब यूरोप 1929 में महामंदी में घिर गया और वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा गिर गया, तो अमेरिका,

कनाडा और जापान जैसी अन्य औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका यूरोप के बचाव में आया। इसने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना शुरू की। इसमें उद्योगों की बहाली, एक मौद्रिक आदेश की स्थापना और एक बार फिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के साथ यूरोप का एकीकरणअमेरिका के नेतृत्व में हुई। मार्शल प्लान एक सफलता थी और यूरोप प्रभावशाली निर्यात–नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि में लौट आया। एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार वास्तुकला भी उदार आर्थिक लाइनों के साथ परिकल्पित किया गया था।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) व्यापारिकता के सिद्धांतों और प्रथाओं का वर्णन करें।

2) औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 नवउदारवाद और उसके पूर्व की विचारधारा

नवउदारवाद की परिभाषा क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है? क्या नवउदारवाद का अर्थ उदारवाद का पुनरुत्थान है? कई लोगों ने नवउदारवाद की विचारधारा को समझाने और समझाने की जहमत नहीं उठाई। यह आलोचक है जो अक्सर नवउदारवाद को कम करता हैः यह लाभकारी, उपभोक्तावाद, पर्यावरण की अवहेलना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो बाजार की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और जहां राज्य ने सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को छोड़ दिया है।

नवउदारवाद को उदारवाद के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिएय इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं। नवउदारवाद एक विशिष्ट विचारधारा हैय हालांकि यह कुछ ऐतिहासिक जड़ों और उदारवाद के साथ कुछ बुनियादी शब्दावली साझा करता है। राजनीतिक दर्शन के रूप में उदारवाद की कई परंपराएं हैं। उनमें से एक आर्थिक उदारवाद है। कोई कह सकता है कि यह आर्थिक उदारवाद है जो समकालीन समय में नवउदारवाद के सबसे करीब आता हैय हालांकि अभी भी एक अंतर के साथ। जैसा कि ज्ञात है, आर्थिक उदारवाद यह विचार रखता है कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बजाय व्यक्तिगत रूप से बाजार अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से काम करने दें जो कि स्वतंत्र और आत्म–विनियमन है।

एक बार फिर से दोहराने के लिए, उदारवाद के साथ नवउदारवाद और आर्थिक उदारवाद को मिलाएं। नवउदारवाद एक विचारधारा से अलग है और, वास्तव में, अक्सर 'उदारवाद' का विरोध किया जाता है। आइए हम उदारवाद और इसके विभिन्न चरणों और आयामों पर एक संक्षिप्त नजर डालें।

3.3.1 उदारवाद

उदारवाद का दर्शन कई चीजों के लिए महत्वपूर्ण हैः लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार, कानून का शासन, व्यक्तिगत अधिकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आदि। यह 19 वीं शताब्दी के यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। ये उदारवादी मूल्य द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से कम से कम पश्चिमी विचारों का हिस्सा बने हुए हैं।

दर्शन के रूप में उदारवाद का इतिहास काफी पुराना और विविध है। अवधारणा समय के साथ अस्पष्ट हो गई हैय इसके अलावा, एक नहीं बल्कि कई तरह के उदारवाद हैं। जॉन लोके, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और यशायाह बर्लिन और जॉन रॉल्स जैसे समकालीन दार्शनिक सभी उदारवादी हैं, लेकिन लोकतंत्र के गुण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा, कल्याणकारी राज्य के विचार और राज्य और बाजार के बीच के समीकरण जैसे मुद्दों पर उनके बीच गहरा मतभेद है। यह संभव है कि अक्सर 'शास्त्रीय' और 'आधुनिक' उदारवाद के बीच साधारण अंतर हो।

i) शास्त्रीय उदारवाद

17 वीं और 18 वीं सदी के दार्शनिक जॉन लोके और एडम स्मिथ से लेकर 20 वीं सदी के दार्शनिक फ्रेडरिक वॉन हायेक सभी 'शास्त्रीय' उदारवाद की परंपरा से संबंधित हैं। 'शास्त्रीय' उदारवाद का मानना है कि राज्य को कानून और व्यवस्था और रक्षा जैसे न्यूनतम काम करने चाहिए। सभी को व्यक्तिगत और उन संगठनों की स्वतंत्र पसंद पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो वह स्थापित करता है और इसमें भाग लेता है। बाजार को अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए मजबूर करें; राज्य केवल 'रात का चौकीदार' है। इस प्रकार वर्णित 'शास्त्रीय' उदारवाद का आर्थिक उदारवाद के साथ घनिष्ठ संबंध है (लेकिन दोनों परस्पर विनिमय योग्य नहीं हैं)। बिना अपवाद के शास्त्रीय उदारवादी आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं – आज के नवउदारवादियों द्वारा एक दार्शनिक स्थिति। 'शास्त्रीय' उदारवादियों का मानना था कि मुक्त बाजार आर्थिक नीतियाँ अंततः सर्वांगीण समृद्धि का उत्पादन करेंगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देंगी।

19 वीं शताब्दी के दौरान शास्त्रीय उदारवाद औद्योगिकीकरण का कारण बना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बैनर को उठाते हुए, उद्योगपतियों और व्यापारियों के उद्यमी वर्ग ने उत्पादन का विस्तार करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अपने धन में वृद्धि की। लॉज फेयर में विश्वास शास्त्रीय उदारवाद के मूल में था; और इसे ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए रामबाण माना जाता था।

19 वीं शताब्दी के अंत में, लॉज फेयर में विश्वास ने अपनी पूरी पैठ बना ली। विचार बदनाम हुआ; इतना तो है कि कई लोग एक आर्थिक मॉडल के रूप में

पूंजीवाद की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठा रहे थे। औद्योगिकीकरण ने बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अनुमति दी थी, लेकिन बहुत से लोग उन्हें खरीद सकने की स्थिति में नहीं थे। उत्पादों के साथ बाजार को चमकाया गया थाय लेकिन केवल खरीदार काफी कम थे। संपूर्ण उत्पादन प्रणाली समय–समय पर गतिरोध के कारण बंद हो गई। लंबे समय तक बिना खरीद और स्थिर उत्पादन के ये लंबे समय तक बने रहे जिन्हें मंदी कहा जाने लगा। लॉज फेयरकी विचारधारा के तहत काम करते हुए, सरकारों ने कुछ नहीं किया। किसी भी मामले में, सरकारों ने केवल उद्योगपतियों और व्यापारियों से बोली लगवाई। औद्योगिक क्रांति के अन्य अप्रत्याशित परिणाम थेः धन की एकाग्रताय श्रमिक वर्ग की निम्न आय और गरीब आबादी के साथ शहरीकरण। स्थिति की विडंबना यह नहीं थीः बहुत ही ताकतें जो कभी उद्यमी ऊर्जा को जारी करती थीं, अब उन्हें नियंत्रित करती हैं। और जो कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकारों के चौंपियन थे, उन्होंने अब निरंकुशता का अभ्यास किया।

ii) आधुनिक उदारवाद

19 वीं शताब्दी के अंत तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के काम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया गया थाः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उतार और चढ़ाव के चक्रों से गुजरती है। आवधिक ठहराव एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र का हिस्सा हैय और बाजार अकेले इसे ठीक नहीं कर सकता। यह भी स्थापित किया गया था कि लैसेज फेयर के दर्शन में भी आर्थिक मंदी से निपटने का कोई तरीका नहीं है। ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक टी.एच. ग्रीनके अनुसार, असमानता, अज्ञानता और गरीबी नई प्रकार की बाधाएँ हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं और सरकारों को निरंकुश बनाती हैं। एक व्यक्ति अकेले अपने प्रयासों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर नहीं कर सकता है। ग्रीन ने लिखा कि स्वतंत्रता के लिए इन बाधाओं से सरकार की सकारात्मक सहायता से ही निपटा जा सकता है।

इस तरह आधुनिक उदारवाद का जन्म हुआय आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में राज्य की सकारात्मक भूमिका की वकालत करता है। टी.एच. ग्रीन ने स्कूलों, अस्पतालों, रोजगारसृजन और श्रम अधिकारों आदि की स्थापना में राज्य की सकारात्मक भूमिका की वकालत की। आधुनिक उदारवाद एक मुक्त बाजार के गुणों में विश्वास करता है, लेकिन यह मुक्त बाजार आर्थिक प्रणाली को संशोधित और विनियमित करना चाहता है। यह आधुनिक उदारवादियों और शास्त्रीय उदारवादियों के बीच अंतर बन गयाः बाद में यह मानना जारी रहा कि बाजार में पूर्ण स्वतंत्रता विकास और समृद्धि का उत्पादन करेगी, और अंततः समाज में एक संतुलन होगा। तुलनात्मक रूप से, आधुनिक उदारवादियों का तर्क है कि बाजार के संचालन को पूरक और सही करने की आवश्यकता है। यह बाजार और राज्य के बीच संतुलन बनाने का आह्वान करता है। आधुनिक उदारवादी कल्याणकारी राज्य के विचार की वकालत करते हैंय और मानते हैं कि भौतिक प्रगति से मानवीय दुनिया की स्थापना होगी।

19 वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल और 20 वें में जॉन रॉर्ल्स आधुनिक उदारवाद के इस ब्रांड की सदस्यता ली। आधुनिक उदारवाद की एक और

हालिया शाखा है जिसे उदार समतावाद कहा जाता हैः जॉन रॉल्स स्वतंत्रता के साथ समानता पर भी जोर देते हैं। उदारवादी समतावादियों का तर्क है कि राज्य को समानता और स्वतंत्रता दोनों की स्थापना के बारे में प्रयास करना चाहिए। राज्य स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है ताकि समाज में अधिक से अधिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। बेशक, उदारवादी समतावादी भी, सभी आधुनिक उदारवादियों की तरह, आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं जो पूंजीवाद के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार उपरोक्त 'शास्त्रीय' और आधुनिक उदारवाद के बीच अंतर स्पष्ट होता है। उनका आवश्यक अंतर राज्य की भूमिका और बाजार और राज्य के बीच के समीकरण पर है।

iii) जॉन मेनार्ड कीन्स

जॉन मेनार्ड कीन्स ने दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में लिखा था। उनके अनुसार 20 वीं सदी के समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत जटिल थे। एक अनियंत्रित मुक्त बाजार का विचार, जैसा कि शास्त्रीय उदारवादियों ने सुझाया था, या आधुनिक उदारवादियों द्वारा वकालत की गईबाजार अर्थव्यवस्था का विचार जिसमें राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी थी, वह भीअपर्याप्त साबित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ने पिछले चार शताब्दियों में व्यापार के उदारीकरण और मानदंडों और मानकीकरण के मामले में एक वित्तीय और व्यापार बुनियादी ढांचे के निर्माण के संदर्भ में जो कुछ भी प्राप्त किया था, उसे नष्ट कर दिया था। कीन्स का संबंध 1929 के महामंदी से भी था जो असामान्य रूप से भयानक था और बहुत लंबे समय तक चला। एक उदार अर्थशास्त्रीहोने के कारण वे श्रम अशांति और सोवियत संघ से आने वाले वैकल्पिक समाजवादी आर्थिक विचारों से चिंतित थे। सबसे महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट था कि पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था के कामकाज को कारगर बनाने के लिए कुछ तर्कसंगत आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है। यह वह संदर्भ था जिसमें उदारवादी ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों को बौद्धिक और नीति–निर्माण मंडलियों के बीच व्यापक स्वीकृति मिली। अपने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी (1936) में, कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था का सरकारी प्रबंधन व्यवसाय चक्र के उतार और चढ़ाव को सुचारू रूप से समाप्त कर सकता है, जो कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। न्यूनतम बेरोजगारी के साथ अधिक या कम सुसंगत विकास का उत्पादन करने के लिए राज्य विनियमन और हस्तक्षेप आवश्यक है।

कीन्स के विचारों का प्रभाव उदार पूंजीवादी देशों में व्यापक था। अमेरिका में, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट (1933–39) ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महामंदी से बाहर निकालने के लिए नई तैयारी शुरू की। इस तैयारी से सरकार ने आर्थिक नियमों और कल्याण उपायों के माध्यम से अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का विस्तार किया। रूजवेल्ट प्रशासन ने नौकरियों के सृजन के लिए कदम उठाए, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की स्थापना की, और बैंकों और उद्योग के कामकाज को विनियमित किया।

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान ने लगातार आर्थिक विकास और समृद्धि के दौर में प्रवेश किया।

उदार अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने अब संस्थागत कारकों पर ध्यान देना शुरू किया जो इन देशों में उच्च आर्थिक विकास का उत्पादन करेंगे। कीन्स से प्रेरित होकर, पश्चिम में उदारवादी नेताओं ने सरकार की शक्ति का उपयोग उधार लेने, कर लगाने और व्यापार चक्र के संकुचन का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के निरंतर विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आगे यह कहा गया कि राज्य द्वारा कल्याणकारी उपायों से वर्ग संघर्ष कम हो जाता है, लोकतंत्र से आम सहमति मजबूत होती है और साम्यवाद की अपील का मुकाबला होता है। ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियाई देशों, कनाडा और अमेरिका में प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पेश किए गए। 1960 के दशक तक, आधुनिक कल्याणकारी राज्य ने न केवल सामाजिक बीमा के सामान्य रूप प्रदान किए, बल्कि पेंशन, बेरोजगारी लाभ, चिकित्सा सहायता, परिवार भत्ते और सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा भी प्रदान की।

कीन्स के विचारों का वैश्विक वित्त और व्यापार के नए संस्थानों पर समान रूप से गहरा प्रभाव पड़ा जो 1940 के दशक में स्थापित किया गया था। कीन्स का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में बदला जा सकता है। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में अपने काम से, और अपने पूरे जीवनकाल में, कीन्स ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका निभाई। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनके कुछ विचार, संक्षेप में कहें, तोः (i) 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, कीन्स ने औपनिवेशिक और अधीनस्थ लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। उनका मानना था कि घरेलू आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों की स्वतंत्रता आवश्यक है। (ii) उन्होंने घरेलू आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अलगाव की राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता निर्धारित की। (iii) उन्होंने दो बातों की वकालत कीः सरकारों को पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना चाहिए और वास्तविक वेतन का सही स्तर बनाए रखना चाहिए। ये दोनों युद्ध और संघर्ष के आर्थिक कारणों को समाप्त करेंगे। सरकारों की ऐसी नीतियां हालांकि कभी–कभार महंगाई पैदा करती हैं, लेकिन यह शांति और विकास का अनिवार्य हिस्सा है। (iv) हालांकि वह इस बात से सहमत थे कि राष्ट्र के लिए मुद्रास्फीति सही नहीं है। उन्होंने निश्चित विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर प्रतिबंधों के विचार को स्वीकार किया ताकि देश स्वतंत्र आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा सकें। (v) उन्होंने देखा था कि 1920 और 1930 के दशक में सरकारें मुख्य रूप से अपने घरेलू आर्थिक मुद्दों से संबंधित थीं, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो। कीन्स ने समझा और 1930 के दशक में संरक्षणवाद और अलगाववाद को स्वीकार किया। (vi) द्वितीय विश्व युद्ध से एक सबक मिलाः वैश्विक शासन के मामलों को अप्राप्य नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कीन्स शांति और सभ्यता के लाभों में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने श्रम की कमी और क्रांतिकारी विचारों को उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए जुड़वां खतरों के रूप में देखा। फिर, इन चुनौतियों को पूर्ण रोजगार और सभ्य मजदूरी की सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से जांचा जा सकता है – ताकि वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

कीन्स, यूएस ट्रेजरी के अधिकारी हैरी डेक्सटर व्हाइट के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बौद्धिक संस्थापक पिता माने जाते हैं, जो ब्रेटन वुड्स,

न्यू हैम्पशायर में बनाए गए थे। 1936 से 1946 तक, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए काम किया, जो एक–दूसरे के खिलाफ देशों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महत्वपूर्ण रूप से, वैश्विक अर्थव्यवस्था की संस्थागत बुनियाद – आईएमएफ और विश्व बैंक – अपने समय से काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं।

3.3.2 नव उदारवाद

नवउदारवाद को न तो किसी सटीकता के साथ परिभाषित किया जा सकता है और न ही इसकी ऐतिहासिकता को निश्चितता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह के नवउदारवाद के अर्थ और उत्पत्ति के बारे में भ्रम है। समर्थकों ने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है; जबकि आलोचक नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के नकारात्मक आयामों पर प्रकाश डालते हैं – धन की एकाग्रता, असमानता में वृद्धि, वैश्विक और राष्ट्रीय कॉर्पोरेट हितों का वर्चस्व, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगम जो राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर प्रवेश करते हैं और राज्य संप्रभुता को कम आंकते हैं। नव उदारवादियों का दावा है कि उनके आर्थिक नीतिगत विचार एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो से लिए गए हैं। वे तुलनात्मक लाभऔर अदृश्य हाथजैसी अवधारणाओं का उल्लेख करते हैं जो बाजार को चलाते हैं।

1970 के दशक में नवउदारवाद के उदय ने जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों के एक ग्रहण को चिह्नित किया, जिन्होंने रोजगार के निर्माण और धन के पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका की वकालत की थी। मिल्टन फ्रीडमैन जैसे नवउदारवादी, मौद्रिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो राज्य की किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका को छूट देते हैं। यह विचार कि बाजार स्व–नियमन कर रहे हैं, नवउदारवादियों की मान्यताओं के केंद्र हैं। न उदारवादियों का कहना है कि संसाधनों का कुशल आवंटन एक आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैय और संसाधनों को आवंटित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका बाजार तंत्र है। राज्य का हस्तक्षेप बाजारवाद और इस प्रकार आवंटन के संसाधन की दक्षताके तर्क को विकृत करता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप सबसे अवांछनीय है। यह माना जाता है कि राज्य का हस्तक्षेप बाजार के तर्क को कमजोर करता है और इस प्रकार आर्थिक दक्षता को कम करता है (थोरसेन और लाइ)।

नवउदारवाद ने आर्थिक विकास की धारणा को बदल दी है। आईएमएफ, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने आर्थिक विकास के नवउदारवादी तरीके का समर्थन किया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने इसे लंबे समय के लिए चौंपियन बनाया और विकासशील देशों में वित्तीय सहायता और ऋण, व्यापार रियायतें, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की ऋण नीतियों और निजी अंतरराष्ट्रीय बैंकों और बहुराष्ट्रीय निगमों आदि के कामकाज के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं, बहुपक्षीय संगठनों और निजी अंतरराष्ट्रीय बैंकों के बीच आम सहमति को अक्सर 'वाशिंगटन सहमति' के रूप में संदर्भित किया जाता है – एक आम सहमति जो 1970 के दशक में नवपाषाण मॉडल के निर्धारित मार्ग पर आर्थिक विकास या समाजवादी प्रणाली के कीन्जियन मॉडल के खिलाफ थी। आज जबसुधारों की बात की जाती है, तो अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है निजीकरण के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिक आर्थिक और वित्तीय उदारीकरण, अमीरों के लिए कर में कटौती और श्रम और अन्य अधिकारों

और सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाप्त करना। लगभग हर देश में, सार्वजनिक क्षेत्र को नवउदारवाद के तर्क के अनुसार निजीकरण और विघटित किया गया हैय यह भी धारणा है कि बाजार संसाधनों का सबसे अच्छा आवंटन है।

नवउदारवाद से जुड़ी कुछ प्रमुख धारणाएं और नीतिगत विचार हैंः (i) मानवीय भलाई के लक्ष्य को मनुष्य की उद्यमशीलता की स्वतंत्रता और कौशल द्वारा सबसे अच्छा काम किया जा सकता है। (ii) इसके लिए, एक संस्थागत ढांचे का होना आवश्यक है जो निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार की गारंटी देता है। (iii) नवउदारवादी राज्य की भूमिका की वकालत करते हैं। यह वह राज्य है जो संस्थागत ढांचे की सुविधा का निर्माण और गारंटी देता है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए धन, व्यावसायिक अनुबंधों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं, घरेलू स्थिरता और सैन्य रक्षा की गारंटी चाहिएय और व्यवसायिक क्षेत्र को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कानूनी ढांचा। यदि बाजार मौजूद नहीं है या कमजोर है, या वित्तीय अशांति और आर्थिक मंदी आदि का सामना कर रहे हैं, तो राज्य को बाजार बनाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, या पूंजी लगाकर और तथाकथित बचाव पैकेजों के माध्यम से मौजूदा बाजार को मजबूत करना चाहिए। सरल शब्दों में, नवउदारवाद इस बात की वकालत करता है कि राज्य अपनी जरूरत के समय में निजी व्यवसाय को बचाने और उसकी सेवा करने के लिए सार्वजनिक धन खर्च करते हैं। (iv) राज्य को सामाजिक क्षेत्रों – शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षासे बाहर निकलना चाहिए। इन सामानों के निजी आपूर्तिकर्ता बनाएँ। (v) आगे इसे ऐसे बाजार बनाने चाहिए जहां ये मौजूद न हो। इसे निजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यह निजी संपत्ति बनाना चाहिए जहां कोई भी मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, राज्य भूमि और जंगलों, पानी और सिंचाई, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण प्रदूषण जैसे क्षेत्रों में बाजार बना सकते हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों का निजीकरण करेंय और उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज के लिए भुगतान करने दें। (vi) राज्य को इन आर्थिक कार्यों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह बाजारों के काम को बिगाड़ देगा और इस तरह आर्थिक विकास की संभावना को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से लोकतंत्र में यह खतरा हैः बाजार के काम को बिगाड़ने के लिए एक राज्य का लाभ उठाया जा सकता है। इससे क्रोनी कैपिटलिज्म औररेंटियर को बढ़ावा मिल सकता है। एक आम कहावत है : बाजारों को सबसे अच्छी जानकारी होती है। अंत में, राज्य के लिए सबसे आवश्यक है : एक बार बाजार बनने के बाद, राज्य न्यूनतम तक ही सीमित हो जाए। यह शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का रात्रि प्रहरी है। (vii) संक्षेप में, नवउदारवाद एक विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत के रूप में सामने आता है जिसने हाल के दिनों में आधुनिक उदारवाद की कीनेसियन किस्म को बदल दिया है। वास्तव में, नवउदारवाद के बारे में कुछ भी उदार नहीं है। विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव प्रगति के आदर्शों से बहुत दूर है। 20 वीं शताब्दी के कुछ सबसे बुरे सत्तावादी शासन ने नवउपनिवेशवाद का अभ्यास किया, उदाहरण के लिए चिली (1973–1989) में ऑगस्टो पिनोशे का शासन। नवउदारवाद अधिक राजनीतिक और आर्थिक प्रथाओं का एक समूह है जो निजी आर्थिक बलों के आसपास केंद्रित होता है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) जॉन मेंआर्ड कीन्स के विचारों को संक्षेप में लिखें।

2) नव उदारवाद की विचारधारा का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 वैश्विक वित्तीय संरचना

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में वाटरशेड माना जाता है। इसने शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और मौद्रिक स्थिरता, वित्तीय सहायता और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों – राजनीतिक और आर्थिक – का निर्माण देखा। इसे लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर का जन्म कहा जाता है – ब्रेटन वुड्स संस्थानों का गठन, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता (जीएटीटी)। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सहयोग और सामूहिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस (बीडब्ल्यूआई) में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) (वर्ल्ड बैंक) मौद्रिक और वित्तीय सहयोग के लिए स्थापित किए गए थे। जबकि अमेरिका में स्थित आईएमएफ का उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं को मौद्रिक सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से संकट के समयय आईआरबीडी, अमेरिका में भी आधारित है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए सरकारों को उधार देता है।

एक तुलनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेदों के कारण नहीं चल सका। 1948 में, उदारवादी व्यापार प्रणाली के मानदंडों को प्रोत्साहित करने और बिछाने के लिए एक अंतरिम संधि के रूप में टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) पर सामान्य समझौता स्थापित किया गया था।

3.4.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

दोनों संस्थानों का जनादेश अलग–अलग है। हालांकि, आईएमएफ और विश्व बैंक सदस्य देशों की सहायता करने और कई पहलों पर एक साथ काम करने के लिए नियमित रूप से और कई स्तरों पर सहयोग करते हैं। आईएमएफ को आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर, 1945 को स्थापित किया गया था, जब ब्रेटन वुड्स में भाग लेने वाले 29 देशों ने अपने लेख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसने 1 मार्च 1947 को अपने वित्तीय संचालन की शुरुआत की। वर्तमान में, बहुपक्षीय संस्था में 189 सदस्य हैं।

आईएमएफ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा बनाने और प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई थी जो 1930 के दशक के महामंदी में योगदान देता था। इसका जनादेश और शासन वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ समय के साथ विकसित हुआ है, जिससे संगठन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला के भीतर केंद्रीय भूमिका बनाए रखने की अनुमति मिली है।

आईएमएफ के उद्देश्यः प्राथमिक उद्देश्य हैंः दुनिया भर में विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देनाय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिएय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिएय भुगतानों की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करनाय और भुगतान कठिनाइयों का संतुलन अनुभव करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना।

आईएमएफ 'कोटा' क्या है ?ः प्रत्येक सदस्य देश को एक कोटा सौंपा जाता है। कोटा मूल रूप से वह धन है जो किसी सदस्य देश को आईएमएफको देना होता है। किसी देश का कोटा जितना बड़ा होता है, उतना ही कहते हैं कि देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के संचालन में है। आईएमएफमें एक देश का कोटा निर्धारित करता हैः इसकी मतदान शक्तिय आईएमएफ को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों की मात्राय और आईएमएफ वित्तपोषण के लिए इसकी पहुंच का आकार।

कोटा कैसे तय किया जाता है?ः किसी देश का कोटा उसके आर्थिक महत्व पर निर्भर करता है। जब कोई देश आईएमएफ में शामिल होता है, तो उसे मौजूदा सदस्यों के कोटा के रूप में उसी श्रेणी में एक प्रारंभिक कोटा सौंपा जाता है जो आर्थिक आकार और विशेषताओं में व्यापक रूप से तुलनीय है।

कोटा जिस देश को सौंपा गया है उसका आकार या राशि एक सूत्र के माध्यम से तय की जाती है। सूत्र खाता कारकों को ध्यान में रखता है जैसे कि जीडीपी का आकार, आर्थिक खुलेपन और अंतरराष्ट्रीय भंडार जिनके पास देश है, आदि कहने के लिए पर्याप्त है, एक कोटा का मूल्य देश की विश्व अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव को इंगित करता है। सदस्य देश विदेशी मुद्रा या सोने के मिश्रण के माध्यम से और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में अपना कोटा देते हैं।

कोटा को विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में दर्शाया गया है, जो अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, रेनमिनबी और पाउंड स्टर्लिंग के मूल्य द्वारा निर्धारित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है।

आईएमएफ कोटा किस उद्देश्य से काम करता है?ः आईएमएफ कोटा कई उद्देश्यों की पूर्ति करता हैः (i) सदस्य द्वारा उद्धृत कोटा, आईएमएफ को प्रदान किए गए धन को इंगित करता है। इसलिए यह आईएमएफ के संसाधन आधार का गठन करता है। (ii) किसी देश का ऋण पात्रता उसके कोटा के आकार पर निर्भर करता है। असाधारण वित्तीय आकस्मिकता में, कोई देश अपने अधिकार से अधिक वित्त का उपयोग कर सकता है। (iii) कोटा का आकार किसी सदस्य की मतदान शक्ति निर्धारित करता है। सदस्यों के भारित मतदान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ;(iv) भारत का कोटा हिस्सा लगभग 2.76 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि इसका मतदान भार लगभग समान प्रतिशत होगा। अमेरिका को 16.54 प्रतिशत मतदान की शक्ति प्राप्त है। आईएमएफ नियम कहता है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय कम से कम 85 प्रतिशत वोटों

के साथ लिए जाने चाहिए। वास्तव में, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी निर्णय अमेरिका की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता है।

आईएमएफ कोटा सुधार क्या होता है?: कोटा फार्मूला समीक्षा के अधीन है। आखिरी समीक्षा 2016 में की गई थी। सुधारों ने आईएमएफ के 189 सदस्यों में से प्रत्येक का कोटा बढ़ा दिया है। बेशक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2017 में 16.52 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े कोटा को बनाए रखना जारी रखा है। कोटा सुधार ने आईएमएफ के समग्र वित्तीय संसाधन आधार को दोगुना कर दिया है। इन अतिरिक्त संसाधनों में से अधिकांश अतिरिक्त धन से आए हैं जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कई सदस्य देशों ने आईएमएफ में योगदान दिया था। कोटा सुधार (i) वित्तीय संकट के समय में जवाब देने के लिए आईएमएफ की वित्तीय शक्ति को बढ़ाते हैं; (ii) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ जैसे कि ब्राजील और चीन संस्था में बड़ा कोटा शेयरय (iii) कोटा शेयरों के पुनर्वितरण का मतलब है कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के पीछे छठे से तीसरे सबसे बड़े सदस्य देश में कूदता है। 6.09 प्रतिशत पर, चीन का कोटा हिस्सा 2 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है। 2017 में भारत की हिस्सेदारी 2.64 प्रतिशत, रूस की 2.59 प्रतिशत और ब्राजील की 2.22 प्रतिशत थी। (iv) जबकि सभी सदस्य देश बड़े कोटा प्राप्त करते हैं, उभरते हुए बाजार देश अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। सुधार कोटा बाजार में लगभग 6 प्रतिशत शेयर उभरते हुए देशों में स्थानांतरित हो जाते हैं। नतीजतन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों जैसी परंपरागत रूप से मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का कोटा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यह ज्यादा प्रभावित नहीं करता हैय ज्यादातर मामलों में कोटा की कटौती आधे फीसदी से भी कम है। सबसे गरीब सदस्य देशों का कोटा हिस्सा काफी हद तक अपरिवर्तित है।

वैश्विक वित्तीय वास्तुकला का सुधार लंबे समय के लिए आवश्यक माना गया था। आईएमएफ के शेयरधारकों ने निर्णय लिया कि (i) के सुधार के लिए सुधार आवश्यक थे ताकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रतिबिंबित किया जा सकेय और (ii) वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में IMF की वैधता को बढ़ावा देने के लिए। अपने निपटान में अधिक वित्त के साथ, यह आशा की जाती है कि आईएमएफ वित्तीय संकटों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देगा और वैश्विक वित्तीय स्थिरता में मजबूती से योगदान देगा।

IMF गवर्नेंस संरचना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कार्यकारी बोर्ड और मंत्री समितियों से बना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक राज्यपाल और एक वैकल्पिक राज्यपाल होता है। गवर्नर को सदस्य देश द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह आमतौर पर वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का प्रमुख होता है। आईएमएफका 24–सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड आईएमएफके दैनिक व्यवसाय का संचालन करता है और इसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, साथ ही उन शक्तियों को समझौते के लेख द्वारा प्रदान करता है। 2016 के सुधार यहां एक बदलाव लाते हैंः आईएमएफ के बोर्ड में कार्यकारी निदेशकों की चयन प्रक्रिया में बदलाव होता है। एक बार सुधार होने के बाद, सभी पदों को चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बजाय मौजूदा प्रचलित व्यवस्था के जहां सदस्य देश पांच सबसे बड़े कोटा प्रत्येक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करते हैं।

3.4.2 पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईआरबीडी) – (विश्व बैंक)

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के साथ आईआरबीडीको विश्व बैंक संगठन कहा जाता है। विश्व बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। आम तौर पर, आईएमएफ का प्रत्येक सदस्य देश आईआरबीडी का सदस्य बन जाता है। जब कोई देश आईएमएफको छोड़ता है, तो यह विश्व बैंक से स्वतः निष्कासित हो जाता है।

विश्व बैंक का जनादेश दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और विशेष क्षेत्रों में सुधार करने या विशिष्ट परियोजनाओं को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करना है। आईएमएफ के लिए, विश्व बैंक की अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ विश्व बैंक का जनादेश और शासन विकसित हुआ है। विश्व बैंक 189 सदस्य देशों से बना है। इन सदस्य देशों, या शेयर धारकों को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो विश्व बैंक में अंतिम नीति निर्धारक हैं। आमतौर पर, राज्यपाल सदस्य देशों के वित्त मंत्री या विकास के मंत्री होते हैं। वे विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में साल में एक बार मिलते हैं। शासन संरचना में अगला स्तर 25 कार्यकारी निदेशक हैं, जो बैंक में साइट पर काम करते हैं, और राज्यपाल उन्हें विशिष्ट कर्तव्यों को सौंपते हैं। पांच सबसे बड़े शेयरधारक एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करते हैं, जबकि अन्य सदस्य देशों को निर्वाचित कार्यकारी निदेशकों द्वारा दर्शाया जाता है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और बैंक के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति का चयन कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा पांच साल के लिए किया जाता है, अक्षय शब्द। कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक के निदेशक मंडल बनाते हैं। वे आम तौर पर बैंक के व्यवसाय की देखरेख के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार मिलते हैं, जिसमें ऋण और गारंटी, नई नीतियां, प्रशासनिक बजट, देश सहायता रणनीतियों और उधार लेने और वित्तीय निर्णय शामिल हैं। विश्व बैंक राष्ट्रपति, प्रबंधन और वरिष्ठ कर्मचारियों के नेतृत्व और निर्देशन और वैश्विक प्रथाओं, क्रॉस–कटिंग समाधान क्षेत्रों, क्षेत्रों और कार्यों के प्रभारी उपाध्यक्षों के नेतृत्व में दिन–प्रतिदिन काम करता है।

उनकी स्थापना के बाद, आईएमएफ और विश्व बैंक का पहला कार्य 1950 के दशक में कई विकासशील देशों के उप–उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में भाग लेना था। मुख्य कार्य इन विघटित देशों की मुख्यधारा की विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण था। इस स्थिति से निपटने के लिए, दोनों संस्थानों ने अपने दायरे का विस्तार किया और विश्व बैंक के दो संबद्ध संगठन बनाए। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहयोग (आईएफसी) की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य निजी संगठनों को क्रेडिट देना है जो विकासशील दुनिया में परियोजनाओं के लिए पूंजी की कमी है। 1961 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य कार्य विशेष रूप से गरीब देशों को बहुत अनुकूल परिस्थितियों में क्रेडिट देना है।

1960 और 1970 के दशक में पश्चिमी औद्योगिक देशों के बीच भुगतान के असंतुलन के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शासन का संकट पैदा हो गया। 1971 में अमेरिकी डॉलर के सोने की परिवर्तनीयता की आधिकारिक समाप्ति इस तरह के संकट का

तत्काल ट्रिगर थी। यह 1970 के दशक के तेल संकट से तीव्र था। ''ब्रेटन वुड्स की एक नई प्रणाली'' के लिए कॉल ने 1980 और 1990 के दशक में गति प्राप्त की, विशेष रूप से शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के पतन के मद्देनजर विश्व व्यवस्था के पुनर्गठन के कारण।

1997–1998 के एशियाई संकट के दौरान, दुनिया भर में लगभग सर्वसम्मति थी कि संकट को हल करने और संकट से निपटने के लिए संकटग्रस्त देशों की मदद करने के लिए आईएमएफ के साथ मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला इसके समाधान के लिए प्रभावी नहीं थी। वास्तव में, आईएमएफ पर संकट की गंभीरता को तेज करने का आरोप लगाया गया था। नतीजतन, कई एशियाई नीति निर्माताओं और पर्यवेक्षकों ने आईएमएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार के लिए प्रयास चल रहे थे जिसमें वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) की स्थापना शामिल थीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के राज्यपालों के लिए ट्वेंटी (जी –20) प्रक्रिया के एक नए समूह का निर्माणय सूचना पारदर्शिता और प्रकटीकरण में सुधारय अंतरराष्ट्रीय मानकों और कोड को अपनानेय बैंकिंग पर्यवेक्षण और इस तरह के अन्य पर बेसल समिति के माध्यम से मजबूत वित्तीय विनियमन। हालांकि, इस तरह के सुधार एक और संकट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 2008–09 का वैश्विक वित्तीय संकट, जिसने विकसित देशों को उलझा दिया, ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार पर चर्चा को नया रूप दिया। इस प्रकार, थ्ै को अधिक जनादेश और बड़ी सदस्यता के साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (थ्ठ) बनने के लिए विस्तारित किया गया है, और प्डथ् के वित्तीय संसाधनों को वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित देशों की सहायता के लिए पर्याप्त रूप से संवर्धित किया गया है। जैसा कि विश्व अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट से धीरे–धीरे वापस आती है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस (बीडब्ल्यूआई) के सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी है।

बीडब्ल्यूआईके वित्तीय शासन पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के कारण व्यापक सदस्यता के बावजूद, आईएमएफऔर विश्व बैंक दोनों की शासन संरचना हावी है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा। मतदान के शेयरों में वर्चस्व के अलावा, बीडब्ल्यूआईअपनी स्थापना के बाद से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्व में है। इस तिरछे प्रतिनिधित्व के प्रकाश में, विकासशील देश बीडब्ल्यूआई – विश्व बैंक और आईएमएफमें शामिल वित्तीय वास्तुकला के सुधार की मांग में सबसे आगे रहे हैं। इस तरह की मांगों को चलाने वाला मुख्य तर्क प्रतिनिधित्व के संदर्भ में विषमता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते आर्थिक प्रभाव को समायोजित करने में उनकी विफलता है। बढ़ते आर्थिक बंद इस तथ्य से स्पष्ट है कि विकासशील देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 1960 में 25ः से बढ़कर 2016 में 56ः हो गई और समान अवधि के लिए विकसित देशों की हिस्सेदारी 80ः से 44ः हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन, भारत और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का 25ः है। हालांकि मतदान शेयरों के संदर्भ में सुधारों पर 2010 में सहमति हुई थी, इसे अंततः 2016 में लागू किया गया था, खासकर अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदन में देरी के कारण।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) आईएमएफ का जनादेश क्या है? आईएमएफ की कोटा प्रणाली और एसडीआर का वर्णन करें।

2) विश्व बैंक की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 सारांश

वैश्विक अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अंतर–आर्थिक आर्थिक गतिविधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक दूसरे पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि राजनीति के साथ अर्थशास्त्र के प्रतिच्छेदन के रूप में समझा जा सकता है। राज्य और अन्य राजनीतिक गतिशीलता उत्पादन और वितरण के मुद्दों को आकार देते हैं। अर्थशास्त्र और राजनीति का यह परस्पर संबंध हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार और कार्य को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने में राज्य और बाजार के सापेक्ष प्रभाव को रॉबर्ट गिलपिन ने अच्छी तरह से समझा है। उनका मानना है कि राज्य और अन्य राजनीतिक ताकतें उत्पादन और वितरण से संबंधित फैसलों को आकार देती हैं और विशेष रूप से ''... राजनीतिक फैसले और हित आर्थिक गतिविधियों के स्थान और इन गतिविधियों की लागत और लाभों के वितरण को प्रभावित करते हैं।''

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई और व्यापारिकता (1500–1750) की उम्र में वृद्धि हुई जब यूरोप के भीतर व्यापार में वृद्धि हुई और दूसरे, यूरोप ने बड़े पैमाने पर और अन्य महाद्वीपों के साथ व्यवस्थित तरीके से व्यापार करना शुरू किया। यह 'खोज की आयु' और 'वैज्ञानिक क्रांति' थी जिसने वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद दोनों को प्रेरित किया। यह समझा जाना चाहिए कि मजबूत राष्ट्रीय राज्यों और विश्व बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के तत्वावधान में व्यापारिकता को बल मिला।

मर्केंटीलिज्म कुछ मान्यताओं और प्रथाओं पर आधारित थाः सोने और अन्य कीमती धातुओं को राज्य के धन का संकेतक माना जाता था। आयात से अधिक निर्यात एक राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। व्यापारीवादी युग में राजनीतिक लक्ष्य सरल और सीधा थाः एक शक्तिशाली और धनी राज्य जो एक शानदार सम्राट के अधीन था। व्यापारीवाद के तहत, पैसा खरीदने और बेचने का माध्यम बन गया। बड़े वित्तीय परिवार और नौकरशाही वैश्विक व्यापार का प्रबंधन करने के लिए उभरेय तो राष्ट्रीय सेनाओं ने

किया। ''इन सभी कारकों ने यह सुनिश्चित किया कि बढ़ती देर से मध्ययुगीन और शुरुआती आधुनिक राज्यों ने एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में व्यापारीवाद को गले लगाया, जिसने उन्हें इन स्थानांतरण संरचनाओं का दोहन करने की तलाश करने की अनुमति दी'' (स्रोतः ''यूरोप, 1450 से 1789'', प्रारंभिक का विश्वकोश आधुनिक दुनियाँ)।

1780 के आसपास औद्योगिक क्रांति के प्रकोप के साथ मर्कैंटिलिस्ट की उम्र समाप्त हो गई। औद्योगिक क्रांति का जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, इसने उत्पादन और उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि की, और इस प्रकार प्रति व्यक्ति धन में वृद्धि हुई। प्रमुख औद्योगिक परिवर्तनों के आधार पर, समाज बदल गया। दो नई कक्षाएं, अर्थात। पूंजीपति और मजदूर वर्ग उभरे। एक मध्यम वर्ग भी उभराय कर का भुगतान करने वाले लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वैज्ञानिक ज्ञान का भी विस्तार हुआ। अपने सेमिनरी कार्य द वेल्थ ऑफ नेशंस में, एडम स्मिथ ने निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिकीकरण सभी के लिए धन में वृद्धि करता है। इस प्रकार उन्होंने दो व्यापारिक मान्यताओं को खारिज कर दियाः धन की सीमाएँ हैंय और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हो सकती है। दूसरे शब्दों में, धन और व्यापार के निर्माण की कोई ऊपरी सीमा नहीं हो सकती है। एडम स्मिथ ने मुक्त बाजार पूंजीवाद के समर्थन में लिखा। उन्होंने आधुनिक उद्योगों को श्रम विभाजन के आधार पर काम करते देखा। उन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन कारखानों को अपने श्रमिकों के उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के पास अपने स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक ड्राइव है। यह स्व–हित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके बाजारों को व्यक्तिगत मांगों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इसे 'अदृश्य हाथ' कहा। लाईसेज पितम में विश्वास मूल शास्त्रीय उदारवाद पर था।

19वीं शताब्दी के अंत तक, औद्योगिक क्रांति के कई नकारात्मक परिणाम थेः आर्थिक असमानता, गरीबी और अज्ञानता। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय चक्र थाः पूंजीवाद बूम–एंड–बस्ट चक्र के लिए प्रवण था। 19 वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में शास्त्रीय उदारवाद में विश्वास कम होने लगा। घटनाओं से यह साबित हुआ कि लॉज फेयर का सिद्धांत कोई जादू की छड़ी नहीं थी। बाजार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की मान्यता एक मिथक थी। यह स्थापित किया गया था कि जिस तरह से बाजार की अर्थव्यवस्था काम करती है, वह ठहराव के आवधिक मुकाबलों का उत्पादन करेगी।

ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक टी। एच। ग्रीन ने कहा कि आय असमानता और कम वेतन जैसी चीजें किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का आनंद लेने से रोकती हैं। इन स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सकारात्मक सहायता आवश्यक है। आधुनिक उदारवादियों ने तर्क दिया कि बाजार के संचालन को पूरक और सही करने की आवश्यकता है। उन्होंने बाजार और राज्य के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया।

20 वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी दो बड़ी घटनाएं थीं, जिसने सामग्री और नैतिक प्रगति को बाधित किया था, आधुनिक उदारवादियों ने वकालत की थी। आलोचकों ने कहा कि पूंजीवाद बूम–एंड–बस्ट चक्रों से गुजरता है। व्यापार चक्र बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन असामान्य रूप से लंबा और विनाशकारी साबित हुआ था। व्यापक बेरोजगारी, श्रम और

सामाजिक अशांति और कट्टरपंथी विचारों के प्रसार जैसे बोल्शेविक क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति दोनों को खतरे में डाल दिया।

जॉन मेनार्ड कीन्स ने सिद्धांत दिया कि अर्थव्यवस्था का सरकारी प्रबंधन व्यवसाय चक्र के उच्च और चढ़ाव को सुचारू कर सकता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। न्यूनतम बेरोजगारी और मजदूरी के सभ्य स्तर के साथ अधिक या कम सुसंगत विकास का उत्पादन करने के लिए राज्य विनियमन और हस्तक्षेप आवश्यक है। केनेसियन विचारों का प्रभाव उदार पूंजीवादी देशों में व्यापक था। एक उदार अर्थशास्त्री, उनके विचारों का आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ–साथ बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में गहरा प्रभाव पड़ा।

1945 की अवधि ने लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के उद्भव को चिह्नित किया – ब्रेटन वुड्स संस्थानों का गठन, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता (जीएटीटी)। ब्रेटन वुड्स संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) (विश्व बैंक) मौद्रिक और वित्तीय सहयोग के लिए स्थापित किए गए थे। व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता (गैट), जो एक संधि के रूप में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सरकारों को संरक्षणवादी उपायों का सहारा लेने से रोकने के लिए एक शासन की स्थापना करना था।

1970 के दशक ने नवउदारवाद के युग के उदय को चिह्नित किया। नवउदारवाद एक विशिष्ट विचारधारा हैय हालांकि यह कुछ ऐतिहासिक समानताएं और उदारवाद के साथ कुछ बुनियादी शब्दावली साझा करता है। नवउदारवाद के उदय ने राज्य में विश्वास के एक ग्रहण को चिह्नित किया। मिल्टन फ्रीडमैन जैसे नवउपनिवेशक, मौद्रिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो राज्य की किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका को छूट देते हैं। यह विचार कि बाजार स्व–नियमन कर रहे हैं, नवउपनिवेशकों की मान्यताओं के केंद्र हैं। नियोलिबरल्स का कहना है कि संसाधनों का कुशल आवंटन एक आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैय और संसाधनों को आवंटित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका बाजार तंत्र है।

नवउदारवाद ने आर्थिक विकास के बारे में धारणा बदल दी है। आईएमएफ, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने आर्थिक विकास के नवउदारवादी रास्ते का समर्थन किया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने इसे लंबे समय तक बनाए रखा है और इसे विकासशील देशों में सहायता और सहायता, ऋण पुनर्गठन और बाजार पहुंच आदि की नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया है। संक्षेप में, नवउपनिवेशवाद एक विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत के रूप में सामने आता है जिसने हाल के दिनों में कीपियन किस्म की जगह ले ली है। आधुनिक उदारवाद। वास्तव में, नवउदारवाद के बारे में कुछ भी उदार नहीं है। विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव प्रगति के आदर्शों से बहुत दूर है। 20 वीं शताब्दी के कुछ सबसे बुरे सत्तावादी शासन ने नवउपनिवेशवाद का अभ्यास किया, उदा। चिली (1973–1989) में ऑगस्टो पिनोचेत शासन। नवउदारवाद अधिक राजनीतिक और आर्थिक प्रथाओं का एक सेट है जो निजी आर्थिक बलों के आसपास केंद्रित है।

3.6 संदर्भ ग्रंथ

बॉटन, जेम्स एम. (2009), ''ए न्यू ब्रेटन वूड्स?'', *फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट*, मार्च 2009, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/03/pdf/boughton.pdf

कोहेन, बेंजामिन जे. (2011), ''इंट्रोडक्शन'' इन बेंजामिन, जे. कोहेन, ऐडिटेड, *इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी*, न्यू यॉर्क : रूटलेज।

कॉक्स, आर. डब्ल्यू (1981), ''सोशल फोर्सेज, स्टेट्स एण्ड वर्ल्ड ऑर्डर्स : बियॉण्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी'' *मिलेनियम : जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज*, वॉल्यूम 10, 1981

डैमेश, सैबाइन, ''दि सिस्टम ऑफ ब्रेटन वूड्स : ए लेसन फ्रॉम हिस्ट्र?'', http://www.ww.uni-magdeburg.de/fwwdeka/student/arbeiten/006.pdf

गिप्लिन, रॉबर्ट (1987), *दि पॉलिटिकल इकोनॉकी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस*, न्यू जर्सी : प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

गिप्लिन, रॉबर्ट (2001), *ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉकी : अण्डरस्टैंडिंग दि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर*, न्यू जर्सी : प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

ग्रे, जॉन (1995), *लिबर्लिज्म*, बकिंघम : ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस।

हॉब्सबॉन, ऐरिक (1996), *दि एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1789–1848*, न्यू यॉर्क : विंटेज।

होपवैल, क्रिस्टन (2016), *ब्रेकिंग दि डब्ल्यूटीओ : हाउ इमर्जिंग पावर्स डिस्रप्टेड दि नियो–लिबरल प्रोजेक्ट*, कैलीफोनिर्या : स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

आईएमएफ (2018), ''फैक्टशीट : दि आईएमएफ एण्ड दि वर्ल्ड बैंक'', http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank

आईएमएफ (2018), ''आईएमएफ कोटाज'' एण्ड ''स्पेशल ड्राइंग राइट (एसडीआर)'',''..http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-Quotas&http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR

आईएमएफ (2018), ''गवर्नेंस स्ट्रक्चर'', http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm

आईएमएफ (2017), ''कोटा एण्ड वोटिंग शेयर्स बिफोर एण्ड आफ्टर इम्पिलिमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स'', http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf

आईएमएफ (2017), ''आईएमएफ मेम्बर्स' कोटाज एण्ड वोटिंग पावर एण्ड आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स'', http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx

मोहन, राकेश एण्ड मुनीश कपूर (2015), ''इमर्जिंग पावर्स एण्ड दि ग्लोबल गवर्नेंस : व्हिदर दि आईएमएफ?'', आईएमएफ वर्किंग पेपर नं.डब्ल्यूपी/15/219, http://www.imf.org /external/pubs/ft/wp/2015/wp15219.pdf

ओज़्कन, गोखन (2012), ''इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐज ए सब–डिस्सिप्लीन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एण्ड इम्पैक्ट ऑफ दि ग्लोबल क्राइसेज ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी'', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड सोशल साइंस*, वॉल्यूम–3, नं.3, जुलाई, पीपी.198–204

पॉल, डैरेल ई. एण्ड अब्ला आमावी, (ऐडिटर्स), (2013), *दि थियरेटिकल इवॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी : ए रीडर,* न्यू यॉर्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

रियान, ऐलन (1993), ''लिबरलिज्म'', पीपी.291–311 इन रॉबर्ट ई. गुड एण्ड फिलिप पेट्टी ऐडिटर्स, *ए कम्पैनियन टू कंटेम्पोररी पॉलिटिकल फिलोसफी,* ऑक्सफोर्ड : ब्लैकवैल।

रिंगमैर, ऐरिक (2017), ''दि मेकिंग ऑफ दि मॉर्डन वर्ल्ड'', इन स्टीफेन मैकग्लिंचे, ऐडिटेड *इंटरनेशनल रिलेशंस,* ब्रिस्टल : इ–इंटरनेशनल रिलेशंस पब्लिशिंग।

थॉरसेन, डैग ईनैर एण्ड ऐमुण्ड ली (2009), *व्हाट इज नियोलिबरलिज़्म?* वर्किंग पेपर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, www.folk.uio.no/daget/neoliberalism.pdf

वालज़ेंबैक, गुण्टर (2017), ''ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी'' इन स्टीफेन मैकग्लिंचे, ऐडिटेड *इंटरनेशनल रिलेशंस,* ब्रिस्टल : इ–इंटरनेशनल रिलेशंस पब्लिशिंग।

वर्ल्ड बैंक (2018), ''ऑर्गेनाइजेशन'', http://www.worldbank.org/en/about/leadership

3.7 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए:

- व्यापारीवाद की प्रथा एवं व्यवहार
- औद्योगिक क्रांति का आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रभाव।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए:

- जॉन मेनार्ड केन्स के विचार और उन्होंने राज्य की भूमिका पर क्यों और कैसे ध्यान केंद्रित किया।
- संसाधन आवंटन में बाजार की प्रभावकारिता में नवउदारवाद की विचारधारा और उसके विश्वास का परिसीमन।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए:

- आईएमएफ का जनादेश, कोटा की कार्य प्रणाली और एसडीआर।
- विश्व बैंक की संगठनात्मक संरचना और कार्य प्रणाली।

इकाई4 वैश्विक व्यापार व्यवस्था (डब्ल्युटीओ एवं अन्य)

संरचना

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)

4.3 जेनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऐंड ट्रेड (गैट)

4.3.1 उरुग्वे राउंड, 1986 – 1993

4.3.2 दोहा राउंड

4.4 विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत, कार्य और तंत्र

4.4.1 व्यापार प्रणाली के सिद्धांत

4.4.2 विश्व व्यापार संगठन के कार्य

4.4.3 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एवं अन्य संगठन

4.4.4 विवाद समाधान

4.5 गैट, विश्व व्यापार संगठन और विकासशील दुनिया

4.6 विश्व व्यापार संगठन और भारत

4.7 लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर (एलआईईओ) का संकट

4.8 सारांश

4.9 संदर्भ ग्रंथ

4.10 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस इकाई में, आप वैश्विक व्यापार प्रणाली – संस्थानों और प्रक्रियाओं के बारे में पढेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आपको सक्षम होना चाहिए:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर (एलआईईओ)की स्थापना को समझना और उस पर चर्चा करने में,
- जेनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ऐंड ट्रेड (गैट) के महत्व और योगदान का विश्लेषण करने में,
- विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों, कार्यों, तंत्र और संस्थाओं की व्याख्याकरने में,
- वैश्विक व्यापार प्रणाली का विकासशील दुनिया के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मूल्यांकन करने में,
- विश्व व्यापार संगठन और भारत को समझने और उसका विश्लेषण करने में।

4.1 प्रस्तावना

यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी उत्पत्ति के समय से ही व्यापार कर रहा है। व्यापार का अर्थ है खरीदना और बेचनाय या, वस्तुओं और सेवाओं का आदान–प्रदान। व्यापार की शुरुआत तब हुई जब कुछ संसाधन और वस्तु स्थानीय स्तर पर या विशिष्ट समाजों में उपलब्ध नहीं होते थेय और इसलिए उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता था। जैसे–जैसे समाज का विस्तार हुआ और एक–दूसरे के संपर्क में आए, व्यापार आर्थिक संचार का मूल रूप बन गया। अक्सर यह व्यापार ही होता है जो विभिन्न लोगों को सामान और सेवाओं की खरीद और बिक्री के उद्देश्य से एक साथ लाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास, सिल्क रोड पर व्यापार शुरू हुआ। चीन से यूरोप में बेचे जाने वाले विलासिता के सामानों को सिल्क रोड से हजारों मील तक ले जाया जाता था। लगभग 7 वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप तक पश्चिम एशिया और अफ्रीका के माध्यम से मसालों का व्यापार समुद्री मार्ग से शुरू हुआ। निर्यात–जीडीपी अनुपात के संदर्भ में सिल्क रोड के माध्यम से किया जाने वाला व्यापार और मसाले का व्यापार दोनों ही काफी कम थे। व्यापार का अर्थ यूरोपीय अभिजात वर्ग के लिए अनिवार्य रूप से विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति करना था। शायद, यह कहा जा सकता है कि यही वैश्विक व्यापार की शुरुआत थी।

व्यापारीकरण के युग में आधुनिक व्यापार प्रणाली 16 वीं शताब्दी में शुरु हुई। व्यापारिकता के युग में व्यापार दो सिद्धांतों से निर्देशित होते थेः किसी देश को अमीर होने के लिए यह आवश्यक है कि वह आयात से अधिक निर्यात करे। दूसरे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को आकार देने के लिए एक मजबूत राज्य या शक्तिशाली सम्राट की आवश्यकता होती है। यह एक सच्चाई हैः एक मजबूत राज्य ही व्यापार को संभव बनाता है।

तकनीकी खोजों द्वारा व्यापार की सुविधा थी। औद्योगिक पूंजीवाद के युग में, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में उच्च स्तर की उत्पादकता और आपसी प्रतिस्पर्धा थी। इसने कारण उन्होंने बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया और उपनिवेशों और अन्य विदेशी बाजारों से कच्चे माल का आयात किया। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की वकालत करते थे। उदाहरण के लिए, जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। स्मिथ ने तर्क दिया कि एक उदार व्यापार प्रणाली जो तुलनात्मक लाभ और श्रम के विभाजन के सिद्धांतों पर काम करती है, सर्वांगीण समृद्धि और शांति पैदा करती है। उन्होंने यूरोप के औद्योगिक देशों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच श्रम का एक अंतर्राष्ट्रीय विभाजन देखा।

लगभग चार शताब्दियों तक, यूरोप वैश्विक व्यापार पर हावी रहा। जीडीपी के अनुपात में व्यापार में वृद्धि हुई। जैसे–जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ, व्यापार के मानदंड और नियम भी बनाए गए। मुद्रा मानकों, और वजन, माप और सिक्के के क्षेत्र में मानकों से संबंधित नियम तैयार किए गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दुनिया के सभी पैसे और पूंजी बाजार में सोने के मानक का सिद्धांत पेश किया। इन व्यापार संबंधी मानदंडों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थिरता दी। हालांकि कुछ ने इसका पालन नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न की।

प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी दो प्रलयकारी घटनाएँ थीं, जिसने पिछली शताब्दियों में विकसित हुई उदार व्यापार प्रणाली को नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद, यह भी स्पष्ट हो गया कि वैश्विक व्यापार की धुरी यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो अमेरिका ने उदार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक, वित्तीय और व्यापार व्यवस्था के बिना, सभी मुक्त बाजार के सिद्धांतों पर आधारित थे, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बार फिर से मंदी और संरक्षणवाद में जाने का गंभीर खतरा था। जॉन मेनार्ड कीन्स ने महसूस किया कि युद्ध के वर्षों के दौरान यूरोपीय देशों ने आर्थिक मंदी से बचने के लिए अपने पड़ोसी देशों से व्यापार की नीति का अनुसरण किया। देशों ने संरक्षणवाद का सहारा लिया, प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन में लिप्त रहे ताकि उनके निर्यात में वृद्धि हो सके और अन्य देशों से आयात को रोकने के लिए टैरिफ की दीवारें खड़ी की जा सकें। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो दो चुनौतियां थींः पहली यह कि अंतरराष्ट्रीय शांति कैसे स्थापित की जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि फिर कोई विश्व युद्ध न हो। दूसरे, एक वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक प्रणाली स्थापित करनामित्र राष्ट्रों के लिए एक चुनौती थी, जिससे युद्ध के दौरानकी विनाशकारी आर्थिक और व्यापार नीतियों से बचा जा सके। यूरोप और अमेरिका के आर्थिक पुनर्निर्माण में कीन्स के लेखन और नीतिगत नुस्खों का बहुत प्रभाव था। सबसे महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट था कि पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज को कारगर बनाने के लिए कुछ तर्कसंगत आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है। घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हुए, कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था का सरकारी प्रबंधन व्यवसाय चक्र के उतार और चढ़ाव, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है को सुचारू कर सकता है। न्यूनतम बेरोजगारी के साथ सुसंगत विकास के लिए राज्य विनियमन और हस्तक्षेप आवश्यक होता है।

22 जुलाई 1944 को, सभी 44 मित्र राष्ट्रों के करीब730 प्रतिनिधियों ने न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में ब्रेटन वुड्स से मुलाकात की और मौद्रिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईएमबीआरडी), और विकास में वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक की स्थापना की। आईएमएफ विश्व इतिहास में पहली पूर्ण रूप से बातचीत की गई मौद्रिक व्यवस्था थी। आईएमएफ और विश्व बैंक की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) के निर्माण पर आम सहमति नहीं बन पाई। आईटीओ की अनुपस्थिति में, अमेरिका ने 1948 में जेनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) पर नेतृत्व और सामान्य समझौता किया – एक उदारीकृत व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिम समझौते का एक प्रकार।

लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर (LIEO) घरेलू स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के बीच समझौता करने का एक प्रयास था। ब्रेटन वुड्स संस्थानों ने राज्यों को घरेलू आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने में स्वायत्तता की अनुमति दी क्योंकि ये बहुत ही संस्थान अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक विनियमन और प्रबंधन प्रदान करेंगे ताकि स्थिरता और मुक्त व्यापार प्राप्त हो सके। किसी ने इसे ''अंतर्निहित उदारवाद के समझौते'' के रूप में वर्णित किया। LIEO में अंतर्निहित आम सहमति थीः 'घर पर कीन्स और विदेशों में स्मिथ।'

4.2 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) 15 जनवरी 1994 को 124 देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। यह एक अंतर–सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच व्यापार करने के लिए शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना है। इसके गठन के साथ, डब्ल्यूटीओ ने टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) पर सामान्य समझौते की जगह ली, जिसने 1948 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए काम किया था। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। राज्यों के अलावा, यूरोपीय संघ भी एक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को केवल स्वतंत्र राज्य होने की आवश्यकता नहीं हैय सीमा शुल्क यूनियनों को अपने बाहरी व्यापार संबंधों का संचालन करने की स्वतंत्रता के साथ सदस्यता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माल, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में होता है। विश्व व्यापार संगठन तीनों को नियंत्रित करता है। डब्ल्यूटीओ देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र कार्य करने वाले न्यायाधीशों द्वारा व्यापार संबंधी विवादों के समाधान का भी प्रावधान है। यह विचार है कि सदस्य देश व्यापार समझौतों का पालन करते हैंय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भेदभाव से मुक्त रहने दें। विश्व व्यापार संगठन पर्यावरणीय संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी अन्य वजनी कारण के कारण सदस्य देशों के अलावा व्यापार में भेदभाव पर रोक लगाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण से पता चलता है कि विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। अगर डब्ल्यूटीओ नहीं होता, तो औसतन किसी देश को अपने निर्यात पर 32 प्रतिशत अंकों से अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ता। यह भी नोट किया गया है कि देश और समूह जब वे आपस में व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं तो अक्सर डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन करते हैं और डब्ल्यूटीपी के कई प्रमुख प्रावधानों की नकल करते हैं। दूसरे शब्दों में, डब्ल्यूटीओ ने अंतर–राज्य व्यापार के मानदंडों और मूल्यों के मानकीकरण में योगदान दिया है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट)

दो बहुपक्षीय संस्थानों आईएमएफ और विश्व बैंक को मौद्रिक और वित्तीय सहयोग के लिए सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। एक तुलनीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के निर्माण पर हालांकि कोई समझौता नहीं किया जा सका। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट) 1947 में 23 देशों की बहुपक्षीय संधि द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक अंतरिम समझौते की तरह थाय एक व्यापार संगठन की कृतियों की ओर एक कदम पत्थर। इन वर्षों में, गैटधीरे–धीरे व्यापार से निपटने के लिए एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। उस संबंध में, यह कहा जाता है कि गैटविश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है।

यह आश्चर्यजनक है कि गैटएक अर्ध–संस्थागत बहुपक्षीय संधि है, जो अनंतिम आधार पर लगभग आधी सदी तक काम करती रही। देशों ने दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में कठिन तरीके से अपने सबक सीखे थेय कोई भी देश संरक्षणवाद, प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन और उच्च आयात शुल्क पर वापस नहीं जाना चाहता था। प्रत्येक देश स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों के तहत मुक्त और निष्पक्ष व्यापार चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बातचीत और सहमति के कई विषय और मुद्दे हैंय उदाहरण के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में व्यापारय कृषि में व्यापारय सब्सिडीय विरोधी डंपिंगय सेवाओं में व्यापार आदि प्रत्येक विषय कठिन वार्ताओं के माध्यम से होता हैय जाहिर है, मानदंड विषय से अलग विषय पर सहमत हुए। अब तक सात प्रमुख विषयों पर बातचीत की जा चुकी है। प्रत्येक विषय पर चर्चा को दौर कहा जाता है। पहले गैटव्यापार दौर ने टैरिफ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया था। 1960 के दशक में, कैनेडी राउंड ने दूसरों के बीच एक एंटी–डंपिंग समझौता किया। 1970 के दशक में टोक्यो राउंड के तहत मुख्य विषय पर बातचीत गैर–टैरिफ बाधाओं में से थी। एक गुदगुदाने वाला मुद्दा, हर देश गैर–टैरिफ बाधाओं पर नए निर्धारित मानदंडों से सहमत नहीं था। ऐसे कई विषय हैं जो बातचीत के लिए बहुत जटिल हैंय वे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच विभाजन का कारण बनते हैंय या विषय जो सबसे कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरणों में सरकारी खरीद, डेयरी उत्पादों में व्यापार आदि शामिल हैं।

आइए हम संक्षेप में दो प्रमुख दौर की चर्चा करते हैं। उरुग्वे दौर और दोहा दौरः

4.3.1 उरुग्वे दौर, 1986–1993

यह गैट फ्रेमवर्क के तहत बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का 8 वां दौर था। उरुग्वे दौर गैटव्यापार नियमों को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर सहमत हुआ जो तब तक बातचीत से मुक्त थेय वे ऐसे विषय पाए गए जो या तो बहुत कठिन थे या बातचीत के लिए बहुत संवेदनशील थे। उदाहरण के लिए, प्रत्येक देश कृषि में व्यापार के उदारीकरण के लिए सहमत नहीं होगाय इसी तरह बौद्धिक संपदा पर बातचीत करना आसान नहीं है। इसके अलावा, वार्ता के अंत में, 123 ''अनुबंध दलों'' ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की।

उरुग्वे दौर के मुख्य उद्देश्य थेः कृषि सब्सिडी को कम करनाय विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाने के लिएय बैंकिंग और बीमा जैसी सेवाओं में व्यापार खोलने की प्रक्रिया शुरू करना; और बौद्धिक संपदा के संरक्षण को शामिल करना। यह वास्तव में अपने

दायरे में बहुत महत्वाकांक्षी और विस्तारक थाय और गैट के तहत लगभग हर दूसरे नियम को प्रभावित किया। 1995 में उरुग्वे दौर 2000 के अंत में, और विकासशील देशों के लिए 2004 में समाप्त हुआ।

यह राउंड सितंबर 1986 में पुंटा डेल एस्टे, उरुग्वे में लॉन्च किया गया था। बाद के वर्षों में जिनेवा, ब्रूसेल्स, वाशिंगटन, डीसी और टोक्यो में बातचीत जारी रही। अंत में, अप्रैल 1994 में मारकेश में 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मारकेश समझौते ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, जो 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ। अंततः 1947 के बाद से यह विश्व व्यापार प्रणाली का सबसे गहरा संस्थागत सुधार था। गैट की स्थापना हुई।

माल में व्यापार के लिए डब्ल्यूटीओ की छत्र संधि के रूप में गैट जारी है। उरुग्वे दौर के परिणामस्वरूप छह प्रमुख भागों के साथ एक व्यापक संधि हुईः (i) एक छाता समझौता जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करता हैय (ii) माल और निवेश पर समझौता। यह माल में व्यापार पर बहुपक्षीय समझौते और व्यापार से संबंधित निवेश उपाय (ट्रिम्स) है; (iii) सेवाएँ (जनरल इन ट्रेड ऑन सर्विसेज (गैट)); (iv) बौद्धिक संपदा (बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार–संबंधित पहलुओं पर समझौता)य विवाद निपटारा (DSU); और, सरकारों की व्यापार नीतियों (टीपीआरएम) की समीक्षा।

उरुग्वे दौर दोनों विकसित और विकासशील देशों द्वारा बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने में सफल रहा है। प्रतिशत के मामले में शुल्क गिर गया है। हालांकि, विकासशील दुनिया की जरूरतों और हितों का ध्यान नहीं रखने के लिए उरुग्वे दौर की भी आलोचना की गई है। यह मैंने कहा कि विकसित ने एक व्यापारी दृष्टिकोण अपनाया है। अपनी शिकारी निर्यात नीतियों के लिए विकासशील देश के बाजार खोलने के लिए। इसके अलावा, बौद्धिक संपदा पर समझौता बुनियादी मानवीय जरूरतों के लिए असंवेदनशील रहा है और विकासशील देशों पर प्रौद्योगिकी और पता करने के लिए अनुचित प्रतिबंध लगाए हैं।

4.3.2 दोहा दौर

विश्व व्यापार संगठन ने 2001 में अपने चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दोहा दौर की वार्ता शुरू की। दोहा विकास दौर वैश्वीकरण को एक समावेशी शक्ति बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास हैय और कृषि सब्सिडी और अन्य बाधाओं को दूर करके दुनिया के गरीबों की मदद करना। दोहा दौर ने नए नियमों को बनाने के अलावा व्यापार उदारीकरण की परिकल्पना की ताकि गरीब देशों को राहत मिल सके।

दोहा विकास दौर रुका हुआ हैय और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास विफल रहे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका कृषि निर्यात विकासशील देशों के खिलाफ अपनी कृषि सब्सिडी और अन्य व्यापार विकृत प्रथाओं को रखना चाहते हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और अमेरिका भी एक दूसरे के खिलाफ कृषि सब्सिडी बनाए रखते हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच औद्योगिक टैरिफ और व्यापार के लिए गैर–टैरिफ बाधाओं जैसे मुद्दों पर मतभेद हैं। अमीर देश अपने विनिर्माण और सेवाओं के लिए विकासशील देशों के बाजारों तक पूरी पहुंच चाहते हैं। साथ ही, वे अपने किसानों के लिए कृषि सब्सिडी को बनाए रखना चाहते हैं, जो प्रभावी रूप से व्यापार बाधाओं के रूप में काम करती हैं। दोहा में अमेरिका ने ब्राजील और भारत को घुसपैठ के लिए

जिम्मेदार ठहरायाः अमेरिका ब्राजील के कृषि निर्यात के लिए अपना घरेलू बाजार नहीं खोलना चाहताय इसी समय, यह चाहता है कि भारत अमेरिकी अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के लिए अपना घरेलू बाजार खोले। यह इस कारण से है कि 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में दोहा दौर को पुनर्जीवित करने का प्रयास विफल रहा।

रुका हुआ दोहा दौर डब्ल्यूटीओके काम में एक गतिरोध है। कुछ संशयवादियों का कहना है कि डब्ल्यूटीओ दोषपूर्ण हो गया है। इसके अलावा एक प्रवृत्ति देखी गई हैः विकसित देश डब्ल्यूटीओ को दरकिनार कर रहे हैं और डब्ल्यूटीओ प्रणाली के बाहर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) गैट से डब्ल्यूटीओ के उद्भव की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4.4 विश्व व्यापार संगठन मूल्य, सुविधाएं और तंत्र

डब्ल्यूटीओ ने गैट के तहत बनाए गए कई व्यापार नियमों को प्राप्त किया हैय इसने व्यापार से जुड़े कई नियमों को भी तैयार किया है ताकि वैश्विक व्यापार को पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनाया जा सके। देश व्यापार मामलों पर बातचीत करते हैं; लेकिन विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान के लिए महत्वपूर्ण कार्यों सहित स्कोर का प्रदर्शन करता है। डब्ल्यूटीओ विभिन्न तंत्रों और अंगों के साथ निरंतरता में एक अभ्यास है जो नीति मार्गदर्शक, विस्तृत अध्ययन और रिपोर्ट और सिफारिशें दोनों करता है।

4.4.1 व्यापार तंत्र के सिद्धांत

डब्ल्यूटीओ व्यापार नीतियों के लिए रूपरेखा तय करता है यानी सदस्यों के बीच व्यापार वार्ता के लिए कुछ बुनियादी नियमों का पालन करता है। यह व्यापार के दौर के परिणाम को नियंत्रित नहीं करता है। गैट ने कुछ सिद्धांतों पर काम किया, जो डब्ल्यूटीओ के कामकाज में शामिल किए गए। डब्ल्यूटीओ के काम को निर्देशित करने वाले पांच प्रमुख सिद्धांतों की पहचान कर सकते हैंः

1. गैर–भेदभावः गैर–भेदभाव का सिद्धांत माल, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार पर डब्ल्यूटीओ के नियमों में शामिल है। विश्व व्यापार को दो बुनियादी मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसमें सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) और राष्ट्रीय उपचार नीति शामिल हैं। एमएफएन के लिए आवश्यक है कि एक सदस्य

देश एक निश्चित उत्पाद में सभी को सबसे अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करेगाय और भेदभाव के साथ कोई नहीं। एक बार एक आयातित उत्पाद एक बाजार में प्रवेश करने के बाद, इसे घरेलू रूप से उत्पादित अच्छे के रूप में अनुकूल माना जाता है। गैर–टैरिफ आधार पर कोई भी भेदभावपूर्ण उपचार जैसे कि सुरक्षा मानक, तकनीकी मानक इत्यादि असंगत है।

2. पारस्परिकताः पारस्परिकता के सिद्धांत का अर्थ है कि किसी को एमएफएनकी आड़ में बाजार तक पहुंचने का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। व्यापार में कोई मुफ्त सवारी नहीं है। एक समझौता किए गए समझौते से लाभ एकतरफा उदारीकरण से अन्यथा प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक होना चाहिए। पारस्परिक रियायतें मतलब यह है कि लाभ भौतिक हो जाता है और सभी पक्षों द्वारा समझौते के लिए उत्सुकता से मांग की जाती है।

3. बाध्यकारी और लागू करने योग्य प्रतिबद्धताः सदस्यों को वार्ता के दौरान किए गए टैरिफ प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। इन प्रतिबद्धताओं पर किसी भी गिरावट पर व्यापारिक भागीदारों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। साझेदारों को आमतौर पर खोए हुए व्यापार के लिए मुआवजा दिया जाता है। व्यापार साझेदारों के बीच कोई असहमति डब्ल्यूटीओ विवाद समाधान के लिए एक उपयुक्त मामला है।

4. पारदर्शिताः पारदर्शिता का सिद्धांत बताता है कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य राष्ट्रीय व्यापार नियमों को प्रकाशित करते हैं, डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करते हैं, और उन तंत्रों को बनाए रखते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाले निर्णयों की समीक्षा करेंगे। डब्ल्यूटीओ समय–समय पर देश की विशिष्ट रिपोर्टों के साथ सामने आता है।

5. सुरक्षा मूल्यः सुरक्षा मानदंडों के तहत, देश पर्यावरण और मनुष्य, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जैसे आधारों पर व्यापार को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

4.4.2 डब्ल्यूटीओ के कार्य

विश्लेषकों ने डब्ल्यूटीओ के विभिन्न कार्यों की पहचान की है, इनमें से महत्वपूर्ण हैं: **डब्ल्यूटीओ**

i. समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और संचालन की देखरेख करता है;

ii. बातचीत के लिए और विवादों के निपटारे के लिए एक मंच प्रदान करता है;

iii. राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है और वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण की निगरानी के माध्यम से व्यापार नीतियों की सुसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है;

iv. विकासशील और कम से कम विकसित और कम आय वाले देशों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के लिए उनके सुचारु संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है; तथा

v. विश्व आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सुसंगतता प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूटीओ, आईएमएफऔर विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास बैंकों के सहयोग से भी काम करता है।

डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की आवश्यकता और प्रासंगिकता को आर्थिक वैश्वीकरण के युग में स्वीकार किया जाता है। यह इसकी सफलता का एक पैमाना हैः विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद से वैश्विक व्यापार की मात्रा लगातार बढ़ी है। व्यापार संबंधी मतभेद और विवाद भी लगातार और अधिक तीव्र होते गए हैं। ये अंतर सामान्य रूप से संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियों, सब्सिडी, बौद्धिक संपदा के उल्लंघन आदि से संबंधित हैं। संक्षेप में, डब्ल्यूटीओ एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छा है। यह राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और आगे के दौरों के लिए विषयों और फ्रेम नियमों की भी पहचान करता है। वैश्विक व्यापार और संबंधित मुद्दों पर इसके अनुसंधान विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा अत्यंत उपयोगी पाए गए हैं जिनके पास व्यापार के मामलों पर गहन शोध करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ वैश्वीकरण का उत्पाद है और आज के वैश्वीकृत समाज में सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है।

4.4.3 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और अन्य निकाय

विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य – देश और सीमा शुल्क संघ – हर दो साल में मिलते हैं। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है। कुछ ज्ञात मंत्री सम्मेलन सिंगापुर में उद्घाटन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि सब्सिडी पर असहमति थी जिसे ''सिंगापुर मुद्दों'' के रूप में जाना जाता था।

2001 में दोहा में चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। दोहा विकास दौर शुरू किया गया, जिसे हांगकांग में छठे विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा पूरक किया गया, जो कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने और माल से माल का शुल्क समाप्त करने पर सहमत हुआ। सबसे से कम विकसित देश। अब तक ग्यारह मंत्री सम्मेलन हुए हैं। दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 11 वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया थाय बारहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2020 में अस्ताना, कजाकिस्तान में होने वाला है।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बगल में जनरल काउंसिल है जो डब्ल्यूटीओ की वास्तविक कार्यकारी है। यह जिनेवा में अपने मुख्यालय में विश्व व्यापार संगठन के कार्यों को करने के लिए वर्ष में कई बार मिलता है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए सामान्य परिषद की रिपोर्ट।

जनरल काउंसिल में कई सहायक निकाय हैं। ये अंग विभिन्न समितियों के कार्यों की नियुक्ति और देखरेख करते हैं। जनरल काउंसिल के तहत काम करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैंः (i) व्यापार के लिए काउंसिल ऑफ गुड्स में कई विशिष्ट समितियां हैं जो कपड़ा, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में इसकी देखरेख में काम करती हैं। (ii) काउंसिल फॉर ट्रेड–रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा और ट्रिप्स परिषद के रिकॉर्ड से संबंधित सभी जानकारी रखता है। (iii) काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड्स इन सर्विसेज (गैट्स) में सामान्य समझौते के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। (iv) डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक की अध्यक्षता में व्यापार वार्ता समिति, जारी व्यापार वार्ताओं से संबंधित है। (v) सेवा परिषद के पास बड़ी संख्या में

तंत्र और समितियाँ हैं जो वित्तीय सेवाओं, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, घरेलू और नियमों आदि जैसे मामलों से निपटती हैं।

डब्ल्यूटीओ सर्वसम्मति के माध्यम से फैसले पर आता हैय और यह अब तक का अभ्यास है। हालांकि इसके नियम मतदान से भी इनकार नहीं करते हैं। विश्व व्यापार संगठन परिभाषित करता है और खुद को ''एक नियम–आधारित, सदस्य–संचालित संगठन के रूप में बताता है – सभी निर्णय सदस्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं, और नियम सदस्यों के बीच बातचीत के परिणाम हैं''। फैसलों पर पहुंचने की सहमति विधि के कुछ दिलचस्प आयाम हैंः इसका मतलब है कि कानून आधारित प्रारंभिक सौदेबाजी। हालांकि, अंत में यूरोप और अमेरिका के पक्ष में सौदेबाजी के जरिए व्यापार वार्ता को अंतिम रूप दिया जाता है। एक अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और इसके बाजार का आकार निर्णय लेने में निर्णायक कारक बन जाता है।

4.4.4 विवाद निपटान

किसी भी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए व्यापार–संबंधी विवादों का निपटारा आवश्यक है। इस तरह का एक तंत्र सभी बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों के काम के लिए केंद्रीय है। इसलिए, बातचीत और सौदेबाजी के जरिए शांति से व्यापार विवाद को निपटाने का इतिहास काफी पुराना है। व्यापारी युग में व्यापार की स्थापना के बाद से इनमें से कई नियम विकसित हुए हैं। 1947 में इसकी स्थापना के बाद से, गैटने खुद ही व्यापार विवादों को हल करने के लिए कई नियम बनाए हैं। 1994 के माराकेश समझौते में विवादों के निपटारे (डीएसयू) को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को समझने वाला था।

डब्ल्यूटीओ के तहत विवादों को सुलझाने के लिए मुद्दे–विशिष्ट पैनल स्थापित किए जाते हैं। ये मुद्दे– विशिष्ट पैनल विवाद निपटान निकाय (डीएसबी), अपीलीय निकाय, महानिदेशक और विश्व व्यापार संगठन सचिवालय, विश्व व्यापार संगठन के मध्यस्थों और सलाहकार विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पार्टियों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि किसी मामले में फैसला किया जाना है तो उसे एक साल की अवधि में तय किया जाना चाहिए। सदस्य देश इस प्रक्रिया को अनिवार्य मानने के लिए बाध्य हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न उद्देश्य, विशेषताएं और कार्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 गैट, विश्व व्यापार संगठन और विकासशील विश्व

वैश्विक शासन के संस्थानों के निर्माण में, चाहे वह ब्रेटन वुड्स संस्थान हों या संयुक्त राष्ट्र, विकासशील देश शायद ही कभी थे। उन्होंने खुद को हाशिए पर और बिना किसी आवाज के वैश्विक मामलों में आर्थिक और राजनीतिक मामलों में पाया। जीएटीटी दौर विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उनकी चिंताओं और प्राथमिकताओं का प्रभुत्व था। वार्ता के दौरान, सभी देश समान हैंय लेकिन एक दौर का अंतिम परिणाम किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसके बाजार के आकार पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर, कुछ आलोचकों का कहना है कि विकासशील देशों को इन गैट दौरों से केवल कुछ ही लाभ हुए हैं। उदाहरण के लिए, 1966 में, विकासशील देशों ने निर्मित निर्यात का 11.2 प्रतिशत हिस्सा लियाय बीस साल बाद, 1986 में, उनकी हिस्सेदारी केवल 13.8 प्रतिशत हो गई थी। कई मंत्री सम्मेलनों ने इसलिए विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत गर्म बहस पैदा की। 1999 में सिएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन असफल रहाय डब्ल्यूटीओ द्वारा विकासशील दुनिया के गले के नीचे नीलिबर नीतियों को धकेलने के प्रयासों के खिलाफ वैश्विक नागरिक समाज का समर्थन था। कैनकन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विकसित देशों ने कृषि में अपने बड़े बहुराष्ट्रीय व्यापारों के लिए विकासशील देशों में बाजारों को खोलने का प्रयास किया। इसी तरह, दोहा विकास दौर 2001 से गतिरोध बना हुआ है। यह कृषि, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों में उदारीकरण पर बातचीत करने के लिए अनिवार्य था – विकसित देशों ने अपनी कृषि सब्सिडी और अन्य भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं को बरकरार रखा।

विकसित देशों ने जीएटीटी के एजेंडे का वर्चस्व किया है, जिसका विस्तार वस्तुओं पर शुल्कों में कमी से परे हुआ। जैसा कि पहले देखा गया था, उरुग्वे दौर इन दौरों का सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद थाय और सात प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया – बाजार पहुंच, कृषि, कपड़ा, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय (ट्रिम्स), व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स), सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट्स), और संस्थागत मामले। विकासशील देश उरुग्वे दौर की दिशा से भी असंतुष्ट रहे। अंतिम परिणाम से अमीर और विकसित देशों को फायदा हुआ। वे अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में सफल रहे, जिसका अर्थ था कि अमीर देशों के एमएनसी का विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और ज्ञान पर एकाधिकार थाय और विकासशील देशों ने इन तकनीकों को सीखने और उपयोग करने का अवसर खो दिया था। उरुग्वे दौर के समापन ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकासशील देश अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन में अपने घरेलू कानूनों में बदलाव लाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो दंडात्मक उपायों जैसे कि काउंटरवैलिंग ड्यूटी के प्रावधान थे।

जीएटीटी दौरों के कारण, यह स्पष्ट हो गया था कि एजेंडा सेट करने, वार्ता की गति और अंतिम परिणाम – से अमेरिका पूरी प्रक्रिया पर हावी होगा। अमेरिका ने गैटके बहुपक्षीय ढांचे और मानदंडों के बाहर व्यापार समझौतों पर काम करना शुरू कर दिया हैय इसने कई द्विपक्षीय व्यापार सौदों का समापन किया जिसने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर कर दिया। गैटअन्य बड़ी व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं पर अनुशासन लागू करने में भी असमर्थ था।

कुल मिलाकर, युद्ध के बाद की अवधि के दौरान, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के आधिपत्य के रूप में काम किया, नेतृत्व प्रबंधन, स्थिरता और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक प्रबंधन और मुक्त व्यापार के माध्यम से पनपने का अवसर प्रदान किया। 1971 में, यूएस ने डॉलर/सोने की परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया, आयात पर एक अधिभार लगाया, और डॉलर का अवमूल्यन किया – जिसने प्रभावी रूप से निश्चित विनिमय दरों को समाप्त कर दिया। विश्लेषकों ने इन घटनाओं को ब्रेटन वुड्स प्रणाली के टूटने के रूप में वर्णित किया है। 1970 के दशक तक, व्यापार और मौद्रिक मामलों में दुनिया का नेतृत्व करने की अमेरिकी क्षमता चुनौती में आ गई। जापान, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक ताकत में बढ़ीं और वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने लगीं।

1970 के दशक में नवउदारवाद का उदय, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं, उदारीकरण और निजीकरण के उदारीकरण पर केंद्रित था, और वैश्वीकरण ने विकासशील दुनिया की घरेलू आर्थिक विकास रणनीतियों में बहुत सारे बदलाव लाए। आलोचक इस चिंता को व्यक्त करते हैं कि डब्ल्यूटीओ व्यापार प्रणाली ने संप्रभु राष्ट्र राज्यों की प्रणाली को कमजोर कर दिया हैय वैश्विक वित्त और व्यापार की निजी शिकारी ताकतों को कमजोर और खराब अर्थव्यवस्थाओं से अवगत करायाय और राष्ट्रों के बीच असमानता बढ़ गई है।

4.6 विश्व व्यापार संगठन और भारत

विश्व व्यापार संगठन बनाने का उद्देश्य एक नियम–आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली थी जो मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाएगी, और व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास दर में सुधार करेगी। व्यापार बाधाओं को कम करने से दुनिया के सभी लोगों के लिए समग्र समृद्धि और बेहतर जीवन स्तर हो सकता है। विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद से वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई है। हालाँकि, डब्ल्यूटीओ की इस बात की भी विशेष रूप से आलोचना की गई कि यह विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा हैय और यह शक्तिशाली और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। आलोचना को इस आधार पर भी समतल किया गया है कि डब्ल्यूटीओ संस्थागत असंतुलन पैदा करता है जो विकसित देशों के पक्ष में है। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन के श्रेय के लिए, इसके व्यापार से संबंधित अध्ययन और मानदंडों के लेखन ने सभी विशेष रूप से विकासशील देशों को बहुत लाभान्वित किया है।

भारत विकासशील दुनिया का एक प्रमुख सदस्य हैय और अक्सर मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों और अन्य बैठकों में गरीब और विकासशील देशों की चिंताओं को उठाया गया है। डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर बदलते बहुपक्षीय व्यापार अनुशासन के परिणामस्वरूप इसने अर्थव्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन का अनुभव किया है। भारत तदनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहा है, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है और एक टैरिफ दर को सुव्यवस्थित किया गया है। हालाँकि, इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई है कि भारत ने क्या हासिल किया है या क्या खोया है।

उरुग्वे दौर समझौता और विश्व व्यापार संगठन भारत में मजबूत आलोचना के लिए आए हैं। आलोचकों का मत है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों पर समझौता

अकेले विकसित देशों के लिए फायदेमंद है और भारत जैसे विकासशील देश हारने के लिए खड़े हैं। यह माना जाता है कि विश्व व्यापार संगठन में कृषि को शामिल करके, भारतीय किसान बेहतर बीजों और कृषि प्रौद्योगिकी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होने जा रहे हैं। किसान अपनी फसल से बेहतर गुणवत्ता वाले बीज नहीं बचा पा रहे हैं और खुले बाजार में उच्च दर पर पेटेंट बीज खरीदने के लिए मजबूर हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंटेड बीजों की मात्रा का उपयोग करना, लेकिन यह अक्सर भारत में खेती की बड़ी आबादी की सस्ती सीमा से परे होता है जिसमें छोटे और सीमांत धारक शामिल होते हैं। कृषि की समग्र लागत ऐसे समय में बढ़ी है जब किसानों को उनकी उपज के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिल रहा है। बड़े किसान अकेले ही बेहतर कृषि तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। इससे अंततः छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती हैय और यह ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाता है। आलोचकों का मत है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के समापन के बाद, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी खत्म हो गई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के माध्यम से, विकसित देशों के खाद्यान्न उत्पादन के अधिशेष से विकासशील देशों के घरेलू बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। पहले से ही, यह कई देशों में गरीब लोगों की आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, इसके अलावा अनावश्यक रूप से भुगतान की स्थिति के संतुलन पर प्रतिकूल दबाव डाल रहा है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण – पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि – उरुग्वे दौर में अधिक कठोर हो गए हैं। यह बहुराष्ट्रीय निगमों और विकसित देशों के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से किया गया है क्योंकि ट्रिपपर एक समझौता पेटेंट धारकों के पक्ष में है। यह कहा गया है कि ट्रिपप्रतिस्पर्धा–विरोधी और उदारीकरण विरोधी है और विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक एकीकरण को खोलने की भावना के खिलाफ है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार दृष्टिकोण को वैध बनाने और वैध बनाने के लिए है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दावा किया और भारत के कई प्राकृतिक उत्पादों पर पेटेंट अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। हल्दी और नीम आदि उन्होंने कई अवसरों पर पारंपरिक औषधीय ज्ञान और प्रथाओं को पेटेंट करने की कोशिश की।

यह आशंका है कि डब्ल्यूटीओ हमारे सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। हमारे घरेलू मानकों की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, बीमा, होटल सेवाएं बेहतर गुणवत्ता की हैं। परिणामस्वरूप, इन सेवाओं को प्रदान करने में लगी स्वदेशी इकाइयाँ हाशिए पर चली जाएंगी और हवा देने को मजबूर होंगी, जिससे घरेलू उद्यमिता को झटका लगेगा। इसके अलावा, शिक्षा में निजी खिलाड़ियों का प्रवेश, स्वास्थ्य सेवा शैक्षिक और स्वास्थ्य को आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए अप्रभावी बना देगा। और डब्ल्यूटीओ के तहत टीआरआईएम का प्रावधान भी भारत को विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने से रोकता है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय बाजार में अनियंत्रित प्रवेश की अनुमति दे सकता है, जो भारत में घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इससे भारत में एफडीआई बढ़ता है, लेकिन यह घरेलू उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उजागर करने के खतरे को भी वहन करता है। यह एक कठिन तथ्य है कि घरेलू उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, उत्पादन की उच्च लागत और अन्य कारकों के कारण। नतीजतन, यह आशंका है कि एमएनसी के पक्ष में घरेलू मांग में बदलाव के कारण घरेलू उद्योग

को हाशिए पर रखा जाएगा। छोटे और मध्यम उद्यम जो आमतौर पर श्रम गहन हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। एसएमई विशेष रूप से श्रम का एक प्रमुख नियोक्ता है जो अर्ध–कुशल या अकुशल है। एक बार जब एसएमई अप्रतिस्पर्धी हो जाता है, तो इससे बेरोजगारी फैल जाएगी।

इसलिए, विश्व का शायद ही कोई विकासशील देश रहा हो जो विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावों से समग्रता में सहमत हो। शेष राशि पर, लाभ और हानि हैं। सभी परिदृश्यों में, व्यापार उदारीकरण का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन अंतिम परिणाम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर विकसित समझौतों और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) समकालीन विश्व में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का मूल्यांकन करें।

2) भारत और विश्व व्यापार संगठन पर नोट लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

4.7 उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम (एलआईईओ)

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की स्थापना 1940 के दशक में हुई थी जब अंतर्राष्ट्रीय शक्ति विन्यास अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के पक्ष में थाय वे एक ही रहते हैं और केवल 1940 के विचारों को प्रतिबिंबित करना जारी रखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, उदार दुनिया का आदेश है कि इन संस्थानों को संकट में है, अगर पूर्ण पैमाने पर खतरा नहीं है। वैश्विक आर्थिक शक्ति विन्यास बदल गया है इसलिए वैश्विक व्यापार का प्रवाह और पैटर्न बना है। एशिया वैश्विक वित्त और व्यापार के केंद्र के रूप में उभरा है, जो टिप्पणीकारों को 21 वीं शताब्दी को 'एशियाई शताब्दी' के रूप में वर्णित करता है। चीन, भारत और एशिया की अन्य गतिशील अर्थव्यवस्थाओं का उदय इस बात की पुष्टि करता है कि यह एशिया है जो वैश्विक वित्त और व्यापार और तकनीकी सफलताओं का नया केंद्र है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं और शक्तियां जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देश) अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने साथ वित्तीय और राजनीतिक वजन दोनों ले जाते हैं। ग्लोबल साउथ के देश आज आपस में ज्यादा व्यापार करते हैं। इसके अलावा, ग्लोबल साउथ की उभरती और अन्य धनी अर्थव्यवस्थाओं के पास बड़ी अधिशेष पूंजी है जो अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने के लिए तैयार है। साथ ही, भारत जैसे देशों और अन्य लोगों ने चुनिंदा क्षेत्रों में विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धी लाभ विकसित

किया हैय उदाहरण के लिए, भारत सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी–आधारित सेवाओं में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है।

1970 के दशक के आसपास से, नवउदारवाद की विचारधारा ने इन देशों के साथ–साथ अमीर देशों की सरकारों के नीतिगत दृष्टिकोण और कार्य को आकार दिया। हालांकि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के साथ नवउपनिवेशवाद ने संकट की अवधि में प्रवेश किया। वैश्विक वित्तीय संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि नवउदारवाद वैश्विक वित्तीय स्थिरता की कोई गारंटी नहीं थी।

राष्ट्रपति डोनाल्ड के राष्ट्रवादी संरक्षणवादी प्रशासन का उदय, एक राष्ट्रवादी ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय, कई यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार और इस तथ्य को कि डब्ल्यूटीओ ठप्प है – सभी केवल इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान हैं इन बदली परिस्थितियों का जवाब देने की क्षमता खो दी। बल्कि, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक्स के + 100 बिलियन के नए विकास बैंक (एनडीबी) के साथ–साथ 100 बिलियन डॉलर के मजबूत कॉन्टिनेंसी रिजर्व फंड या चीन के नेतृत्व वाले 100 बिलियन एशियाई के रूप में एक 'मिनी–आईएमएफ' के रूप में तैयार हो रही हैं। इसका मतलब केवल यह है कि आईएमएफ, विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास बैंक सभी ने विकास संबंधी वित्त और आकस्मिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में अपनी अपेक्षाओं को कम कर दिया है।

संक्षेप में, संकेतों की कोई कमी नहीं है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की संस्थागत वास्तुकला को अद्यतन करने की आवश्यकता है। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट ने तेजी से परस्पर वित्तीय प्रणाली में छूत की संभावना को इंगित किया। 2008 का वैश्विक संकट जो अमेरिकी आवास में सबप्राइम संकट के साथ शुरू हुआ था, ने पुष्टि की कि वैश्विक वित्त अत्यधिक जटिल है और आसानी से समझने योग्य नहीं हैय संक्रामक एक जटिल और रहस्यमय तरीके से काम कर रहे वैश्विक वित्त में जंगल की आग की तरह फैल जाएगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन संरचनात्मक बदलावों के बावजूद, ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधार के प्रयासों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। 1999 में, एशियाई संकट के मद्देनजर, जी20 को जी8 से परे वैश्विक आर्थिक प्रशासन में प्रतिनिधित्व का विस्तार करने के लिए, 20 सबसे बड़े विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। 2008 के संकट के बाद, जी20 एक नेताओं का मंच बन गया, जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए जिम्मेदार था। विशेष रूप से उनके शासन ढांचे में बहुपक्षीय संस्थानों का सुधार और आईएमएफ की कोटा संरचना को 2010 में वोटों और सीटों को पुनर्वितरित करके उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन को कम करने के लिए उठाया गया था। सुधारों का केवल सीमित प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वीटो पावर को बरकरार रखा और यूरोप डी फैक्टो ने प्रबंधकीय नौकरी की गारंटी दी, आईएमएफ का शासन उसी मुख्य शेयरधारकों पर हावी रहा। फिर भी परिवर्तन भी हैंः आईएमएफ में कर्मचारियों के चयन में, और फंड के नीतिगत दृष्टिकोण में। 2016 में, चीनी रॅन्मिन्बी को उन मुद्राओं में भी जोड़ा गया जो आईएमएफ की आरक्षित संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार का मूल्य निर्धारित करती हैं।

क्या वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक प्रणाली अमेरिका के बिना जीवित रह सकती है। अमेरिका लंबे समय से वैश्विक नेता और संकट प्रबंधक रहा है जिसने इन संस्थानों के भीतर काम किया है। आईएमएफमें इसका कोटा लगभग 113 बिलियन डॉलर हैय इसने 2010 से विश्व बैंक में कुछ 23 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। एनडीबी और एआईआईबी हैंय लेकिन उनका आईएमएफ और विश्व बैंक के आकार से कोई मेल नहीं है। पहले स्थान पर, ये नए संस्थान आईएमएफ और विश्व बैंक को चुनौती देने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनकी गतिविधियों के पूरक हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति के अधीन एक राष्ट्रवादी अमेरिका वापस नहीं आएगा, लेकिन इन बहुपक्षीय संस्थानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कम कर सकता है। साथ ही, अमेरिका अन्य देशों को वित्तीय सहायता, आपातकालीन सहायता और व्यापार रियायतें प्रदान करने में बहुपक्षवाद के बजाय द्विपक्षीयता का मार्ग चुन सकता है। उस मामले में, अमेरिका बहुपक्षीय डोमेन के बाहर द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने खुद के नए नियम बना सकता है कि अमेरिका केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है।

सभी में, वैश्विक वित्तीय और व्यापार वास्तुकला संकट और अनिश्चितताओं के साथ जारी हैय और वित्तीय तूफानों का सामना करने की संस्थाओं की क्षमता में गिरावट आ रही है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 5

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए इकाई के अंत में दिए गए सुझाव को देखें।

1) अंतर्राष्ट्रीय उदारवादी आर्थिक क्रम के संकट पर नोट लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

4.8 सारांश

व्यापार उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज। वास्तव में, व्यापार अन्य लोगों और समाजों के साथ बातचीत करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है। आधुनिक व्यापार प्रणाली व्यापारिकता के युग की ओर लौटती है। मर्केंटाइल पूंजीवाद का मानना है कि बहुत सारे सोने, चांदी और अन्य समृद्ध धातुओं को संचित करने के लिए निर्यात आवश्यक है। सोना और चांदी राष्ट्रीय समृद्धि के संकेत थे। मजबूत राष्ट्र राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। औद्योगिक पूंजीवाद के युग में, व्यापार का विकास हुआ, विशेष रूप से शिपिंग और रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी आविष्कारों और नवाचारों के लिए धन्यवाद। विदेशी उपनिवेश काम आए। श्रम का एक विभाजन उभरा। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ उत्पादन और उत्पादकता की उच्च दरों के साथ प्रतिस्पर्धी थीं। कालोनियों ने बाजारों का गठन किया और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता भी थे। एडम स्मिथ ने तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की वकालत की। एक

उदारीकृत व्यापार प्रणाली सभी के लाभ के लिए तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर काम कर सकती है।

लगभग चार शताब्दियों में, यूरोप वैश्विक व्यापार पर हावी था। जैसे–जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, व्यापार–संबंधी मानदंड और नियम भी सहमत होने लगेय उदाहरण के लिए वजन, माप आदि के क्षेत्रों और विभिन्न मुद्राओं के विनिमय मूल्य और परिसंचरण में एक राष्ट्रीय मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करने के लिए सोने का उपयोग।

दो विश्व युद्ध और 1929 की महामंदी ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को समाप्त कर दिया। देश उनके व्यापार व्यवहार में संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक प्रणाली स्थापित करना था जो न्यूनतम बाधा के साथ व्यापार और वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा देगा। देश घरेलू आर्थिक नीतियों का चयन कर सकते थे लेकिन जहाँ तक व्यापार का सवाल है, एक नियम–आधारित व्यापार आदेश से सभी को लाभ होगा।

ब्रेटन वुड संस्थान अस्तित्व में आए। 44 मित्र देशों से कुछ 730 प्रतिनिधियों और अमेरिका के नेतृत्व में मौद्रिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना की और विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी), विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) के निर्माण के लिए एक आम सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका ने 1948 में देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) पर नेतृत्व और सामान्य समझौता किया। गैटका उद्देश्य व्यापार पर शुल्क कम करना था। बाद के दौर में, नए विषयों को जोड़ा गयाः एंटी–डंपिंग, मैन्युफैक्चरिंग में व्यापार, सेवाओं में व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार आदि।

उरुग्वे दौर 1986 से 1993 तक चला। उरुग्वे दौर गैट व्यापार नियमों को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए सहमत हुआ, जो तब तक बातचीत से मुक्त थे; वे ऐसे विषय पाए गए जो या तो बहुत कठिन थे या बातचीत के लिए बहुत संवेदनशील थे। उरुग्वे दौर के मुख्य उद्देश्य थेः कृषि सब्सिडी को कम करना; विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाने के लिए; बैंकिंग और बीमा जैसी सेवाओं में व्यापार खोलने की प्रक्रिया शुरू करना; और बौद्धिक संपदा के संरक्षण को शामिल करना। यह वास्तव में अपने दायरे में बहुत महत्वाकांक्षी और विस्तारक था; और गैट के तहत लगभग हर दूसरे नियम को प्रभावित किया। उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन बनाया जो 1995 में प्रभावी हुआ।

विश्व व्यापार संगठन ने 2001 में अपने चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दोहा दौर की वार्ता शुरू की। दोहा विकास दौर वैश्वीकरण को एक समावेशी शक्ति बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास है; और कृषि सब्सिडी और अन्य बाधाओं को दूर करके दुनिया के गरीबों की मदद करना। दोहा विकास दौर रुका हुआ है; और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास विफल रहे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका कृषि निर्यात विकासशील देशों के खिलाफ अपनी कृषि सब्सिडी और अन्य व्यापार विकृत करने वाली प्रथाओं को रखना चाहते हैं, जबकि एक ही समय में, भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को कृषि आयातों के लिए खोलने के लिए मजबूर करते हैं।

डब्ल्यूटीओ व्यापार वार्ताओं के लिए रूपरेखा तय करता है यानी यह व्यापार वार्ताओं के नियमों को निर्धारित करता है। यह व्यापार के दौर के परिणाम को नियंत्रित नहीं करता है। गैट ने कुछ सिद्धांतों पर काम किया, जो डब्ल्यूटीओ के कामकाज में शामिल किए गए। अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों पर कई सहमत हैं उदाहरण के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) और व्यापार के मामलों में पारस्परिकता का सिद्धांत। डब्ल्यूटीओके पास अपने कई निकाय और तंत्र हैं उदाहरण के लिए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो हर दो साल में मिलता है। एक महत्वपूर्ण डब्ल्यूटीओ निकाय इसका विवाद निपटान तंत्र है। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद से वैश्विक व्यापार की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। हालाँकि, विकासशील देश भी अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। अंत में डब्ल्यूटीओ के निर्णय अमीर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के हितों को पूरा करते हैं – अक्सर विकासशील देशों की कीमत पर।

कृषि में व्यापार का उदारीकरण भारत जैसे देशों को नुकसान पहुँचाता है। डब्ल्यूटीओ के नियमों की आवश्यकता है कि भारतीय किसान बड़े बीएनसी से पेटेंट किए हुए बीज और नॉच खरीदते हैं, जो विशेष रूप से छोटे किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाता है।

बहुपक्षीय वित्तीय और व्यापार संगठन 1940 के दशक के बिजली वितरण को दर्शाते हैं, जबकि इस बीच दुनिया बहुत बदल गई है। एशिया में वृद्धि हुई है; आज उभरती अर्थव्यवस्थाओं और शक्तियों के स्कोर हैं; अमेरिका और यूरोप अपनी उदार प्रतिबद्धताओं पर पीछे हटते जा रहे हैं और आवक और राष्ट्रवादी बन गए हैं। इस संबंध में, यह कहना उचित है कि बहुपक्षीय प्रणाली संकट में है।

4.9 संदर्भ ग्रंथ

बेलिस, जॉन, स्टीव स्मिथ एण्ड पैट्रिसिया ओवेंस, (ऐडिटर्स) (2001), *दि ग्लोबलाइजेशन दि वर्ल्ड पॉलिटिक्स : ऐन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस,* सेकेण्ड ऐडिशन, ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

डैस्टेच, क्लॉज गुण्टर एण्ड बर्नहार्ड स्पेयेर (ऐडिटर्स) (2001), *दि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलेनियम राउण्ड : फ्री ट्रेड इन दि ट्वेंटी–फर्स्ट सेंचुरी,* न्यू यॉर्क : रूटलेज।

होएकमैन, बेर्नार्ड एण्ड माइकेल कोस्टीकि (2001), *दि पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ दि वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम : फ्रॉम गेट (जीएटीटी) टू डब्ल्यूटीओ,* न्यू यॉर्कः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

डॉलाह, कैफ (ऐडिट) (2004), *बैकवार्टर्स ऑफ ग्लोबल प्रॉस्पैरिटी : हाउ फोर्सेज चह ग्लोबलाइजेशन एण्ड जीएटीटी/डब्ल्यूटीओ ट्रेड रिजाइम्स कंट्रीब्यूट टू दि मार्जिनलाइजेशन ऑफ दि वर्ल्ड पूअरेस्ट नेशंस,* वेस्टपोर्ट : प्रीगेर

न्ये, जोसेफ एस. एण्ड जॉन डी. डोनाहुए (ऐडिटर्स) (2000), *गवर्नेंस इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड,* वॉशिंगटन, डी.सी. : ब्रूकिंग्स इंस्टीच्यूशन प्रेस।

नायर, दीपक, (ऐडिट) (2002), *गवर्निंग ग्लोबलाइजेशन : इश्यूज एण्ड इंस्टीच्यूशंस,* ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

हेल्ड, डेविड एण्ड ऐन्थेनी, मैकग्रीयू, (ऐडिटर्स) (2003), *दि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस रीडर : ऐन इंट्रोडक्शन टू दि ग्लोबलाइजेन डिबेट*, कैम्ब्रिज : पॉलिटी प्रेस।

राव, पी.के. (2000), *दि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एण्ड दि इन्वायरन्मेंट*, न्यू यॉर्क : स्टी. मार्टिन–ज प्रेस।

राए, एम. बी. एण्ड मंजुला गुरु (2001), *डब्ल्यूटीओ एण्ड इंटरनेशनल ट्रेड*, न्यू डेल्ही : विकास पब्लिशिंग हाउस।

सैम्पसन, ग्रे पी., (ऐडिट) (2001), *दि रोल ऑफ दि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस*, न्यू यॉर्क : दि यूएन यूनिवर्सिटी प्रेस।

4.10 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

- आपके उत्तर में वैश्विक व्यापार के शुरुआती समय, दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि, और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद एक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम (एलआईईओ) स्थापित करने की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

- आपके उत्तर को विशेष रूप से उरुग्वे दौर और डब्ल्यूटीओ के गठन पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैट वार्ता के विभिन्न दौरों को कवर करना चाहिए।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

- आपके उत्तर में विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न उद्देश्य, विशेषता और कार्यों कावर्णन होना चाहिए।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

- विश्व व्यापार संगठन, विकासशील विश्व और भारत।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 5

- बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती क्षमताओं के पहलुओं पर प्रकाश डालें।

इकाई 5 एमएनसी और टीएनसी की कार्य–प्रणाली

संरचना

5.0 उदेश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 एमएनसी और टीएनसी की अवधारणा और विशेषताएं

5.3 टीएनसी का विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था

5.4 वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी

5.5 घरेलू और मेजबान देशों के साथ टीएनसी के संबंध

5.6 सारांश

5.7 संदर्भ ग्रंथ

5.8 अपनी प्रगति जांच करें अभ्यास के उत्तर

5.0 उदेश्य

इस इकाई में आप बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) और अंतर्राष्ट्रीय निगमों (टीएनसी) के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई के माध्यम से आप निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे :

- एमएनसी और टीएनसी की अवधारणा और विशेषताओं को परिभाषित करें
- एमएनसी और टीएनसी के विकास का परीक्षण करें
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका पर चर्चा करें, और
- घरेलू और मेजबान देश पर टीएनसी के प्रभाव का अध्ययन करें।

5.1 प्रस्तावना

बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) या अंतर्राष्ट्रीय निगमों (TNCs) का उद्‌भव विश्व अर्थव्यवस्था में नई घटना नहीं है। हालांकि, 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत से वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख बन गए हैं। तेजी से बदलती तकनीक पर आधारित वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और टीएनसी के विकास को प्रेरित किया है। वैश्वीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है, जिसमें आर्थिक (गैर–सरकारी) और राजनीतिक अभिकारकों (राज्य) के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था शक्तिशाली निजी अभिकारकों द्वारा संचालित है जिसमें वित्तीय निगम (बैंक और अन्य वित्तीय फर्म) के साथ–साथ गैर–वित्तीय निगम भी वैश्विक उत्पादन तंत्र (एमएनसीध्टीएनसी) में शामिल हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतनी अधिक अभूतपूर्व प्रभाव वाली गतिविधियों को अंजाम दिया कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों और बाजारों का एक प्रमुख स्तंभ माना जाने लगा। इसके साथ ही टीएनसी अपने आकार में इतने बड़े हो गए हैं कि वे दुनिया भर के लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। मानव

जीवन में उनकी उपस्थिति और महत्व आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी गहन भूमिका से प्रकट होता है। वे दुनिया के कई राष्ट्र राज्यों से अधिक संसाधनों पर अधिकार के मामले में बेहद शक्तिशाली संस्थान बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्र राज्यों और उनके बीच संबंधों तथा किसी देश के घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालने की क्षमता के कारण ये निगम सत्ता का केंद्र बन गए हैं। संक्षेप में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंव तकनीकी नवाचार की विस्तार की भूमिका के कारण एमएनसी और टीएनसी 20वीं और 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएनसी और टीएनसी का कितना वजन और प्रभाव है इसे समझने और अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित को देखें :

i. दुनिया की 100 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 51 वैश्विक निगम और सिर्फ 49 देश हैं,

ii. शीर्ष 200 निगमों की संयुक्त बिक्री दुनिया की 9 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर सभी देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बड़ी है और यही कारण है कि वे 182 देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था से आगे निकल गए हैं,

iii. शीर्ष 200 निगमों का दुनिया भर के ⅘ सबसे गरीब लोगों पर लगभग दोगुना आर्थिक दबदबा है।

5.2 एमएनसी और टीएनसी की अवधारणा और विशेषताएं

जैसे–जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती गई, बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी), बहुराष्ट्रीय उपक्रम (एमएनई) और अंतर्राष्ट्रीय निगम (टीएनसी) जैसे बहुत सारे शब्द इसके लिए उपयोग में आए। हालांकि, कुछ विद्वान एमएनसी या टीएनसी शब्द के बीच अंतर नहीं करते हैं और आमतौर पर शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो दोनों को अलग मानते हैं। जो इन दो शब्दों के बीच अंतर करते हैं, उनका तर्क है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक स्वामित्व वाली होती हैं, खासकर एक देश द्वारा, जो एक या दो देशों में संचालन करती हैं, जबकि टीएनसी कंपनियां कई देशों में संचालन करती हैं और ज्यादातर दो या अधिक देशों के सह–स्वामित्व पर आधारित होती हैं। हालांकि, यह अंतर धुंधला हो गया है क्योंकि अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी संख्या में सहायक कंपनियों के साथ विभिन्न देशों में संचालित होती हैं। इसलिए, इस शब्द का प्रयोग एक ही समय में परस्पर रूप से किया जाता है।

''एक कंपनी जिसका मुख्यालय एक देश (जो कि स्वदेश है) में है और जो कम–से–कम एक विदेशी (मेजबान) देश में काम करती है।'' उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है। (विल्किंस, 1991)। टीएनसी को ''मूल उपक्रम और उसके विदेशी सहयोगियों से जुड़े या असंबद्ध उपक्रमों'' के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल उपक्रम क्या है? इसका एक साधारण परिभाषा है – एक उपक्रम जो आमतौर पर अपने गृह देश के अलावा अन्य देशों में एक निश्चित इक्विटी पूंजी हिस्सेदारी के स्वामित्व द्वारा दूसरी संस्थाओं की संपत्तियों को नियंत्रित करता है। एक विदेशी सहयोगी क्या है? एक विदेशी सहयोगी एक निगमित या अनिगमित उपक्रम है जिसमें एक निवेशक, जो किसी दूसरे देश का निवासी है, एक ऐसी हिस्सेदारी का

मालिक है जो उस उपक्रम के प्रबंधन में एक स्थायी हित की अनुमति देता है (एक निगमति उपक्रम के लिए 10 प्रतिशत या उसके समकक्ष अनिगमित उपक्रम में इक्विटी हिस्सेदारी) (यूएनसीटीएडी, 2018)।

लाभ के उद्देश्य के आधार पर ये एमएनसी या टीएनसी एक से अधिक देशों में बिक्री का विस्तार करने, संसाधनों का अधिग्रहण करने, बिक्री और आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने और प्रतिस्पर्धी जोखिम को कम करने के उद्देश्य के साथ अधिक–से–अधिक लाभ कमाना चाहती हैं।

एमएनसी क्या है और इसके गुण क्या हैं? एमएनसी – ''एक ऐसी फर्म जिसका संचालन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होता, वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है।" (हेस, 1972)। दूसरे शब्दों में कहें तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय निगम जो एक कंपनी के तौर पर अपनी मूल संस्था के नियंत्रण में विदेशी निवेश और विदेशों में हिस्सेदारी खरीदती है, एमएनसी है। सबसे महत्वपूर्ण है, "एमएनसी/टीएनसी संस्थाएं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में संलग्न होती हैं और एक से अधिक देशों में मूल्यवर्धन गतिविधियों पर मालिकाना हक या नियंत्रण रखती हैं।" इसके आगे, रॉबर्ट गिलपिन प्रबंधन के पहलू पर प्रकाश डालते हैं। उनके लिए एमएनसी "एक ऐसी संस्था है जो दो या दो से अधिक देशों में आर्थिक इकाइयों की मालिक है और उनका प्रबंधन करती है। यह एक निगम द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और कई देशों में आर्थिक इकाइयों (सेवाओं, खनन उद्योगों या विनिर्माण संयंत्रों) का स्वामित्व हासिल करने पर जोर देती है। इस तरह के प्रत्यक्ष निवेश (पोर्टफोलियो निवेश के विपरीत) का मतलब राष्ट्रीय विभिन्न देशों में प्रबंधकीय नियंत्रण का विस्तार है।" सरल और व्यापक शब्दों में, एमएनसी/टीएनसी ऐसी विदेशी फर्म है जो कई देशों में परिचालन शाखाओं और सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालन करती है।

उपरोक्त विवरणों से बहुराष्ट्रीय निगमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं : (i) पहला, यह राष्ट्रीय सीमाओं के पार कई मूल्यवर्धित गतिविधियों को पहुंच, आयोजन और समन्वय करता है। (ii) दूसरा, यह इन गतिविधियों से उत्पन्न मध्यवर्ती उत्पादों के लिए कम–से–कम सीमा पार कुछ बाजारों को स्थापित करता है। यह एमएनसी ही है जो सीमा पार उत्पादन और लेन–देन, दोनों में शामिल है। (iii) तीसरा, एमएनसी की प्रकृति अल्पाधिकारी हो जाती है जहां स्वामित्व, प्रबंधन, उत्पादन और विक्रय गतिविधियां कई देशों के क्षेत्राधिकार में फैली होती हैं। इसमें मुख्य कार्यालय एक देश में जबकि प्रबंधन से जुड़े लोगों, वित्तीय संपत्तियां और तकनीकी संसाधन के साथ–साथ सहायक कंपनियां दूसरे देश में स्थित होती हैं। (iv) चौथा, एमएनसी का इरादा दुनिया भर के बाजारों के लिए न्यूनतम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, खासकर उत्पादन सुविधाओं वाले सबसे अनुकूल स्थानों का अधिग्रहण कर या मेजबान सरकार द्वारा कर में छूट प्राप्त कर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज का मुख्य आधार है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. एमएनसी/टीएनसी को परिभाषित करें और उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 टीएनसी का विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था

एमएनसी के विकास की एक लंबी कहानी है। उसने अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, तीव्र उदारीकरण, वैश्वीकरण और विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में परिवर्तन के कारण कई वर्षों में खुद को रूपांतरित किया है। परिणामस्वरूप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैमाने और दायरे दोनों बढ़ गए हैं। मोटे तौर पर, जिस तरह से कंपनियां दुनिया भर में अपने कारोबार का विस्तार और उसे एकीकृत कर रही हैं, उससे पता चलता है कि वे उद्देश्य के साथ बढ़ रही हैं।

टीएनसी के विश्व अर्थव्यवस्था के 'विकास का इंजन' बनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित घटनाक्रमों में दिए गए हैं :

1. बाजार की ताकतों पर बढ़ता जोर और लगभग सभी विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के लिए बढ़ती भूमिका।
2. तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति एवं संगठन और ऐसी गतिविधि के स्थान को बदल रही हैं।
3. फर्मों और उद्योगों का वैश्वीकरण जिससे उत्पादन श्रृंखला राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करती है।
4. विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा एकल क्षेत्र बनने के लिए सेवाओं का उदय।
5. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण

आधुनिक एमएनसी या टीएनसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में विकसित हुए। हालांकि, बहुराष्ट्रीय उपक्रमों की उत्पत्ति का पता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शुरुआती संकेतों से लगाया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जड़ों का पता सहस्राब्दी ई.पू. से लगाया जा सकता है, जब मध्ययुगीन यूरोप के प्राचीन असीरियन उपनिवेशवादियों, फोनीशियन, यूनानियों और रोमनों द्वारा संचालित व्यवसाय जुड़ी हुई थीं। वहीं, अन्य लोग पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी (1600) और डच ईस्ट इंडिया कंपनी (1602) की कंपनियों में समानता देखने को मिलती है। रॉयल अफ्रीकन कंपनी (1660) को अफ्रीका से सोने और गुलामों के व्यापार के लिए बनाया गया था और हडसन बे कंपनी (1670) को फर का व्यापार करने और उत्तरी अमेरिका का उपनिवेशीकरण करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, 18वीं शताब्दी के अंत तक और 19वीं सदी की शुरुआत तक औद्योगिक क्रांति से मिलता–जुलता और समकालीन स्थिति में निगमों का उदय नहीं हुआ था। उत्पादन

प्रक्रियाओं में परिवर्तन और तकनीकी विकास के कारण नई उत्पादन प्रक्रियाओं के उदय के परिणामस्वरूप वर्तमान टीएनसी की समान विशेषताओं वाले आधुनिक निगमों का उद्‌भव हुआ। हालांकि, यह केवल 20वीं शताब्दी की शुरुआत ही थी जब योग्य पेशेवरों द्वारा प्रबंधित और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था पर आधारित बड़े उपक्रम उभरे।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दो दशकों में यूएस टीएनसी आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर हावी रही। अमेरिकी प्रत्यक्ष निवेश का मूल्य 1950 में 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1984 तक लगभग 233.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 1981 में दुनिया के एफडीआई में यूएस का हिस्सा 2/5 से अधिक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एफडीआई की दिशा में भी परिवर्तन हुआ था। अमेरिकी निवेश लैटिन अमेरिका से कनाडा, पश्चिमी यूरोप और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया। निवेश का बड़ा हिस्सा उन्नत विनिर्माण उद्योगों यानी उन्नत औद्योगिक क्षेत्रों (ऑटोमोबाइल, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स) में चला गया। इस बीच 1970 के दशक के शुरुआत में में ब्राजील, भारत और पूर्व के वामपंथी देशों जैसे नव–औद्योगिकृत देशों (एनआईसी) में कुछ निगमों के साथ–साथ यूरोपीय और जापानी बहुराष्ट्रीय निगमों का भी उदय हुआ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी उन्नति, राजनीतिक अनिश्चितताओं और विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार बाधाओं में नाटकीय वृद्धि के परिणामस्वरूप विदेशी सहायक या स्थानीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना हुई। इससे 20वीं सदी के अंत तक कई देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विलय एवं अधिग्रहण (एम ऐंड ए) विदेशी निवेश का पसंदीदा तरीका बन गया, जो विकसित दुनिया में एफडीआई के थोक और विकासशील दुनिया में शेयरों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट – 2002 के अनुसार, 1987 में विभिन्न देशों में विलय एवं अधिग्रहण (एम ऐंड ए) 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1999 में 720 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सीमा पार एम ऐंड ए के रूप में दुनिया में एफडीआई प्रवाह का अनुपात 1999 में 80 प्रतिशत तक पहुंच गया। वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी एवं संचार में तेज प्रगति से प्रेरित विश्व अर्थव्यवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के कारण टीएनसी की भूमिका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

आपको पता होना चाहिए कि विलय और अधिग्रहण (एम ऐंड ए) व्यावसायिक फर्मों की रणनीतिक प्रबंधन का हिस्सा है। एम ऐंड ए एक लेनदेन है जिसमें कंपनियों, अन्य व्यावसायिक संगठनों या उनकी परिचालन इकाइयों के स्वामित्व को अन्य संस्थाओं के साथ स्थानांतरित या सम्मिलित किया जाता है। एम ऐंड ए के साथ कंपनियां विकास करती हैं, उनका आकार घटता है या खत्म हो जाती हैं। एम ऐंड ए के कारण फर्मों के व्यवसाय की प्रकृति या प्रतिस्पर्धी स्थिति में भी परिवर्तन होता है।

सरल शब्दों में कहें तो विलय दो इकाइयों का एक इकाई में एकीकरण है, जबकि अधिग्रहण का मतलब है कि एक फर्म ने किसी अन्य इकाई के शेयर, इक्विटी हितों या परिसंपत्तियों का स्वामित्व ले लिया। वाणिज्यिक शब्दों में, दोनों प्रकार के लेनदेन में आमतौर पर एक इकाई के तहत संपत्ति और देनदारियों का समेकन होता है; इसलिए ''विलय'' और ''अधिग्रहण'' के बीच का अंतर धुंधला बना हुआ है।

विकासवादी प्रक्रिया में, विदेशी बाजारों से लाभ उठाने के लिए टीएनसी की वैश्विक रणनीतियों में भी परिवर्तन देखा गया हैः दुनिया के बाजारों के साथ जुड़ने के लिए पांच अलग–अलग साधन हैं :

1. निर्यात या स्थानीय फर्मों को लाइसेंस देकर बाजार की सेवा द्वारा प्रत्यक्ष निवेश नहीं।
2. ग्रीनफील्ड उद्यम द्वारा सीधे निवेश।
3. किसी स्थानीय फर्म का अधिग्रहण द्वारा सीधे निवेश।
4. स्थानीय फर्म के साथ विलय द्वारा सीधे निवेश।
5. स्थानीय फर्म के साथ रणनीतिक गठबंधन।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोट i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था में विलय एवं अधिग्रहण (एम ऐंड ए) की घटना की व्याख्या करें

.....

.....

.....

.....

.....

5.4 वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी

पिछले कुछ वर्षों में टीएनसी की भूमिका विश्व अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक उलझा हुआ और जटिल हो गई है। उनकी व्यापक भूमिका न केवल पैमाने और पहुंच में स्पष्ट हैं, बल्कि उनकी गतिविधियों की प्रकृति भी एकरूपता है।

टीएनसी की संख्या बढ़ रही हैः 1990 के दशक की शुरुआत में विश्व में 1,70,000 विदेशी सहयोगियों के साथ अनुमानित 37,000 टीएनसी थे। इनमें से 33,500 विकसित देशों में स्थित मूल निगम (पैरेंट कॉरपोरेशन) थे। 15 वर्षों की अवधि में 7,70,000 से अधिक विदेशी सहयोगियों के साथ बढ़कर टीएनसी की संख्या 77,000 हो गई। इसके अलावा, 1990 के दशक की शुरुआत में 90 प्रतिशत से अधिक टीएनसी के मुख्यालय विकसित देशों में थे और 01 प्रतिशत से कम टीएनसी की उत्पत्ति मध्य और पूर्वी यूरोप में हुई। सभी मूल निगमों का लगभग 08 प्रतिशत हिस्सा विकासशील देशों में है। वर्ष 2005 के आसपास 15 वर्षों की अवधि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मूल निगम सभी टीएनसी के एक चौथाई थे और उनमें से पांच दुनिया के शीर्ष 100 स्थान में शामिल थे।

टीएनसी का राजस्व आधार मजबूत और बड़ा हैः राजस्व के मूल्य के अनुसार, 2016–17 में राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों सहित शीर्ष 10 सबसे बड़े निगम थेः 485 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व वाला वॉलमार्ट (यूएस), स्टेट ग्रिड (चीन) 315 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सिनोपेक समूह (चीन) 267 बिलियन अमेरिकी डॉलर, चाइना नेशनल पेट्रोलियम (चीन) 262 बिलियन अमेरिकी डॉलर, टोयोटा मोटर (जापान) 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वॉक्सवैगन (जर्मनी) 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर, रॉयल डच शेल (नीदरलैंड) 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बर्कशायर हैथवे (यूएस) 223 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऐप्पल (यूएस) 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर और एक्सॉन मोबाइल (यूएस) 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के अनुसार, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों ने 2016 में राजस्व में 27.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और मुनाफे में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोत्तरी की। इन कंपनियों ने वर्ष 2016–17 में दुनिया भर में 67 मिलियन लोगों को रोजगार दिया, जिसमें 34 देशों के लोग शामिल थे।

बाजार पूंजीकरण के अनुसार, वर्ष 2016 में विश्व के शीर्ष 10 निगम अमेरिका के थे। हालांकि, हांगकांग और चीन की चाइना मोबाइल लिमिटेड, आईसीबीसी लिमिटेड और पेट्रो चाइना दुनिया की शीर्ष 20 कंपनियों में शामिल हैं, विशेष रूप से दूरसंचार, वित्तीय और तेल एवं गैस के क्षेत्र में।

टीएनसी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाः विश्व अर्थव्यवस्था में टीएनसी के प्रमुख योगदानों में से एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला या वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण है जिसके तहत एक एकल उत्पाद का दुनिया के विभिन्न स्थानों पर उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐप्पल आईफोन मूलभूत परिवर्तन को दिखाता है जो उत्पादन प्रक्रिया के बारे में टीएनसी द्वारा समन्वित वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के कारण उत्पादन प्रक्रिया के बारे में बताता है। वर्ष 2014 तक आईफोन 6 के पुर्जे 31 देशों में 785 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित किए गए थे। उत्पाद को अमेरिका में डिजाइन किया गया और चीन में जोड़ा गया। इनमें से 60 आपूर्तिकर्ता यूएस के और 349 चीन के थे। वैश्विक उत्पादन में इस तरह के अंतर्संबंध को मान्यता देते हुए, यूएनसीटीएडी ने कहा : "आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) से चिह्नित किया जाता है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखरी हुई उत्पादन प्रक्रियाएं में होता है। जीवीसी आमतौर पर संबद्ध नेटवर्क, संविदात्मक साझेदारों और अलग–अलग आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ आयात–निर्यात के साथ टीएनसी द्वारा समन्वित होता है। टीएनसी समन्वित जीवीसी का वैश्विक व्यापार में लगभग 80ः हिस्सा है।"

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उन्नत और विस्तारित उपयोग ने टीएनसी के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है और मेजबान देशों में उसके विदेशी सहयोगियों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन को भी प्रभावित किया है। यूएनसीटीएडी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, 2010 से 2015 के बीच यूएनसीटीएडी की शीर्ष 100 टीएनसी की सूची में तकनीकी कंपनियों की संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। इनकी संपत्ति में 65 प्रतिशत वृद्धि हुई और उनके परिचालन राजस्व और कर्मचारियों में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। सभी उद्योगों के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में ई–कॉमर्स और डिजिटल कंटेंट फर्म सहित डिजिटल

तकनीक को अपनाने का भी अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। डिजिटल टीएनसी का विदेशों में कुल बिक्री का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि उसकी संपत्ति का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा उसके घरेलू देश से बाहर है।

विकासशील देशों की टीएनसी युवा हैः वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की प्रमुख विशेषताओं में से एक विकासशील देशों की टीएनसी की बढ़ती प्रमुखता है, खासकर राज्य के स्वामित्व वाली टीएनसी की। 2008–2009 के जीएफसी के दौरान कई टीएनसी को झटका लगा था, जबकि कई विकसित और उभरते एवं विकासशील देशों की राज्य स्वामित्व वाली टीएनसी (एसओ–टीएनसी) ने विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई। वर्ष 2012 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं को एफडीआई में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा जो वैश्विक प्रवाह का सिर्फ 42 प्रतिशत था, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक एफडीआई प्रवाह का 52 प्रतिशत अवशोषित किया। विकासशील देशों ने भी वैश्विक एफडीआई का लगभग एक तिहाई प्रवाह किया। यूएनसीटीएडी की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, 86,000 से अधिक विदेशी सहयोगियों वाले लगभग 1,500 एसओ–टीएनसी हैं, जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं और ये कुल टीएनसी का लगभग 1.5 प्रतिशत और सभी सहयोगियों के 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि शीर्ष 100 गैर–वित्तीय टीएनसी में से 15 राज्य के स्वामित्व वाले टीएनसी थे। इन 100 में से शीर्ष 41 टीएनसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस में स्थित थे।

राज्य के स्वामित्व वाली टीएनसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है : कुल संपत्ति के मामले में जर्मनी, इटली और फ्रांस से गैर–वित्तीय एसओ–टीएनसी 2016 में हावी थे। 432 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ जर्मनी के वॉक्सवैगन समूह को पहला रैंक हासिल है, इसके बाद इटली के एनेल स्पा और एनी स्पा (क्रमशः 164 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति), जर्मनी के ड्यूश टेलीकॉम एजी (156 बिलियन अमेरिकी डॉलर), ईडीएफ एसए (296 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और एंजी (167 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हैं। वर्ष 2016 में चीन और जापान क्रमशः 179 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 187 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष दस एसओ–टीएनसी में 7वें और 10वें स्थान पर थे।

जहां तक वित्तीय एसओ–टीएनसी की कुल संपत्ति का सवाल है, 2016 में चीनी कंपनियों का प्रभुत्व स्पष्ट था। वर्ष 2016 में जापान पोस्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने कुल रैंकिंग में 4वां स्थान हासिल किया, जिसकी कुल संपत्ति 2,592 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और यूनाइटेड किंग्डम (यूके) के रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्रुप पीएलसी ने 982.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया।

टीएनसी और एफडीआई : टीएनसी माल और सेवाओं में त्वरित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एफडीआई और तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया के केंद्र में है। इस प्रकार टीएनसी विश्व अर्थव्यवस्था के गहन एकीकरण और खुलेपन को बढ़ावा देता है। इस तरह की भूमिका के कई संकेतकों में से एक बढ़ती एफडीआई के माध्यम से आर्थिक एकीकरण है। वर्ष 2010 में वैश्विक एफडीआई का मूल्य 21,288.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था और 8,90,000 बिलियन विदेशी सहयोगियों के साथ 100,000 से अधिक टीएनसी की है। एफडीआई

विभिन्न देशों में आर्थिक गतिविधियों का प्रसार, सभी देशों में विकास को बढ़ावा और व्यापार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण को सक्षम कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक–से–अधिक आर्थिक दक्षता में योगदान देता है। इस प्रक्रिया में वह विशेष रूप से मेजबान देशों में रोजगार का सृजन करता है। हालांकि, इस तरह के एफडीआई पर मेजबान देशों की निर्भरता में वृद्धि, तेज प्रतिस्पर्धा, स्वदेश के लिए मुनाफे का दोहन और संसाधनों पर नियंत्रण जैसे इसके प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। कभी–कभी टीएनसी मेजबान देश के मुकाबले अपने देश की हितों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, अपने हितों को साधने में विफल रहने पर गृह देश सहायक कंपनियों के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक रूप से मेजबान देश को अलग कर सकता है। इसके विपरीत, मेजबान देश किसी सहायक की संपत्ति को भी जब्त कर सकता है और किसी भी नकारात्मक निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए गृह देश पर दबाव डाल सकता है। मेजबान देशों के विदेशी व्यापार और मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन से सहायक कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गृहयुद्ध या घरेलू हिंसा टीएनसी के हितों को खतरे में डाल सकती है जिसके कारण मेजबान देश में इसका संचालन वापस या निलंबित हो सकता है।

टीएनसी और विकासशील दुनिया में उसकी विकासात्मक भूमिकाः टीएनसी ने एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य श्रृंखला गतिविधियों का विखंडन और विभिन्न देशों में उसका फैलाव हुआ है। इससे पहले, ऐसी गतिविधियों को एक फर्म के संरक्षण में समन्वित किया गया था और मुख्य रूप से उत्पादन और संचालन पर केंद्रित किया गया था। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ इस तरह की गतिविधियां स्वतंत्र या कहें शिथिल निर्भर संस्थाओं के बीच समन्वित होती रही हैं। इसलिए, टीएनसी भी तेजी से संस्थानों को आकार दे रहे हैं और स्थानीय नागरिक समाज साझेदारों के माध्यम से इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल हैं और स्थानीय उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और आपूर्तिकर्ता संपर्क–सूत्र प्रदान कर टीएनसी स्थानीय कंपनियों को संचालन के पैमाने और दायरे का विस्तार करने के साथ–साथ मानव संसाधन को उन्नत करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, टीएनसी की भागीदारी उन देशों में आर्थिक गतिविधि के दायरे के विस्तार की कुछ कठिनाइयों को दूर करने में मदद कर सकती है जहां सामाजिक सामंजस्य कम और शिक्षा का स्तर पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक–निजी साझेदारी के माध्यम से टीएनसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक और उद्योग एवं फर्म स्तर के स्व–नियमन की स्थापना में मेजबान सरकार की मदद करता है। टीएनसी सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से परस्परिक लाभ के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या बुनियादी ढांचा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में शामिल है।

वैश्विक शोध एवं विकास (आर ऐंड डी) : वैश्विक शोध एवं विकास (आर ऐंड डी) में टीएनसी बड़ी भूमिका निभा रहा है, खासकर विकासशील और निम्न विकासशील देशों में। टीएनसी अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त का स्रोत और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकियों के इस तरह के हस्तांतरण के लिए मेजबान देशों की ग्राह्य क्षमता बढ़ाने के लिए टीएनसी भी विकासशील देशों को वैश्विक आपूर्ति एवं वितरण श्रृंखला और बाहरी बाजारों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उनके आर ऐंड डी व्यावसायीकरण प्रणाली के निर्माण में मदद करते हैं। वैश्विक आर ऐंड डी गतिविधियों में टीएनसी की एक बड़ी हिस्सेदारी है। वर्ष 2002 में दुनिया की

शीर्ष 700 कंपनियों ने आर ऐंड डी पर 311 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। वर्ष 1993 और 2002 के बीच दुनिया भर में विदेशी सहयोगियों का अनुसंधान एवं विकास व्यय अनुमानित 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 1996 से 2002 के बीच विकासशील देशों में आर ऐंड डी में विदेशी सहयोगियों की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई। 2000 के दशक की शुरुआत से सबसे महत्पूर्ण बात चीन, भारत, ब्राजील और रूस सहित कम लागत पर उपलब्ध असाधारण प्रतिभा एवं प्रौद्योगिकी और भविष्य के बाजार क्षमता वाले उभरते बाजारों या देशों में टीएनसी द्वारा आर एंड डी संसाधनों का स्थानांतरण है। वर्ष 2000 और 2015 के बीच उभरते देशों में एमएनसी आर ऐंड डी केंद्रों की संख्या पांच कारक से बढ़ी है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोट i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. वैश्विक मूल्य श्रृंखला के विचार और महत्व का संक्षेप में वर्णन करें
2. वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएनसी/टीएनसी के विकास को कौन–से कारक स्पष्ट करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

5.5 घरेलू और मेजबान देशों के साथ टीएनसी के संबंध

घरेलू और मेजबान देशों, दोनों के साथ टीएनसी का संबंध जटिल है। घरेलू और मेजबान देश दोनों के लिए टीएनसी के सकारात्मक और नकारात्मक निहितार्थ हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं : (i) टीएनसी विशेष रूप से मेजबान देशों में राजस्व और रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, जो गरीबी में कमी और बेरोजगारी दूर करने में मदद कर सकता है। (ii) वैश्वीकरण और नव–उदारवाद के संदर्भ में टीएनसी को मेजबान देश में निर्यात बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण माना जाता है। (iii) विकसित देशों के कई ऐसे राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो टीएनसी के कार्यों का नियमन करते हैं। टीएनसी पर्यावरण और श्रम स्थिति सहित मानक नियमों और कार्यों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए पारदर्शी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। (iv) विकसित देशों में सरकारें सार्थक आर ऐंड डी के लिए निहायत ही कम धनराशि और क्षमता रखती हैं। तकनीकी दक्षता और तकनीकी परिवर्तन द्वारा टीएनसी सहयोगियों द्वारा की गईं अनुसंधान और विकास गतिविधियों के माध्यम से आर ऐंड डी संबंधित एफडीआई आर्थिक विकास को सीधे प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह 'प्रतिस्पर्धात्मक लाभ' हासिल करने वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं

को उत्कृष्ट क्षेत्रों में बढ़ावा देता है। इसके अलावा, आर ऐंड डी मेजबान देश में रोजगार सृजन में योगदान देता है। हालांकि, अनुसंधान और विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेजबान देशों के दुर्लभ स्थानीय आर ऐंड को स्थानीय फर्मों और अनुसंधान संस्थानों से वंचित कर सकता है।

इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि विकासशील देशों में एमएनसी के कामकाज को लेकर को विद्वानों को बहुत शिकायत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकृतियां पैदा की हैं। (i) कहा जाता है कि घरेलू और मेजबान देशों, दोनों अपने–अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए टीएनसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। घरेलू देश लॉबिंग, विज्ञापन और अन्य तरीकों से विदेश नीति और अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टीएनसी का उपयोग और जोड़–तोड़ करते हैं। इसके विपरीत, मेजबान देश भी अपने देश की सहायक कंपनियों पर किसी नकारात्मक निर्णय को शामिल करने के लिए लिए जब्ती के माध्यम से दबाव डाल सकते हैं। (ii) कहा जाता है कि एमएनसी और टीएनसी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार की वैश्विक प्रणाली का नेतृत्व नहीं करते हैं। वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई आज वास्तव में इंट्रा–फर्म व्यापार है। (iii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कल्पना घरेलू देश में श्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा अपने हितों के लिए खतरे के रूप में की जा सकती है। इसी तरह, मेजबान देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके आर्थिक, राजनीतिक और अन्य हितों के लिए हानिकारक मानकर अपने अर्थव्यवस्था में प्रवेश रोक लगा सकता हैं। (iv) जैसा कि पहले कहा गया है, दुनिया की 100 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 51 निगम हैं, जबकि केवल 49 देश हैं। वॉलमार्ट इजराइल, पोलैंड और ग्रीस जैसे 161 देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से बड़ा है। मित्सुबिशी इंडोनेशिया से बड़ी है। जनरल मोटर्स डेनमार्क से बड़ी है। फोर्ड दक्षिण अफ्रीका से बड़ी है। टोयोटा नॉर्वे से बड़ी है। ये विशालता सिर्फ उनकी पूंजी आधार और कमाई के लिहाज से नहीं है, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में कहीं अधिक तकनीक है। (v) टीएनसी का विश्वव्यापी प्रसार चिंता का विषय है। वैश्विक असमानता और गरीबी की गहरी खाई के लिए उन्हें अधिक जिम्मेदार माना जाता है। शीर्ष 200 निगमों का दुनिया के ⅘ सबसे गरीब लोगों पर लगभग दोगुना आर्थिक दबदबा है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया के अमीरों के पास धन का भारी संग्रह हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया की जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत सबसे अमीर 1/5 लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, केवल 15 प्रतिशत जीडीपी सबसे गरीब 4/5 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, दुनिया के सबसे गरीब 4.5 बिलियन लोग सिर्फ 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली आर्थिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि शीर्ष 200 कंपनियों की 7.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर संयुक्त राजस्व के आधा से कुछ ही अधिक है। (vi) टीएनसी नौकरी उत्पन्न नहीं करती है, वह वास्तव में मौजूदा रोजगार को नष्ट करती है। विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों में 20 मिलियन से भी कम लोग कार्यरत हैं, जबकि यह अनुमान है कि 2.6 बिलियन लोग वैश्विक कार्यबल में शामिल हैं। इस प्रकार एमएनसी द्वारा उत्पन्न की गईं नौकरियां विश्वव्यापी रोजगार का एक प्रतिशत भी नहीं है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

नोट i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. एमएनसी/टीएनसी के कार्यों के नकारात्मक प्रभाव और निहितार्थ पर एक नोट लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

5.6 सारांश

पिछले कुछ दशकों में टीएनसी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने टीएनसी की प्रकृति और कार्य–प्रणाली को बदल दिया है। शुरुआती वर्षों में टीएनसी में मूल रूप से विकसित देशों की निजी कंपनियों का प्रभुत्व था। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निगमों के तेज विकास का गवाह बनी है, जो पारंपरिक निगमों को तेज गति से सहयोग और समृद्ध कर रही है। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी में उन्नति और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बदलाव के साथ टीएनसी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। एफडीआई प्रवाह का एक प्रमुख खिलाड़ी होने के कारण टीएनसी अब सेवाओं की डिलीवरी (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) जैसी कई अन्य गैर–आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव विकासशील देशों की एसओ–टीएनसी का उभार है। इन एसओ–टीएनसी की भूमिका, खासकर चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्था की, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य हो गया है और भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था में और परिवर्तन हो सकते हैं।

5.7 संदर्भ ग्रंथ

डन्निंग जॉन एच. एण्ड एस. एम. लुण्डान, (2008), *मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज एण्ड दि ग्लोबल इकोनॉमी,* चेल्तनहाम : ऐडवर्ड ऐल्गर पब्लिशिंग।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500, http://fortune.com/global500/

गिलपिन, रॉबर्ट, (1987), दि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यू जर्सी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

हायेस, रिचर्ड डी., क्रिस्टोफर एम., कोर्थ, मनुचेर रॉडिआनी, (1972), *इंटरनेशनल बिजनेस : ऐन इंट्रोडक्शन टू दि वर्ल्ड ऑफ दि मल्टिनेशनल फर्म,* न्यू जर्सी, ईगलवूड प्रेस।

लाल्ल, संजया (2002), *इंप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस–बॉर्डर मर्जर एण्ड एक्यूजिशनंस बाय टीएनसीज इन डेवलपिंग कंटरीज : ए बिगनर–ज गाइड.* वर्किंग पेपर नम्बर 88, क्यूईएच वर्किंग पेपर सिरीज – क्यूईएचडब्ल्यूपीएस 88, जून। https://pdfs.semanticscholar.org/c185/183060ca96c3803bba65d65ab665cfd0c56 .pdf

लुण्डान, सरिआना एम. एण्ड हफीज़ मिर्जा, (2010), ''टीएनसी इवॉल्यूशन एण्ड दि इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट–डेवलपमेंट पैराडाइम'', *ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस,* वॉल्यूम–19, नम्बर–2, अगस्त, पृ.31–45

मॉडेल्स्की, जॉर्ज, (1979), ''ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस एण्ड दि वर्ल्ड ऑर्डर इन जॉर्ज मॉडेल्स्की, ऐडिटेड, *ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस एण्ड वर्ल्ड ऑर्डर,* चिकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो प्रेस।

फिलिप्स, निकोला, (2017), ''ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी'', इन जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ, पैट्रिसिया ओवेन्स, ऐडिटर्स, *दि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स : ऐन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस,* ऑक्सफोर्ड : ओयूपी।

यूएनसीटीएडी, (2007), *दि यूनिवर्स ऑफ दि लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस,* न्यू यॉर्क : यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशंस. http://unctad.org/en/Docs/iteiia20072en.pdf

यूएनसीटीएडी, (2013), ''ग्लोबल वैल्यू चेन्स : इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेड फॉर डेवलपमेंट'' इन *वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2013.* http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013en.pdf,

यूएनसीटीएडी, (2017), ''इन्वेस्टमेंट एण्ड दि डिजिटल इकोनॉमी'', *वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017,*http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf

विलकिंस, मीरा, (1991), ''यूरोपीयन एण्ड नॉर्थ अमेरिकन मल्टिनेशनल्स, 1870–1914 : कम्पैरिजन एण्ड कॉन्ट्रास्ट'', इन मीरा विल्किंस, ऐडिटेड, *दि ग्रोथ ऑफ मल्टिनेशनल्स,* मस्साच्यूसेट्टस : ऐडवर्ड एल्गार पब्लिशिंग।

विलकिंस, मीरा, (1991), ''मॉर्डन यूरोपीयन इकोनॉमिक हिस्ट्री एण्ड लरत मल्टिनेशनल्स'', इन मीरा विल्किंस, ऐडिटेड, *दि ग्रोथ ऑफ मल्टिनेशनल्स,* मस्साच्यूसेट्टस : ऐडवर्ड एल्गार पब्लिशिंग।

विलकिंस, मीरा, (2005), ''मल्टिनेशनल इंटरप्राइज टू 1930 : डिस्कन्टीन्यूटीज एण्ड कंटीन्यूटीज'', इन ऐल्फर्ड डी. चैन्डलर जूनियर एण्ड ब्रूस मज़लिश ऐडिटर्स, *लेवियाथंस : मल्टिनेशनल कॉर्पोरेशंस एण्ड दि न्यू ग्लोबल हिस्ट्री,* न्यू यॉर्क : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

5.8 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- एमएनसी की परिभाषा और उनकी मुख्य विशेषताएं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) की घटना क्यों प्रमुख हो गई है?

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- वैश्विक मूल्य श्रृंखला का विचार और महत्व।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए।

- एमएनसी के काम के नकारात्मक प्रभाव और निहितार्थ को कवर करें।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 वैश्वीकरण – सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी आयाम

संरचना

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 वैश्वीकरण

6.3 संस्कृति

6.4 वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम

6.5 वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम

6.6 प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव

6.7 सारांश

6.8 संदर्भ ग्रंथ

6.9 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

यह इकाई वैश्वीकरण, इसके सांस्कृतिक और तकनीकी आयामपर केंद्रित है। इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्न बातों को समझने में सक्षम हो जाएंगे;

- वैश्वीकरण, संस्कृति और प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना
- वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों की समझ
- प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करना

6.1 प्रस्तावना

यदि आप आराम से सोचते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। कुछ विद्वानों का दावा है कि वैश्वीकरण एक हालिया घटना है, जबकि अन्य आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह एक पुरानी और एक निरंतर प्रक्रिया है जो हजारों साल पहले भाषा, लेखन और पहिया के आविष्कार के साथ शुरू हुई थी। हालांकि, हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हाल के दिनों में वैश्वीकरण ने वास्तव में अपनी गति को काफी बढ़ा दिया है। इतिहासकारों ने इस गहनता की तारीख को 1990 के दशक की शुरुआत के आसपास रखा। यह दशक संचार विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में जबरदस्त छलांग का लक्षण है। तकनीकी आधार में यह बदलाव एक सुविधा सामाजिक–राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय विकास द्वारा भी किया गया था। इसका मतलब कम्युनिस्ट यूएसएसआर का पतन था जिसने उदारवादी पूंजीवादी विश्व दृष्टिकोण के लिए एक जीत का संकेत दिया। फ्रांसिस फुकुयामा और अन्य जिन्होंने सोवियत संघ के पतन पर विजयी महसूस किया,

उन्होंने महसूस किया कि पूंजीवाद और लोकतंत्र का अंतिम युग शुरू हो गया है। उन्होंने इसे अपनी पुस्तक 'एंड ऑफ हिस्ट्री' में यह तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तावित, पूंजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृति इसके बाद प्रबल होगी। एक बेहतर दुनिया के लिए अधिक वैचारिक बहस और राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं होगीय सरल शब्दों में, सबसे अच्छा पहले ही आ चुका है।

शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, इतिहास में पहली बार ऐसा लगा कि पूरी दुनिया जल्द या बाद में पूंजीवादी हो जाएगी। इतिहास की उलझन खत्म होती दिख रही थी। सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों पर 1948 से बहस चल रही थी, 1994 में उरुग्वे में उदार–पूंजीवादी समझौतों की वेदी पर निष्कर्ष देखा गया और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना 1995 में इसकी सदस्यता के लिए इच्छुक देशों के साथ हुई थी। (आज, 2017 में, 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, कानूनी तौर पर वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो दुनिया को पहले कभी नहीं लाएंगे)। हालाँकि, इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ था। पूंजीवाद के इस ब्रांड की विद्वानों द्वारा एक समरूपता वाले प्रवचन के रूप में आलोचना की गई थी, जो कि साम्राज्यवाद के एक छद्म नए संस्करण के अलावा और कुछ नहीं है और इसे नव–साम्राज्यवाद और नव–पूंजीवाद कहा जाता है।

तेजी से बढ़ती तकनीक के साथ, दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी हुई है और एक वैश्विक गांव का गठन कर रही है। हालाँकि, यी वैंग (2007, 84) का मानना है कि यह एक वैश्विक गांव हो सकता है, लेकिन वैश्विक समुदाय नहीं क्योंकि वैश्वीकरण की समकालीन घटना ठीक उदारवादी पूंजीवाद और भौतिकवादी आधुनिकता के वैश्वीकरण की है। क्योंकि आर्थिक प्रणाली एक प्रमुख है जो अन्य सामाजिक प्रणालियों को नियंत्रित करती है, एक भौतिकवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलाई जा रही है। जीवन के प्राकृतिक तरीके को एक यंत्रवत और एक व्यक्ति में बदल दिया जाता है। प्रत्येक देश में अमीर और गरीब के बीच और अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की एक प्रक्रिया है – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त एक प्रक्रिया। वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया इतनी प्रभावी है कि यह न केवल देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि दुनिया भर के समाजों के पर्यावरण, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, समृद्धि और मानव भौतिक भलाई को भी प्रभावित करती है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि इस प्रक्रिया के कारण और प्रभाव क्या हैं? आप यह समझना पसंद कर सकते हैं कि वैश्वीकरण कैसे काम करता है और चुनाव एक व्यक्ति और समाज को इसका सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी और सामाजिक नेटवर्किंग में सुपरफास्ट वृद्धि के साथ पिछले तीन दशकों के दौरान पूरी प्रक्रिया बदल गई है और इसका संस्कृति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। नई संस्कृतियां भी विकसित हुई हैं। विभिन्न विद्वानों ने कभी–कभी 'सांस्कृतिक वैश्विकता' नामक अनुशासन के तहत इसका विश्लेषण किया है। वे मुख्य रूप से इस प्रक्रिया को विभिन्न शीर्षकों/थीसिस जैसे, समरूपता, विषमता, ध्रुवीकरण, संकरण आदि के तहत चिह्नित करते हैं। यह उचित लगता है क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया असमान है और अलग–अलग लोगों को अलग तरह से

प्रभावित करती है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, आइए हम पहले वैश्वीकरण और संस्कृति के व्यापक अर्थ को समझें।

6.2 वैश्वीकरण

वैश्वीकरण एक नई घटना नहीं हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से 1990 के दशक की चर्चा है। हालांकि, तीन दशकों के बाद भी, वैश्वीकरण अकादमिक चर्चा का एक गर्म विषय बना हुआ है। इकाई–1 में आपको इस बहुआयामी को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों सहित वैश्वीकरण की अवधारणा और अर्थ से परिचित कराया गया, फिर भी इसे परिभाषित करना मुश्किल है। एक बार फिर, आइए हम वैश्वीकरण की कुछ परिभाषाओं को देखें, इसकी कोई एकल और पूर्ण परिभाषा नहीं है।

कार्नॉय (1999) का तर्क है कि वैश्वीकरण केवल व्यापार, निवेश या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि ''सामाजिक स्थान और समय के बारे में सोचने का एक नया तरीका'' है और यह मुख्य रूप से इसलिए हुआ है क्योंकि एनआईसीटी (नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) दूरी और समय को फिर से परिभाषित किया है। वैश्वीकरण की एक विशेष रूप से उपयोगी परिभाषा जो हमारी अन्योन्याश्रितताओं पर जोर देती है, ब्लैकमोर (2000) द्वारा दी गई है, जो वैश्वीकरण को ''आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, और सामाजिक अन्योन्याश्रितियों में वृद्धि के रूप में वर्णित करता है और पूंजी, श्रम, और गतिशीलता से उत्पन्न होने वाली नई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक संरचनाएं। जानकारी, दोनों समरूपता और विभेदक प्रवृत्तियों के साथ''। ज्यादातर मामलों में, वैश्वीकरण को मुख्य रूप से एक नई और एक आर्थिक घटना माना जाता है, हालांकि कुछ आलोचक विभिन्न सामाजिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से वैश्वीकरण की जांच और परिभाषित करते हैं, जिसमें प्रवचन सिद्धांत, लिंग अध्ययन, कथा विज्ञान और बहुसंस्कृतिवाद शामिल हैं। वैश्वीकरण का अध्ययन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि सहित विभिन्न आयामों के माध्यम से किया जाता है।

इसलिए, वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुबंधों के माध्यम से दुनिया एक उच्च अंतर्संबंधित दुनिया बन रही है। यह वैश्विक अंतर्संबंध की गहनता को संदर्भित करता है, आंदोलन और मिश्रण, अनुबंध और लिंकेज से भरी दुनिया का सुझाव देता है, और लगातार सांस्कृतिक संपर्क और आदान–प्रदान करता है। परिणामस्वरूप दुनिया समय और स्थान के मामले में सिकुड़ रही है और दुनिया छोटी और दूरियों को कम महसूस कर रही है। इस प्रक्रिया की तीव्रता और गति को परिष्कृत त्वरित संचार और तेजी से यात्रा के विस्तार से अधिक बढ़ाया गया है। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण का अर्थ नए समय संयोजनों में संस्कृतियों और समुदायों को एकीकृत करना और उन्हें जोड़ना, और दुनिया को वास्तविकता में बनाना और अधिक परस्पर अनुभव करना है।

दूसरी ओर, एक प्रक्रिया, एक शर्त, एक प्रणाली, एक बल और एक उम्र का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय प्रेस और अकादमिक साहित्य दोनों में वैश्वीकरण का विभिन्न रूप से उपयोग किया गया है। यह देखते हुए कि इन प्रतिस्पर्धी लेबल के बहुत अलग अर्थ हैं, उनका अंधाधुंध उपयोग अक्सर अस्पष्ट होता है और भ्रम को आमंत्रित करता है। वैश्वीकरण की गतिशीलता की खोज करने वाले शिक्षाविदों विशेष रूप से

सामाजिक परिवर्तन के विषय से संबंधित अनुसंधान प्रश्नों का पीछा करने के लिए उत्सुक हैं। कई वैश्विक अध्ययन विशेषज्ञों का तर्क है कि आर्थिक प्रक्रियाएं वैश्वीकरण के मूल में हैं। अन्य लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, या वैचारिक पहलुओं को विशेषाधिकार देते हैं। (स्टीगर, 2017) इसलिए, विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न तरीकों से इसका विश्लेषण, व्याख्या और व्याख्या की गई है – विरोधाभासी बयानों से लेकर प्रशंसात्मक बयानों तक–दुनिया के दृश्य जिसे आप इसे देखने के लिए लाते हैं।

अपने वैश्वीकरण में मैनफ्रेड बी. स्टीगर (2017) के अनुसारः एक बहुत छोटा परिचयः, ''वैश्वीकरण का अर्थ है, विश्व–समय और विश्व–अंतरिक्ष में सामाजिक संबंधों और चेतना के विस्तार और गहनता को दर्शाता है''। और वहां भी दिया गया, ''वैश्वीकरण के रूप में छोटी परिभाषा दुनिया भर में परस्पर संबंध बढ़ने के बारे में है''।

इन दृष्टिकोणों का यह मानना कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो एक साथ और असमान रूप से कई स्तरों पर और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न आयामों में संचालित होती है। इन प्रक्रियाओं को चलाने वाली ताकतें वास्तव में 3500 ईसा पूर्व से हजारों वर्षों से काम कर रही हैं। सुमेर (वर्तमान दक्षिणी इराक) जब पहली बार मनुष्य ने उच्च स्तर पर समाज को संगठित करना शुरू किया और लेखन और नई तकनीक और व्यापार के लिए लंबी दूरी के संचार के माध्यम से संचार और एकजुटता की मांग की। आज हम उस प्रयास के उच्च गति वाले चरण में हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1) वैश्वीकरण और उसके विकास को परिभाषित करें।

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 संस्कृति

रेमंड विलियम्स (1976, 87) ने संस्कृति को सबसे जटिल शब्दों में से एक माना है। इम्मानुएल वालरस्टीन के अनुसार (1990) संस्कृति यह वर्णन करने का एक साधन प्रदान करती है कि समूह अन्य समूहों से कैसे अलग हैं। समूहों के बीच अंतर का वर्णन करने के अलावा, संस्कृति व्यक्तियों को उनके आसपास की दुनिया को समझने और व्याख्या करने के लिए एक साधन प्रदान करती है। इस संबंध में, संस्कृति जीवन के एक सामूहिक मोड का प्रतिनिधित्व करती है, मान्यताओं, शैलियों, मूल्यों और प्रतीकों की एक प्रतिरूप (एंडरसन 1991, 171)। वैश्वीकरण ने इन जटिलताओं को बहुत बड़े स्तर पर ला दिया है। कठिन और दर्दनाक विकल्पों के साथ सामना करने

पर अपने आप के चारों ओर दुनिया की भावना बनाना सरल और अभी तक जटिल हो गया है। क्लिफर्ड गीर्ट्ज (1973, 89) संस्कृति की बहुत उद्धृत परिभाषा लोकप्रिय और व्यावहारिक गतिविधियों में विश्वास–आधारित फोकस से परे जांच को व्यापक बनाती है। वह संस्कृति को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रतीकात्मक रूप में प्रतीकात्मक रूप से संचरित पैटर्न, जिसके माध्यम से पुरुषसंचार करते हैं, बिगड़ते हैं और जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं।

एक अन्य दृष्टिकोण से, माइकल ग्रीग (2002, 225) का तर्क है कि संस्कृति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है क्योंकि यह मानव अस्तित्व के लिए मौलिक आधार प्रदान करती है और मानव बातचीत के सभी स्तरों को आकार देने का कार्य करती है। सांस्कृतिक अंतर समूहों और व्यक्तियों की संवाद और सहयोग करने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक अंतर ने दुनिया के कुछ सबसे खूनी संघर्षों को आधार प्रदान किया है। फिर भी संचार में परिवर्तन संस्कृतियों में परिवर्तन करते हैं – विस्तार करना, बदलना, नष्ट करना और यहां तक कि उन्हें बनाना। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि जैसे–जैसे संचार का विस्तार होता है और सांस्कृतिक अंतर अधिक स्पष्ट होते जाते हैं, वैसे–वैसे सांस्कृतिक/सभ्यता संबंधी दरार (हंटिंगटन 1996) के साथ विवादों के बढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी गंभीर होता जाएगा। इसके अलावा, कुछ विद्वानों ने दावा किया कि पिछले कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी में प्रगति ने लोगों के बीच संस्कृति की अधिक एकजुटता लाई है और साथ ही लोग उनके बारे में अधिक जागरूक हैं और उनकी संस्कृति की विशिष्टता। इस प्रकार, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में संचार और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन दुनिया में संस्कृतियों के वितरण को कैसे प्रभावित करता है।

6.4 वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम

वैश्वीकरण और संस्कृति एक अच्छी तरह से स्थापित विषय है। यह पहली बार 1992 में रोनाल्ड रॉबर्टसन (1992), वैश्वीकरणः सामाजिक सिद्धांत और वैश्विक संस्कृति के काम में आया। वैश्वीकरण के क्षितिज को आगे बढ़ाने के साथ प्रौद्योगिकी और संचार के विकास के साथ, संस्कृति का इसके विभिन्न आयामों में निरंतर विश्लेषण किया जा रहा है। अप्पादुरई (1996) जैसे भारतीय विद्वानों ने मानव अंतःक्रिया के तीन स्तरों पर इसका विश्लेषण किया है – मनुष्य प्रकृति और जीवन से संबंधित है, वे प्रतीकों और अनुष्ठानों से संबंधित हैं, और अंतिम अर्थों के लिए उनकी खोज जो उन्हें लक्ष्य और प्रेरणा प्रदान करती है। पिछले दशकों में सांस्कृतिक अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितताओं के अन्वेषण नेटवर्क ने कुछ टिप्पणीकारों को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है कि सांस्कृतिक अभ्यास समकालीन वैश्वीकरण के बहुत केंद्र में हैं। फिर भी, सांस्कृतिक वैश्वीकरण रॉक 'एन' रोल, कोका–कोला या फुटबॉल के विश्वव्यापी प्रसार से शुरू नहीं हुआ। आधुनिक सभ्यता की तुलना में व्यापक सभ्यतागत आदान–प्रदान बहुत पुराना है। फिर भी, 21 वीं सदी में सांस्कृतिक प्रसारण की मात्रा और सीमा पहले के समय की तुलना में बहुत अधिक है। इंटरनेट और हमारे प्रोलिफेरेटिंग मोबाइल उपकरणों द्वारा सुस्पष्ट, हमारी उम्र के अर्थ की प्रमुख प्रतीकात्मक प्रणाली – जैसे कि व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद और विभिन्न धार्मिक प्रवचन – पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से और व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। चूंकि चित्र और विचार अधिक

आसानी से और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किए जा सकते हैं, वे लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन का अनुभव करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आज, सांस्कृतिक प्रथाओं ने शहर और राष्ट्र जैसे निश्चित इलाकों की जेल से बच निकले हैं, अंततः प्रमुख वैश्विक विषयों के साथ बातचीत में नए अर्थ प्राप्त कर रहे हैं। (स्टीगर 2017, 81) रॉबर्ट होल्टन (2000) ने तीन प्रमुख विषयों के तहत इस समस्वरता का विश्लेषण होमोजेनाइजेशन, ध्रुवीकरण और संकरण के रूप में किया। उन्होंने उल्लेख किया है कि वैश्वीकरण के तहत, वैश्विक संस्कृति पश्चिमी या अमेरिकी पैटर्न के आसपास मानकीकृत हो गई है। कुछ विद्वानों ने इसे मैकडॉनलाइजेशन कहा है। संचार क्रांति, इसकी कठोरता और आउटरीच ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया को एक वैश्विक बाजार बना दिया है। जेट विमान, सस्ती टेलीफोन सेवा, खाद्य श्रृंखला, ईमेल, कंप्यूटर, विशाल समुद्री जहाज, तत्काल पूंजी प्रवाह, इन सभी ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक निर्भर बना दिया है। हालांकि, दुनिया में अंतर–जातीय, अंतर–सांस्कृतिक और अंतर–धार्मिक संघर्ष भी हैं, और वैश्वीकरण के साथ वे केवल अधिक स्पष्ट हो गए हैं। लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों की खोज कर रहे हैं और एकल को चुनौती दे रहे हैं और सांस्कृतिक मानदंडों को समरूप बनाना चाहते हैं। इस अर्थ में ध्रुवीकरण, सांस्कृतिक विकल्पों और पश्चिमी मानदंडों के प्रतिरोध की उपस्थिति के साथ वैश्विक सांस्कृतिक विकास की एक अधिक ठोस तस्वीर प्रदान करता है। संकरण में, संस्कृतियां एक दूसरे से तत्वों को उधार लेती हैं और शामिल करती हैं, जो संकर और समकालिक रूपों का निर्माण करती हैं। कुछ इसे ग्लोकल या ग्लोकलाइजेशन के रूप में संबोधित करते हैं। सबाल्टर्न समूह और स्वदेशी लोग नए वैश्विक युग में अपने स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की पुष्टि और बचाव कर रहे हैं। (वांग 2007, 83)।

एक संस्कृति के बाहरी प्रभाव के प्रति अतिसंवेदनशील (कमजोर) होने के लिए, क्रॉस–सांस्कृतिक संचार की क्षमता मौजूद होनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, यह क्षमता तेजी से सीमित रही है। संभावित प्रभावों की सीमा को सीमित करते हुए यात्रा और संचार मुश्किल, महंगा और कभी–कभी खतरनाक था। आज, हालांकि, संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति, एक विस्तारित वैश्विक आर्थिक प्रणाली के साथ मिलकर, भौगोलिक रूप से अलग समूहों के बीच बातचीत के अवसरों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूरसंचार, इंटरनेट और टेलीविजन सभी लोगों को भौगोलिक सीमाओं को पार करने और अन्य संस्कृतियों के साथ बातचीत करने के लिए साधन प्रदान करते हैं। जैसा कि वैश्वीकरण का विस्तार होता है और दूरस्थ और स्थानीय संचार दोनों तात्कालिक हो जाते हैं, दूरी और भौतिक भूगोल की प्रासंगिकता बलों के रूप में होती है जो आकार संस्कृति में गिरावट आएगी (ग्रीग 2002, 228–9)। हालाँकि, यी वैंग (2007, 84) का तर्क है कि कभी–कभी वैश्वीकरण के विरोधी लोगों की अधीनता की शक्ति की अनदेखी करते हैं। क्योंकि लोग केवल सांस्कृतिक प्रभावों की वस्तु नहीं हैं, बल्कि ऐसे विषय हैं जो विभिन्न प्रभावों को स्थानांतरित कर सकते हैं और उन्हें अस्वीकार या एकीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोक और मैकडॉनल्ड्स यूएसए में बहुत लोकप्रिय हो सकते हैंय लेकिन भारत में, कुछ अमीर उन्हें खरीद सकते हैं और वे स्थिति के प्रतीक बन जाते हैं और चीन में, पारंपरिक चीनी रेस्तरां अभी भी प्रमुख हैं। वास्तव में, चीन और भारत दोनों में, यहां तक कि मैक डोनाल्ड को भी स्थानीय स्वादों को पूरा करना था और अपने मेनू और मसालों को संशोधित करना था।

सभी कारकों पर विचार करके, हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण द्वारा लाया गया समरूपीकरण सतही है और लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता वस्तुओं के भौतिक स्तर और एक निश्चित उपभोक्ता संस्कृति तक सीमित है जो मीडिया द्वारा कृत्रिम रूप से प्रचारित किया जाता है। यह प्रभावित नहीं करता है कि लोग एक–दूसरे से कैसे संबंधित हैं और वे जीवन में अर्थ और उद्देश्य कैसे पाते हैं। यह काफी हद तक व्यक्तिगत और समूह के रूप में, संस्कृति को बनाने और बदलने वाली संस्कृति में विषयों की स्वतंत्रता और अछूता नहीं है। (फ्रीडमैन, 1994)। क्योंकि यह अंततः हम तय करने वाले हैं कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। संस्कृति के समरूपीकरण के मामले में, लोग भोजन, फैशन, संगीत आदि में इसके प्रभाव को अधिक देखने के लिए सहमत हुए। इसके बजाय होमोजिनाइजेशन, ध्रुवीकरण और विषमजनन के बजाय लोग संकरण के साथ अधिक सहज हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1) वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

6.5 वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम

अधिकांश वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के मुख्य सूत्रधार और प्रेरक बल के रूप में तकनीकी विकास की कल्पना की जाती है। प्रौद्योगिकी को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के सामाजिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम आगे इस परिभाषा का वर्णन पांच महत्वपूर्ण तत्वों के साथ कर सकते हैंः उत्पादन (प्रौद्योगिकी का), ज्ञान (प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का), (प्रौद्योगिकी की बाजार उपलब्धता) उपकरण, (उपकरणों की) क्षमता और (अनुभव) परिवर्तन। सूचना और प्रौद्योगिकी का मतलब न केवल दूरी के अत्याचार का विस्मरण (विनाश) है, बल्कि एक वैश्विक आभासी वास्तविकता का निर्माण भी है, जिसमें समय सामाजिक विनिमय के लिए कोई मौलिक बाधा प्रस्तुत नहीं करता है। (होटन 2000, 141)। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने वैश्विक नेटवर्क की ओर रास्ता खोल दिया है। वैश्विक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी जानकारी और ज्ञान – विचारधारा भी – प्राप्ति, रखरखाव और प्रणाली के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है – मूल रूप से पूंजीवादी प्रणाली – वास्तविकता के रूप में पनपती है। शब्द 'नई अर्थव्यवस्था' यह स्पष्ट विवरण है कि ये सभी जानकारी, ज्ञान और विचारधारा पूंजीवाद के घनिष्ठ संबंध में कैसे हैं। इंटरनेट और विशेष रूप से ई–कॉमर्स ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से तकनीकी–वैश्विकता के हालिया दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तकनीकी–वैश्वीकरण को वैचारिकता

के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है जो तकनीकी आधार पर वैश्विकता को तर्कसंगत बनाता है। यह पूरी प्रक्रिया 1990 के दशक के बाद हुई विश्वव्यापी अंतरनिर्भरता और वैश्विक आदान–प्रदान के नाटकीय निर्माण, विस्तार और त्वरण को प्रस्तुत करती है। इस नवीनतम वैश्वीकरण की लहर को चिह्नित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इसे 'महान अभिसरण' कहा जाए – अलग–अलग और व्यापक रूप से फैले हुए लोग और सामाजिक संबंध पहले से कहीं अधिक तेजी से एक साथ आ रहे हैं। वास्तव में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के आईसीटी क्रांति के साथ संयोजन ने वैश्वीकरण को एक नए गियर में डाल दिया। इंटरैक्टिव संचार के क्षैतिज नेटवर्क का अभूतपूर्व विकास जो स्थानीय और वैश्विक से जुड़ा था, इंटरनेट, वायरलेस संचार, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग टूल के विश्वव्यापी प्रसार के माध्यम से संभव हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से परिष्कृत सोशल नेटवर्किंग दुनिया भर में दो मिलियन से अधिक लोगों के लिए एक नियमित गतिविधि बन गई है। (स्टीगर, 2017)।

जैसा कि स्पैनिश समाजशास्त्री मैनुअल कैस्टेल्स ने बताया है, एक वैश्विक नेटवर्क समाज के निर्माण को संचार शक्ति द्वारा ईंधन दिया गया है, जिसे नई जानकारी और संचार प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास द्वारा मुख्य रूप से तकनीकी क्रांति की आवश्यकता थी। ब्रेकनेक गति से आगे बढ़ते हुए, ये नवाचार मानव जीवन के सामाजिक परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। टेक्नो–ग्लोबलिस्ट, उनमें से अधिकांश एंग्लो–सैक्सन देशों में रहते हैं, दावा करते हैं कि प्रौद्योगिकी वैश्विकता को अप्रतिरोध्य बनाती है। इसलिए, आर्थिक या प्रौद्योगिकी प्रवाह के लिए दुनिया भर में बाधाओं को दूर करने के इच्छुक तकनीकी–वैश्विकवादियों ने तकनीकी रूप से बेहतर बुनियादी ढांचे पर एक ''उदार'' वैश्विक आर्थिक प्रणाली का सुझाव दिया।

हालांकि, यह मान लेना गलत होगा कि यह सब पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ती तकनीक के कारण है। वैश्वीकरण एक गतिशील और विविध प्रक्रिया रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि यह पूर्व ऐतिहासिक काल से शुरू होता है। सामाजिक संबंधों का स्थानिक विस्तार और वैश्विक कल्पना का उदय धीरे–धीरे गहरी ऐतिहासिक जड़ों के साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। जिन इंजीनियरों ने व्यक्तिगत कंप्यूटर और सुपरसोनिक जेट विमानों का विकास किया, वे पहले के इनोवेटरों के कंधों पर खड़े थे, जिन्होंने स्टीम इंजन, कॉटन जिन, टेलीग्राफ, फोनोग्राफ, टेलीफोन, टाइपराइटर, आंतरिक–दहन इंजन और बिजली के उपकरणों का निर्माण किया। इन उत्पादों, बदले में, दूरबीन, कम्पास, पानी के पहिये, पवन चक्कियों, बारूद, प्रिंटिंग प्रेस और समुद्र के जहाजों जैसे बहुत पहले के तकनीकी आविष्कारों के लिए अपने अस्तित्व का त्याग करते हैं। और ये आविष्कार दुनिया के सभी क्षेत्रों में मनुष्यों की सामूहिक उपलब्धि थी, न कि केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त भौगोलिक केंद्र में, जो कि पश्चिम है। फिर भी, यह अस्वीकार करना मूर्खतापूर्ण होगा कि इन नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने विश्व–समय और विश्व–अंतरिक्ष के संपीड़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, इंटरनेट ने वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण के माध्यम से वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है जो अरबों व्यक्तियों, नागरिक समाज संघों और सरकारों को जोड़ता है। चूंकि इनमें से अधिकांश प्रौद्योगिकियां लगभग तीन दशकों से कम समय के लिए रही हैं, इसलिए यह उन टीकाकारों से सहमत होने के लिए समझ में आता है जो दावा करते हैं कि वैश्वीकरण वास्तव में एक अपेक्षाकृत नई घटना है। (स्टीगर 2017, 18)।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1) वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

6.6 वैश्वीकरण के साथ प्रौद्योगिकी के विकास का संस्कृति पर प्रभाव

जब भी हम पर वैश्वीकरण के प्रभाव को देखते हैं, विशेष रूप से हमारी संस्कृति, एक प्रश्न जो हमें हड़ताल कर सकता है, वह यह है कि क्या वैश्वीकरण को 'अच्छी' या 'बुरी' बात माना जाना चाहिए, क्या वैश्वीकरण दुनिया भर के लोगों को अधिक समान या अधिक भिन्न बनाता है। व्यापार के उदारीकरण से उत्पन्न होने वाले कथित लाभों के लिए बाजार के वैश्विक लोग अक्सर अपने तर्कों को जोड़ते हैं– बढ़ते वैश्विक जीवन स्तर, आर्थिक दक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति। लेकिन जब बाजार की गतिशीलता सामाजिक और राजनीतिक परिणामों पर हावी हो जाती है, तो भूमंडलीकरण के अवसर और पुरस्कार बहुतायत की कीमत पर लोगों, क्षेत्रों और निगमों के चुनिंदा समूह के बीच शक्ति और धन को केंद्रित करते हुए अक्सर असमान रूप से फैल जाते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना तक पहुंच के लिए भी यही बाजार तर्क लागू होता है। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय, हम दो समूहों में चर्चा कर सकते हैं–निराशावादी और आशावादी।

निराशावादी विश्ववादी तर्क देते हैं और सुझाव देते हैं कि हम एक सांस्कृतिक इंद्रधनुष की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जो दुनिया की मौजूदा आबादी की विविधता को दर्शाता है। इसके बजाय, हम न्यूयॉर्क, हॉलीवुड, लंदन, पेरिस और मिलान में स्थित एक पश्चिमी संस्कृति उद्योग द्वारा लिखित एक तेजी से समरूपता वाली लोकप्रिय संस्कृति के उदय के साक्षी बन रहे हैं। एंग्लो–अमेरिकन मूल्यों और उपभोक्ता वस्तुओं के अमेरिकीकरण के रूप में विश्व के प्रसार का उल्लेख करते हुए, इस सांस्कृतिक समरूपीकरण थीसिस के समर्थकों का तर्क है कि पश्चिमी मानदंड और जीवन शैली अधिक कमजोर संस्कृतियों को भारी कर रहे हैं। यद्यपि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की इन ताकतों का विरोध करने के लिए कुछ देशों द्वारा गंभीर प्रयास किए गए हैं – उदाहरण के लिए, ईरान में उपग्रह व्यंजनों पर प्रतिबंध, और आयातित फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों पर टैरिफ और कोटा लागू करना – अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति का प्रसार लगता है अजेय। (स्टीगर 2017, 82)। निराशावादी वैश्वीकरण के इस समूह में एक विशेष विचारशील विश्लेषक अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार बेंजामिन बार्बर हैं। उनके अनुसार, बाजारों का विस्तार करने और लाभ कमाने के लिए, वैश्विक पूंजीवादी दुनिया

भर में युवा और धनवानों को लक्षित करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं में बच्चों को बदलकर सजातीय वैश्विक उत्पाद विकसित कर रहे हैं। इस प्रकार, वैश्विक उपभोक्तावाद लाभ की खोज में तेजी से अनैतिक और अनैतिक हो जाता है।

हालांकि, इसे मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण की सभी सफलताओं के लिए, यह कई विकासशील देशों (साथ ही रूस के लिए) के अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। तथ्य के रूप में, एक ही समय के दौरान कि कुल विश्व आय में औसतन 2. 5 प्रतिशत सालाना की वृद्धि हुई, गरीबी में रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या में लगभग 100 मिलियन की वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण, जिसने कई लोगों के लिए धन बनाने और रहने की स्थिति में सुधार करने में मदद की है, साथ ही साथ हैव्स और हवस के बीच बढ़ते विभाजन के लिए संदर्भ है। वैश्वीकरण के तहत, लोगों की बढ़ती संख्या को घोर गरीबी में छोड़ दिया गया है, जो प्रति दिन एक डॉलर से भी कम पर जी रहे हैं। (वैश्वीकरणः यह क्या है?)। आशावादी विश्ववादी अपने निराशावादी सहयोगियों से सहमत हैं कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण अधिक सामर्थ्य उत्पन्न करता है, लेकिन वे इस परिणाम को एक अच्छी बात मानते हैं। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्री रोनाल्ड रॉबर्टसन कहते हैं कि वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह अक्सर स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओंको मजबूत करते हैं। समता के पश्चिमी उपभोक्तावादी ताकतों से पूरी तरह से वंचित होने के बजाय, स्थानीय अंतर और विशिष्टता अभी भी अद्वितीय सांस्कृतिक नक्षत्रों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तर्क देते हुए कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण हमेशा स्थानीय संदर्भों में होता है, रॉबर्टसन सांस्कृतिक समरूपता थीसिस को खारिज कर देता है और ग्लोकलाइजेशन के बजाय बोलता है – जटिल वैश्वीकरण गतिशील जिसमें वैश्विक और स्थानीय की बातचीत शामिल है। सांस्कृतिक संकरता के परिणामस्वरूप अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट रूप से समान या अलग नहीं किया जा सकता है। संकरण की प्रक्रियाएं फैशन, नृत्य, फिल्म, भोजन, खेल और भाषा में अधिक दिखाई देती हैं। (स्टीगर 2017, 86)।

आशावादी विश्ववादियों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण ने नई प्रौद्योगिकियों के विस्फोट, वस्तुओं और सेवाओं का प्रचुर उत्पादन और लाखों लोगों के लिए धन के बढ़ते स्तर का उत्पादन करने में मदद की है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रणालियों के तहत रह रहे हैं, अधिक समाज मानवाधिकारों के महत्व को पहचान रहे हैं, और विश्व इतिहास में इससे पहले कभी भी इतने लोगों को शिक्षा और ज्ञान के लिए इतने अवसर नहीं थे। इसके अलावा, वैश्वीकरण के कारण, कई विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात–नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि के कारण, पूर्वी एशिया के लाखों लोग अब कुछ वर्षों पहले की तुलना में अब बहुत बेहतर हैं (और 'बेहतर' होना एक बड़े जीएनपीका कार्य नहीं है) , लेकिन इसमें लंबे समय तक रहने वाले और स्वस्थ रहने वाले नागरिक भी शामिल हैं)।

लेकिन वैश्वीकरण और संशयवादियों के संबंधित तर्क असंगत नहीं हैं। सांस्कृतिक सीमाओं के पार रहने और अभिनय करने के समकालीन अनुभव का अर्थ है पारंपरिक अर्थों की हानि और नए प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों का निर्माण। तन्मयता की भावना के साथ असहज तनाव में सह–अस्तित्व की पुनर्निर्मित भावनाएं। वास्तव में, कुछ टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि आधुनिकता धीरे–धीरे पहचान, स्थान और ज्ञान की कम स्थिर भावना की विशेषता एक नए उत्तर–आधुनिक ढांचे को आकार दे रही है।

मैनफ्रेड बी. स्टेगर के अनुसार, वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह की जटिलता को देखते हुए, वास्तव में असमान और विरोधाभासी प्रभाव देखने की उम्मीद होगी। कुछ संदर्भों में, ये प्रवाह राष्ट्रीयता की पारंपरिक अभिव्यक्तियों को एक लोकप्रिय संस्कृति की दिशा में बदल सकते हैं, जिसमें समानता की विशेषता हैय दूसरों में वे सांस्कृतिक विशिष्टता के नए भावों को बढ़ावा दे सकते हैंय अभी भी दूसरों में वे सांस्कृतिक संकरता के रूपों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे टिप्पणीकार जो संक्षेप में अमेरिकीकरण के समरूप प्रभाव की निंदा करते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज दुनिया का शायद ही कोई समाज प्रामाणिक, स्व–निहित संस्कृति रखता हो। जो लोग सांस्कृतिक संकरता के उत्कर्ष पर निराशा करते हैं, उन्हें रोमांचक बॉलीवुड पॉप गाने सुनने के लिए, हवाई पिजिन के कई रूपों की गहनता की प्रशंसा करनी चाहिए, या क्यूबा–चीनी व्यंजनों का आनंद लेना चाहिए। अंत में, उपभोक्तावादी पूंजीवाद के प्रसार की सराहना करने वालों को इसके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि पारंपरिक सांप्रदायिक भावनाओं की नाटकीय गिरावट के साथ–साथ समाज और प्रकृति का नाटकीय ढंग से संशोधन। (स्टीगर 2017, 87)

माइकल ग्रेग (2002) ने आगे उल्लेख किया कि, हालांकि वैश्वीकरण से लोगों में सांस्कृतिक समानता अधिक हो सकती है, यह समानता सांस्कृतिक मूल्यों के एक सेट को दूसरे पर थोपने के माध्यम से विकसित नहीं होती है। इसके बजाय, सांस्कृतिक समानता सांस्कृतिक मूल्यों की विविधता के मिश्रण के माध्यम से विकसित होती है, पिएर्सियस (1995 और 2015) के करीब पहुंचती है, सांस्कृतिक आधिपत्य की तुलना में ''सांस्कृतिक मेलजोल''। वास्तव में, हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में आज सांस्कृतिक मूल्यों का मिश्रण कैसे होता है क्योंकि संचार का विस्तार लोगों को नए सांस्कृतिक रूपों के संपर्क में आने का अवसर देता है। संस्कृति गतिशील है, स्थिर नहीं है। सांस्कृतिक परिवर्तन पर संचार के विस्तार के प्रभाव को समरूपता और विषमता के बीच एक साधारण अंतर तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, संचार का विस्तार सांस्कृतिक सहभागिता के नए अवसर प्रदान करता है जबकि दूसरों को भी सीमित करता है। सांस्कृतिक मूल्यों के परिवर्तन और परिवर्तन के रूप में, नए अवसरों और चुनौतियों की संभावना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में विकसित होगी (ग्रीग 2002, 242)। आज की सांस्कृतिक दोष रेखाएँ समानता के व्यापक क्षेत्रों में विकसित हो सकती हैं, जिससे संचार और सहयोग कम कठिन हो जाता है। इसके विपरीत, नई सांस्कृतिक दोष रेखाएं भी विकसित होने की संभावना है, लोगों को नए और अप्रत्याशित तरीकों से विभाजित करना और संघर्षों और विवादों के नए स्रोत प्रदान करना।

माइकल ग्रेग (2002) आगे तर्क देता है कि, वैश्वीकरण से सिस्टम में सांस्कृतिक समरूपता के स्तर में वृद्धि होती है और उस दर पर हाइब्रिड संस्कृतियों का विकास होता है। फिर भी, संचार का विस्तार उस डिग्री को भी कम कर देता है, जो सांस्कृतिक लक्षणों से पहले बातचीत के लिए सबसे प्रमुख थे। इस संबंध में, ये परिणाम बताते हैं कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक मूल्यों के एक विशेष समूह के आरोपण के बजाय एक सजातीय संकर संस्कृति के विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, परिस्थितियों के सही सेट के तहत, संचार का विस्तार सांस्कृतिक प्रवासी के विकास और रखरखाव को प्रोत्साहित करके स्थानीय सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

हालाँकि, वैश्वीकरण के नए युग में, लोग अपनी संस्कृति की विशिष्टता और विशिष्टता के बारे में अधिक चिंतित हैं। सांस्कृतिक पहचान स्थानीय ज्ञान और स्वयं, समुदाय और राष्ट्र की भावना को वैश्विक महत्व प्रदान करती है। देंग (2005) बताते हैं कि सांस्कृतिक पहचान ''मैं कौन हूं?'' के सवालों का जवाब देता है, ''हम कहां जा रहे हैं?'' और ''हमारे पास क्या है?'' चूंकि लोग अपनी संस्कृतियों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं, इसलिए वे उनका बचाव करेंगे। दरअसल, वैश्वीकरण पहले की तुलना में सांस्कृतिक पहचान के बारे में अधिक जागरूकता लाता है। गहरे अर्थों में, वैश्वीकरण सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है और लोग अपनी संस्कृति की विशिष्टता या विशिष्टता के बारे में अधिक चिंतित हो जाते हैं। यदि हम इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो वैश्वीकरण से हेग्मोनिक नियंत्रण हो सकता है। लेकिन सकारात्मक रूप से देखा जाए, तो वैश्वीकरण से ''एकजुटता'' की भावना पैदा हो सकती है। ग्रह हमारी लाइफबोट है और हम सभी एक साथ इस नाव में हैं। वैश्वीकरण भी ''गहराई से जड़–में–एक–संस्कृति'' और स्थानीय ज्ञान के वैश्विक महत्व की भावना को जन्म दे सकता है। ये दो आयाम एक बहुत ही उपयोगी बातचीत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए, विविधता के साथ संघर्ष में एकजुटता बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया अधिक विविध और भी अधिक ''एक साथ'' हो जाती है।

जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वैश्वीकरण को देखते हैं, तो हम बेहतर नोटिस करते हैं कि लोग वैश्वीकरण के प्रभाव को निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके पास संस्कृति को बदलने और बनाने के लिए महान विषय और स्वतंत्रता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, लोग पहले की तुलना में करीब हैं। वे अपनी सांस्कृतिक पहचान के बारे में अधिक चिंतित हो जाते हैं। वे लगातार अपनी सांस्कृतिक जड़ों की खोज कर रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं। यदि हम इस नए युग में लोगों की विविधता और उनकी संस्कृतियों का सम्मान कर सकते हैं, तो यह बहुवाद में एकता द्वारा चिह्नित वैश्विक समुदाय को जन्म दे सकता है। संस्कृतियां अब पारंपरिक अर्थों में स्थानीय नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अलग और बहुवचन हैं। इससे एक नए प्रकार का वैश्वीकरण होगा जो समरूपता नहीं होगी।

9/11 के बाद के दो दशकों में, वैश्वीकरण के अर्थ और दिशा पर वैचारिक संघर्ष ने विघटन के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। शायद 21 वीं सदी में मानवता के सामने आने वाले तीन सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य वैश्विक असमानता में कमी, हमारे चमत्कारिक ग्रह के संरक्षण और मानव सुरक्षा को मजबूत करना है। अन्य सफलता की कहानियां जैसे कि दुनिया भर में पूर्ण गरीबी में कमी और बाहरी अंतरिक्ष के संयुक्त अन्वेषण के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के गठन का सुझाव है कि हमारी वैश्विक समस्याओं का समाधान कम नहीं है, लेकिन (और बेहतर) वैश्वीकरण (स्टीगर 2017, 133–34)। बिना किसी सवाल के, आगे के वर्ष और दशक नए वैश्विक संकट और आगे की चुनौतियां लाएंगे। मानवता अभी तक एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है – हमारी प्रजातियों के अपेक्षाकृत कम अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण। जब तक हम वैश्विक समस्याओं को उस बिंदु तक तेजी से जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, जहां हिंसा और असहिष्णुता हमारे असमान रूप से एकीकृत दुनिया का सामना करने के एकमात्र यथार्थवादी तरीकों से प्रकट होती है, हमें भूमंडलीकरण के भविष्य के पाठ्यक्रम को एक गहन सुधारवादी एजेंडे से जोड़ना होगा। इन परिवर्तनकारी सामाजिक प्रक्रियाओं को महानगरीयता के नैतिक नीति–निर्देशक द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिएः वास्तव

में एक लोकतांत्रिक और समतावादी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण जो मानव विकास की जीवनदायी सांस्कृतिक विविधता को नष्ट किए बिना सार्वभौमिक मानव अधिकारों की रक्षा करता है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1) संस्कृति पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

6.7 सारांश

इस क्षेत्र में जाने माने विद्वानों/विशेषज्ञों की विभिन्न अवधारणाओं और विचारों का विश्लेषण करने के बाद, हम यह संक्षेप कर सकते हैं कि वैश्वीकरण मानव के रूप में ऐतिहासिक है और प्रौद्योगिकी की पीठ पर प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है। पिछले तीन दशकों में इस मार्च को सबसे बड़ा बढ़ावा देने का तर्क दिया जा सकता है। यह भी दावा किया जा सकता है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों को विभिन्न विद्वानों और विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण के तीन शोधों के विशेष संदर्भ के साथ देखा जा सकता है – समरूपता, विषमता/ध्रुवीकरण और संकरण के रूप में। क्योंकि वैश्वीकरण बहुआयामी, गतिशील, विविध और जटिल प्रक्रिया है और इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरण, मानव समृद्धि और कल्याण जैसे विभिन्न अन्य कारक/तत्व/बल शामिल हैं, ये तीन प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं।

6.8 संदर्भ ग्रंथ

''इफैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीकल डेवलपमेंट ऑन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस'', *http://mediaif.emu.edu.tr/pages/atabek/GCS7.html*

''ग्लोबलाइजेशन : व्हाट इज इट?'', *http://stevekerby.com/omde_626/globalisation.htm*

ऐण्डर्सन, बेनेडिक्ट (1991), *इमैजिन्ड कम्यूनिटीज,* लन्दन : वर्सो।

अप्पादुराय, ए. (1996), *मॉडर्निटी ऐट लार्ज : कल्चरल डामेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन,* एम.एन. यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा प्रेस।

ब्लैकमोरे, जे. (2000), ग्लोबलाइजेशन, ए यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर फेमिनिस्ट रिथिंकिंग थियरी एण्ड स्ट्रटजीज इन ऐडुकेशन, इन *ग्लोबलाइजेशन एण्ड ऐडुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्ज* (ऐटिर्स) एन. सी., बुर्बुलेज एण्ड सी.ए. टेर्रेस, लन्दन : रूटलेज।

कार्नोय, एम., (1999), *ग्लोबलाइजेशन एण्ड ऐडुकेशनल रिफोर्मस : व्हाट प्लेयर्स ट्राइड टू नो,* पेरिस : यूनेस्को।

कार्नोय, मार्टिन (1999), *सस्टेनेबल फ्लेक्सिबिलिटी : वर्क फैमिली एण्ड कम्यूनिटी इन दि इंफोर्मेशन ऐज,* न्यू यॉर्क : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

कास्टेल्स, मैनुएल (1996), *दि इंफोर्मेशन ऐज : इकोनॉमी, सोसाइटी एण्ड कल्चर, वॉल्यूम–1 दि राइज ऑफ दि नेटवर्क सोसाइटी,* ऑक्सफोर्ड : ब्लैकवेल।

डैंग, एन. (2005), ऑन दि नेशनल लिटरेचर'ज टैक्टिस इन दि ग्लोबलाइजेशन'ज लैंगुएज इन्वायरन्मेंट, *जर्नल ऑफ ह्यूमन इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमनिटीज, साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी,* 1, 39–41

फ्राइडमैन, जे. (1994), *कल्चर आइडेंटिटी एण्ड ग्लोबल प्रोसेस,* यू.के. : सेज।

ग्रीट्ज, क्लिफोर्ड (1973), रिलिजन ऐज ए कल्चरल सिस्टम, *दि इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर'ज,* न्यू यॉर्क : बेसिक बुक्स।

ग्रीग, जे. माइकेल (2002), दि ऐण्ड ऑफ जियोग्राफी? : ग्लोबलाइजेशन, कम्यूनिकेशंस एण्ड कल्चर इन दि इंटरनेशनल सिस्टम, *दि जर्नल ऑफ कॉन्फिलक्ट रिजोल्यूशन,* वॉल्यूम–46, नं.2, अप्रैल, 225–243

हॉल्टोन, रॉबर्ट (2000), ग्लोबलाइजेशन'ज कल्चरल कंसीक्वेंसेज, *अमेरिकन एकेडेमी ऑफ पॉलिटिकल एण्ड सोशल साइंस,* वॉल्यूम–570, जुलाई, 140–152

हंटिंग्टन, सैमुएल (1996), *क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन,* न्यू यॉर्क : सिमोन एण्ड शस्टर।

पीटर्से, जैन (1995), ग्लोबलाइजेशन ऐज हाइब्रिडाइजेशन, इन *ग्लोबल मॉडर्निटीज,* (ऐटिड) माइक फीदर्स्टोन, एस. लैश, रॉनाल्ड रॉबर्टसन, लंदन : सेज पब्लिकेशंस।

पीटर्से, जैन नैडरवीन (2015), *ग्लोबलाइजेशन एण्ड कल्चरत : ग्लोबल मेलैंज,* लैनहैम, बॉल्डर, न्यू यॉर्क, लन्दन : रॉमैन एण्ड लिटलफील्ड।

रॉबर्टसन, रोनाल्ड (1992), ग्लोबलाइजेशन : सोशल थियरी एण्ड ग्लोबल कल्चर, लन्दन, थाउजैण्ड ऑक्स, न्यू डेल्ही : सेज पब्लिकेशंस।

स्टीजेर, मैनफ्रेड बी., (2017), *ग्लोबलाइजेशन : ए वैरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,* यूके : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

वालर्स्टीन, इम्मेनुएल (1990), कल्चर ऐज दि आइडियोलॉजिकल बैटलग्राउण्ड ऑफ दि मॉर्डन वर्ल्ड सिस्टम, *थियरी, कल्चर एण्ड सोसाइटी,* 7 : 257–81

वांग, यी (2007), ग्लोबलाइजेशन इन्हांसेज कल्चरल आइडेंटिटी, *इंटरकल्चरल कम्यूनिकेशन स्टडीज,* XVI, 83-86

विलियम्स, रेमण्ड (1976), *सीवर्ड्स,* लंदन : फ्लैमिंगो।

6.9 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

- आपके उत्तर में वैश्वीकरण की विभिन्न परिभाषाएं और तीनों चरण शामिल होने चाहिए।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

- अंतरसंपर्क, समरूपता, ध्रुवीकरण और संकरण पर प्रकाश डालें।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

- आपके उत्तर में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकियों का वर्णन होना चाहिए जो वैश्वीकरण में एक गतिशील और विविध प्रक्रिया प्रदान करता है जो अतीत से बहुत अलग है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

- संस्कृति पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों पर प्रकाश डालें

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY